LOK SABHA DEBATES

Seventh Session (Third Lok Sabha)



LOK SABHA SECRETARIAT New Delhi

CONTENTS

No. 59-Monday, April 27, 1964/Vaisakha 7, 1886 (Saka)

•					, ,			COLUMNS		
Oral Answers to Questions-										
*Starred Questions Nos. 1199	5 to 1	200 aı	nd 120	2 to 1	204			12891—929		
Written Answers to Questions-										
Starred Questions Nos. 1192	to 11	94, 12	oi an	d 120	5 to	1210		12929-36		
Unstarred Questions Nos. 250	00 to	2530						12936—58		
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—										
Firing by Naga hostiles on K								12958—66		
Papers laid on the Table								12967		
Estimates Committee—								,-,		
Minutes of Sub-committee								12967		
Message from Rajya Sabha .		•			•		•			
	•\ D:I						•	12967—68		
Drugs and Cosmetics (Amendment Laid on the Table as passed			Sabba					12069		
	-	Kajya	Sabha	١.				12968		
Appropriation (No. 3) Bill—Passe	d	•	•				•	12968— 6 9		
Constitution (Seventeenth Amendment) Bill-										
Motion to consider as reporte		Joint	Comn	nittee		•	12	2969—13086		
Shri Kashi Ram Gupta	a`				•		•	12970-75		
Shri Daji								- 1 - 1		
Shri Oza								1298 5— 8 8		
Shri Gajraj Singh Rao								12988—92		
Shri Bade .								992—13002		
Shri D. C. Sharma								13002-07		
Shri P. G. Menon								13007—12		
Shri Kishen Pattnayak								13012—17		
Shri Sinhasan Singh								13017—26		
Shri P. N. Kayal								13026—32		
Dr. L. M. Singhvi'								13032-42		
Shri D. S. Patil								13042-48		
Shri Bakar Ali Mirza								13049-52		
Shri Vasudevan Nair								13052-58		
Dr. Sarojini Mahishi								13058—64		
Shri M. L. Jadhav								1306467		
Shri Sheo Narain								13067—72		
Shri P. R. Chakraverti								13072-77		
Shri Basappa .								13077—80		
Shri Muthiah .								13080—85		
Shri A. K. Sen .								13085—86		

^{*}The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

⁴⁷² ai LSD-1.

12892

12891

LOK SABHA

Monday, April 27, 1964/Vaisakha 7, 1886 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr. Speaker in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: Shri Vishwa Nath Pandey. Shri Maheswar Naik. Shri Ram Harkh Yadav. Shri R. S. Pandey. Shri P. C. Borooah. Shri Yashpal Singh.

Shri Yashpal Singh: 1195.

Mr. Speaker: If the Member is not in his seat, I will not recognise his presence. He cannot speak from the passage.

Television

+
1195.
Shri Yashpal Singh:
Shri Maheswar Naik:

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

- (a) whether Government have received a proposal from a commercial firm for the installation of television in the country;
- (b) if so, the main features of the proposal; and
- (c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath): (a) to (c). Pro-

posals for the installation of television in the country have been received by the Government from a number of organisations from time to time. As the name of the firm has not been indicated in the question, it is not possible to furnish the main features of the proposal or indicate the reaction of Government thereto.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के मौजूदा हालात में जब कि चारों तरफ रुपए की कमी है, यह टेलीविजन का लगाना कहां तक उपयुक्त होगा, खास कर जब कि हम श्रपने देश को रोटी भी मयस्सर नहीं कर सकते ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : माननीय सदस्य को मालम होना चाहिए कि इस सदन में बहुत बड़ी तादाद ऐसे सदस्यों की है जो कि इस बात पर जोर देती रही है कि टेलीविजन होना चाहिए, ग्रौर बहत दिनों से यह मामला चला ग्रा रहा। हम ने पिछली बार जवाब दिया था कि इस में फारिन एक्सचेंज का सवाल है, इसीलिए तीसरी योजना में यद्यपि इस के लिए रूपया रखा गया या लेकिन इमरजेंसी के कारण इसको प्रायित्वी नहीं मिली और यह चीज बन्द हो गई। लेकिन म्रब कुछ प्रोपोजल म्राए हैं। पहले भी प्रोपोजल ग्राएथे, लेकिन फारिन एक्सचेंज की दिक्कत की वजह से हम ने उनको कबुल नहीं किया। श्रभी एक प्रोपोजल श्राया है, उसको आंच हो रही है। वे लोग जो यह प्रोपोजल लाए ये वे फाइनेंस मिनिस्टर हैं भी मिले ये और उन्होंने बताया है कि इसमें फारिन एक्सचेंज का मामला गर्म्भार नहीं है । इससे इस बारे में कुछ उम्मीद होता है कि

12893

शायद कोई रास्ता निकल आवे। वह कहते हैं कि हम उस लगा देंगे और हमको १४-१६ साल में धीरे त्रीरे पैसा दे दिया जाए. पांच साल के मोरेटोरियम के बाद। लेकिन ग्रभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि क्या निर्णय होगा ।

श्री यशराल सिंह : करोज वाग में पहाड़ी इलाका है। मैं जानना चाहता है कि क्या पहाड़ों को लांघ कर टेलोविजन को ले जाया जाएगा ?

श्री तःयनारायण सिंह: ग्रभी तो ग्राया हो नहीं है।

श्रव्यक्ष महोदय: पहले तो श्रापने कहा कि होना हो नहीं चाहिए ग्रौर ग्रब ग्राप कहते हैं कि पहाड़ा पर हो कर कैंत जाएगा।

Shri Kapur Singh: May I know whether Government have now conceded the principle of licensing nongovernmental broadcasting and television corporations?

Shri Satya Narayan Sinha: No. we have not yet.

श्री राम सेवक यादव : ग्रभो मंत्री महोदय ने बताया कि इमरजेंसी के कारण इत योजना पर विचार स्थिगित हो गया था. लेकिन भ्रब इस पर विचार हो रहा है। तो क्या यह समझा जार कि अब इमरजेंसो नहीं है ?

श्री सत्व नारायग सिंह : माननीय सदस्य की दिक्कत यह है कि जो हम लोग कहते हैं उसे वे ठीक तरह सुनते नहीं हैं। मैं ने कहा कि दिक्कत यह थो कि उस में फारिन एक्सचेंज का सवाल था। लेकिन इस प्रोपोजल में हम लोगों के लिए फारिन एक्सचेंग का सवाल कुछ स्रासान हो जाता है, इसलिए इस पर सोचा जा रहा है। यह बड़ा भारो फर्क हो गयान दोनों में।

Shri Liladhar Kotoki: The hon. Minister said there was a new proposal from a Scottish firm that is under consideration. May I know at what stage this proposal is, and by when this proposal is going to be finalised?

Shri Satya Narayan Sinha: It has just been received, it is being examined. We cannot say when it will be finalised. We are all anxious, and if the thing is to be brought into existence, it should be done as early as possible.

भी य० सिं० चौधरी : इस विचार के भ्रन्तर्गत देश के किन भागों में यह पहले लगाया जाएगा ?

श्वी सत्य नारायण सिंह : पहले कर से कम चार बडे शहरों में लगाया जाएगा।

श्री विश्राम प्रसाद: मैं यह जानना चाहता हं कि कितने टेलं विजन स्टेशन बनाए जायेंगे । भीर क्या साथ साथ टेलीविजन सेट बनाने के लिए भी देण के ग्रन्दर कोई कारखाना बनाने का विचार है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जब तक टेली-विजन सेट न होंगे तब तक टेलीविजन लगाने से क्या फायदा होगा। ये दोनों चीजें उसी स्कीम में शामिल हैं। भ्रभी सोच विचार हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि क्या फैसला होगा ।

श्री यज्ञवाल सिंह : इस पावरफुल गवनंमेंट के टांसमिटर इतने कमजोर हो गए हैं कि चीनी ट्रांसमिटरों का मकाबला नहीं कर सकते। क्या टेलीविजन लगाने से पहले उन टांसमिटरों को ज्यादा मजबत बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा ?

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether Government has taken a decision as a matter of policy to commercialise television, and if so, how soon it is proposed to take action.

Shri Satya Narayan Sinha: I have said Government has not decided this matter yet.

श्री विभति मिश्राः क्या सरकार का ध्यान इस ग्रोर गया है कि जो बैकवर्ड स्टेटस 🕏 बहां टेलीविजन लगा देने से बहां के बच्चों को ज्यादा शिक्षा फिल शकेगी ?

श्रष्यक्ष महोदय ः पहले श्राने तो दीजिए, फिर स्टेट का फैसना कर लेंगे।

श्री विमूर्ति मिश्रः ग्रभी यह टेलोविजन, फलकत्ता, बम्बई, मद्रास श्रीर दिल्ली इन भार बड़े शहरों में लग जाएगा। मैं चाहता हैं कि मंत्री जी इस का जवाब दें कि यह छोटे शहरों में लगाया जाएगा या नहीं।

श्री सत्य नारायण सिंह: माननीय सदरय को माल्म होना चाहिए कि ऐसे बहुत से पिछड़े हुए इलाके हैं जहां बिजली न होने से श्रमी रेडियो का हो इन्तिजाम नहीं है टेलीविजन की बाततो दूर रही। इसके अलावा पिछड़े इलाकों के लोग गरीव भी ज्यादा हैं। टेलीविजन सैट का टाम हम चाहे कितना भी कम करें तो भी अभी काफी होगा और बड़े शहरों को छोड़ कर छोटे इलाकों के लोग, जैस चम्पारन आदि के लाग, उनको खरीद भी नहीं सकेंगे।

Conference of the Commonwealth Countries

Ŧ

Shri Harish Chandra Mathur:

| Shri Bade: | Shri Hukam Chand | Kachhavaiya: | Shri Onkar Lal Berwa: | Shri P. R. Chakraverti: | Shri Hem Barua: | Shri Ram Sewak Yadav: | Shri Kishen Pattnayak:

Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether any conference of the Commonwealth countries is proposed to be held and India's convenience consulted; and
- (b) when and where the conference is to be held?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (b). As already stated by the Prime Minister in the House on the 22nd April, it is proposed to hold a meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London in July next. The Prime Minister has accepted the invitation.

Shri Harish Chandra Mathur: May know whether the Government accepts the well-informed political assessment that this Prime Ministers' Commonwealth Conference is held before the general elections for the Conservative Party to gain the loss ground in Western Europe and, if so, why is it that the India Government want, or what are the reasons which persuaded them, to strengthen the hands of the Conservative Party before accepting a Commonwealth conference at this time, and also accepting it to be held in London when even the Leader of the Opposition there wanted that it should be held in other Commonwealth countries?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlai Nehru): The Government of India could not and did not enter into domestic considerations applicable to the U.K. In the ordinary course the Commonwealth Prime Ministers' Conference was held, and is going to be held after nearly two years; and in the ordinary course again, it was decided to attend it.

Shri Harish Chandra Mathur: The second part of my question still remains. Even the Labour Leader said that the Commonwealth Prime Ministers' Conference should be held in different Commonwealth countries and not only in London. What is our reaction to it? Why do we not take up My first question was that idea? whether we examined the political implications of this Conference or not, and political implications arise out of Conservative Party taking the benefit. The second part was already there.

Shri Jawaharlal Nehru: I was not even aware that the Leader of the Opposition, of the Labour Party, suggested that the meeting might be held elsewhere. This question has come up repeatedly at the meetings of the Conference—about subsequent meetings being held elsewhere—and one might say that although some people were for it, the majority were against it, and so it has not been decided. To shift over suddenly will be difficult.

Shri Harish Chandra Mathur: When he goes for such conferences the Prime Minister usually visits many other countries. I think he has a pressing invitation from the United Arab Republic Government for a meeting with the President and rest there. May I know what is his programme this time and what countries he is visiting in this connection and how long does he propose to stay there?

Shri Jawaharlal Nehru: I am afraid the programme has not been made yet and so I cannot say. But it is possible that I might stay for a day in Cairo on my way to London or on my way back.

Shri Hem Barua: Is it a fact that the U.K. Prime Minister has consulted our Prime Minister about the invitation of Southern Rhodesia to this proposed Commonwealth Prime Ministers' Conference and, if so, what suggestions have our Government offered in this connection?

Shri Jawaharlal Nehru: I do not hink they have consulted us about it. do not remember seeing anything to that effect. But it is obvious that our reply, if we are consulted, will not be in favour of Southern Rhodesia being invited.

श्री रामसेवक यादव : कौमनवैत्य कंट्रीज के सम्मेलन में कौन कोन से महत्व-पूर्ण प्रश्नों पर विचार होगा और क्या कश्मीर का भी सवाल पाकिस्थान से जहां तक उस का सम्बन्ध है वहां पर उठाया जायेगा? श्री जवाहरलाल नेहर : कह नहीं सकता। एजेंडा उस का श्रभी नहीं श्राया है लेकिन कश्मीर जैसे सवाल वहां पेश नहीं होत हैं।

Shri Ranga: Has the agenda been settled? What are the important points there which are going to be discussed, and may I know whether India has any subject to her credit which is going to be discussed, or whether it is going to be just a gettogether?

Shri Jawaharlal Nehru: I have said that the agenda has not been prepared, or, not been received by us. But usually the subjects discussed are, apart from the Commonwealth itself, the changing pattern of the Commonwealth, the question of war and peace, disarmament—international problems like that—and a general review of the world situation. No particular problems affecting India are likely to come up.

Shri Ranga: What about Indians coming away from those countries and being sent away from there? Are they not going to discuss it—Indians in Burma, Ceylon and East Africa?

Shri Jawaharlal Nehru: I do not know. From East Africa some Indians have themseives decided to come away, have resigned, and it is a different situation in each country. It may be referred to there, perhaps.

Shri Hem Barua: Don't you have an agenda?

Mr. Speaker: Dr. Swell.

Shri Swell: Is it a fact that this Commonwealth Conference has become too unwieldy to be effective and is there any proposal that a small council of this Conference will be constituted and, if so, what will be the duties and functions of this council?

Shri Jawaharlal Nehru: It is true that it is getting rather unwieldy but I do not know of any proposal to constitute a small committee of it, and therefore, I cannot say what the duties of the committee will be.

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether India will take up the question of the attitude taken by the British representative in the Security Council with regard to Jammu and Kashmir and other related matters vis-a-vis India, at this Conference, with the other representatives of the Commonwealth who are present there?

Shri Jawaharlal Nehru: No, we do not take up questions as to what attitude a particular member of the Commonwealth has adopted in international law or national questions.

Shri P. R. Chakraverti: In the context of the not-too-helpful performance of the British representative in the Security Council on Kashmir Affairs and also in the context of the genocide in Pakistan in respect of the Hindu and Christian minorities there, may I know whether the Government have indicated these factors for inclusion in the agenda of the Conference?

Shri Jawaharlal Nehru: Government, first of all, has no chance of indicating anything because we have received no agenda yet and no request for our suggestions. Secondly, as I have just now said, we do not discuss such questions like the Kashmir issue; the hon. Member has referred to genocide; I do not see how that comes in, in the normal course there.

श्री गुलशन : यह जो राष्ट्रमंडलीय देशों का सम्मेलन होने वाला है उसमें क्या चीन और भारत के झगड़े के हल के रूप में जो कोलम्बों तजबीजें हुई थीं क्या उन पर पर भी वहां विचार करने वाले हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहर : इस सब बातों पर विचार कुछ होता है, कुछ योड़ी सी चर्चा होती है लेकिन वहां पर कोई फँसला नहीं होता है। श्री किशन पटनायक: क्या इस सम्मेलन का एजेंडा बनाने में हिन्दुस्तान की सरकार की भी राय ली जाती है, प्रगर ली जाती है तो सरकार की तरफ से उस में क्या सुझाव दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहव : जी हां, एक एजंडा भेजा जाता है वहां से ग्रांद पूछा जाता है कि उस में कुछ बढ़ाना है, घटाना है या ऐसे ही रहने देना है ग्रोर हमारी जो कुछ एय होती है हम उन्हें लिख देते हैं।

Shri Ramanathan Chettiar: May I know whether in the Commonwealth Prime Ministers' Conference, matters of trade among the Commonwealth countries are usually discussed?

Shri Jawaharlal Nehru: Yes; they will be discussed. To some extent they are bound to be discussed.

Shri Kapur Singh: Does the hon. Prime Minister propose to take another Minister with him to assist him in the discharge of his onerous duties?

Shri Ranga: Especially social functions.

Shri Jawaharlal Nehru: I have no present intention of doing so. There will be, of course, others going with me, but I doubt if a Minister will go with me.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में ऐसे राष्ट्र जिनमें कि भारतीय रहते हैं, जैसे लंका, वर्मा, फिजी और ईस्ट अफ़ीका के देश, जहां से कि भार-तीयों को निकाला जा रहा है और उस क रण एक बड़ी विचिन्न तथा गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो क्या उस समस्या को भी उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायगा जिससे कि कुछ उचित निर्णय लिया जा सके।

श्री जवाहरलाल नेहर : श्राम तौर से यह समस्याएं वहां पेश नहीं होती हैं। 12901

जिन बातों को लेकर मुल्कों में भापस में बहस हो मेरा खयाल है कि वह चीजें गालिबन वहां पेश नहीं होती हैं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: श्रलग ग्रलग उन से बात कर ली जाय । यह एक गम्भीर समस्या बन गयी है।

श्री जंबाहरलाल नेहरू: हो सकता है लेकिन श्राप इन बातों को देखें कि यह कोई नई बात नहीं है। लंका के बारे में श्राप ने भो कहा तो लंका की बात तो बहुत पुरानी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: फिजी की नई है, वर्मी की नई है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: वर्मा में प्रकेले हिन्दुस्तानियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने सारे विदेशियों के खिलाफ कदम उठाया है। उसमें हिन्दुस्तानी भी आ गये। लेकिन उन्होंने प्रकेले हिन्दुस्तानियों के खिलाफ ही कोई कदम प्रपने यहां नहीं उठाया है भी नहीं।

Shri A. P. Jain: Is it proposed to take up the question of the European Economic Community and the matters arising therefrom and the European free trade area?

Shri Jawaharlal Nehru: All these questions are usually referred to in the general discussion and not as specific items on the agenda. I suppose these will be dealt with in that way.

भी ओंकार लाल बेरवा : क्या इस सम्मेलन के अबदर चीनियों और पाकिस्ता-नियों ने जो हमारी सरहद दबा रक्खी है उस के बारे में भी विचार किया जायगा ?

प्राप्यक्ष महोवय : यह सवाल पहले ही पुछ लिया गया है। म्राकाशवाणी के समाचार विभाग सया वैदेशिक सेवा प्रसारण विभाग का पुनर्गठन

*११६७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि स्नाकाशवाणी के समाचार विभाग तथा वैदेशिक प्रसारण विभाग के पुनगंठन का प्रश्न विचाराधीन है; स्रोर
 - (ख) ऐसा कब तक कर दिया जायगा?

सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाय): (क) श्रीर (ख). समाचार सेवा विभाग का पुनगंठन १ मार्च १६६३ से किया जा चुका है। विदेश सेवा विभाग के ढांचे में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

[(a) and (b). The re-organisation of News Services Division has already been carried out with effect from the 1st March, 1963. As regards External Services Division, no change in its organisational set up is contemplated at present.]

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: १ मार्च, १६६३ से समाचार सेवा विभाग का जो पुनगंठन किया गया तो उसमें मुख्य क्या क्या परिवर्तन किये गये और उन की वजह से समाचार सेवा विभाग की कार्यक्षमता में कहां तक वृद्धि हुई है ?

श्री शामनाय: उसमें जो पोस्ट्स यीं उनको कुछ घटाया गया श्रीर कुछ पोस्ट्स को बढ़ाया गया है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : उसका डिटेल बतलाइये ।

प्रध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी में बह सारा डिटेल कैसे बयान किया जा संकता है भलबता भगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं मिनिस्टर साहब को कह दूं कि वह उस बारे में एक स्टेटमेंट रख दें। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: जी हां ऐसा कर दिया जाय।

श्रध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय समाचार सेवा विभाग के पुनर्गठन के बारे में एक स्टेटमैंट रख दें।

श्री सिद्धंक्वर प्रशाद : क्या यह बात सही नहीं कि दो साल पहले ऐसा निर्णय लिया गया था कि समाचार सेवा विभाग के अन्तर्गत एक हिन्दी न्यूज यूनिट अलग होगा श्रीर अंग्रेजी न्यूज यूनिट अलग होगा श्रीर अंग्रेजी न्यूज यूनिट अलग होगा श्रीर क्रियों के नाम पर यह हिन्दी न्यूज यूनिट के अलग से निर्माण की बात को रोक दिया गया है लेकिन अंग्रेजी न्यूज यनिट में ४ डिण्टी डाइरॅंक्टर न्यूज के बना दिये गये?

श्री शामनाथ : जहां तक इस चीज का ताल्लुक है आया कोई ऐसा फैसला लिया गया था गुझे उसका इल्म नहीं लेकिन हिन्दी और अप्रेजी को अलग करना एक नामुमकिन सी बात मुझे नजर आती है। न्यूज सर्विसेज डिबीजन एक यूनिट हैं और उस के मातहत मुख्तलिफ जबानों में रीजन्ल लेग्बेजेज में अप्रेजी में और हिन्दी न्यूज ब्रांडकास्ट होती हैं।

Shri Heda: While the reorganisation of the External Services Division is taking place, may I know if consideration has been given to the languages broadcast to the countries where people are speaking Indian languages and, if so, whether the extension of services in those languages under the External Services Division would be taken care of?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): For the present there is no such idea because the work, they say, is going on all right, and therefore it has not been thought necessary to make any reorganisation with regard to that particular thing.

भी द्वा० ना० तिबारी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस री-धार्गनाइजेशन के कारण खर्च में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, यदि वृद्धि हुई है, तो कितनी ?

श्री सत्य नारायण सिंह: सब एडीटर्ज की कुछ नई पोस्ट्स कीएट की गई हैं ग्रीर कुछ पास्ट्स की रिट्रेंच कर दिया गया है। खर्चा करीब करीब बराबर है—वैलेस्ड बजट है, या शायद थोड़ा बहुत फर्क रहा होगा। खर्चा बहुत नहीं हुआ है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो गया है।

Shri Hari Vishnu Kamath: If I heard the Deputy Minister aright, he said that there is no move to reorganise the External Affairs Publicity Services Division. May I remind the Minister of what the Prime Minister said in the course of reply to a debate. and also what the Deputy Mnister of External Affairs mentioned earlier, that there has been a continual examination of the efficiency of the External Publicity Services. In that context, may I ask the Minister what steps are being taken to reorganise the Publicity Services with a view to make them more efficient, particularly to counter-act the anti-Indian propaganda from Pakistan and from China?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): It is quite true that we continuously examine these things and make minor changes from time to time. But no major changes have been made recently.

Shri Hari Vishnu Kamath: Have they become more efficient to meet the demands of the time? How do you distinguish between major and minor changes? Would he kindly indicate what are the minor changes?

Shri Jawaharlal Nehru: How am I to say that in what way and what changes are made? I have not got them here. Apart from that, it is a bit difficult to refer to small changes that are being made—more people being sent somewhere, more people

being transferred from one place to another, the kind of information they should give and all that.

Shri Hari Vishnu Kamath: Are they more efficient today?

Shri Jawaharlal Nehru: I think, Sir, they are rather efficient now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: पाछ संगठ-काल में विदेशों के लिये विदेशी भाषाश्रीं, में जो सभाचार प्रसारित किये जाते थे, क्या उनमें कोई ऐसे समाचार भी प्रसारित कर दिये गए, जो भारतीय सुरक्षा और भारतीय परम्पराग्रों के सर्वया प्रतिकृत थे, यदि हां, तो जिन श्रधिकारियों ने इस प्रकार के प्रसा-रण किये, जिनके बारे में सरकार को बाद में पता चला, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की गई?

भी सत्य नारायण सिंह: माननीय सदस्य को मालूम होगा कि मुझे इस बात की ख़बर नहीं थो, लेकिन हमारे रेडियो के कुछ प्रधि-कारियों के घ्यान में यह बात लाई गई। उसके बाद ूमेरे सामने यह सवाल ग्राया। उस ग्रादमी को सर्विस से मुग्रत्तिल कर दिया गया है।

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether it is a fact that in spite of the fact that the number of news bulletins has increased the number of news editors remains the same and therefore the pressure of work is too much on the people?

Shri Sham Nath: It is a fact that the number of news bulletins has increased during the last few years. I have not been able to follow the latter part of the question.

Mr. Speaker: Next Question—Shri P. R. Chakraverti

Shrimati Savitri Nigam: I wanted to know whether in spite of the increase in the number of news bulletins there has been no increase in the number of news editors.

Mr. Speaker: Shri P. R. Chakraverti.

Goa

Τ.

| Shri P. R. Chakraverti: | Shri Hari Vishau Kamath: *1198. | Shri Sidheshwar Prasad: | Shri Harish Chandra | Mathur:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the speech of Mr. Adlai Stevenson, Chief U.S. delegate to the U.N. at Princeton University on 23rd March, 1964, describing the take-over of Goa by India as an outright invasion; and

(b) if so, whether Government have conveyed their reaction to the eminent speaker and circulated the same among the U.S. Universities, specially at Princeton?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (b). The Government have seen reports in the Press about Mr. Adlai Stevenson's speech in which reference was made by him to the liberation of Goa the armed action. Since Nations have already endorsed that Goa, Daman and Diu have nationally united with India, Government do not consider it necessary at this stage to take note of the personal opinion of an individual

Shri P. R. Chakraverti: Is it not a fact that Mr. Adlai Stevenson while making special mention of outright invasions singled out India to be responsible for the same; if so, may I know whether the Government is in a position to nullify the mischievous information conveyed to the world at large?

Shrimati Lakshmi Menon: We have seen the statement of Mr. Stevenson. I have already stated that the United Nations, by a resolution, No. 1807, passed in the General Assembly stated:

"in view of the fact that Sao Jose Batista d'Ajuda and Goa and dependencies were no longer under the administration of Portugal having been nationally united with Dahomey and India respectively."

In view of this it is not necessary for us to do anything because the whole world knows that it is part of India.

Shri P. R. Chakraverti: Is it not a fact that the outbursts of Shri Adlai Stevenson in the Security Council in 1961 over the question of Goa and the Resolution which was sponsored by the western nations and vetoed by Russia created tension to the extent of straining our relations with the U.S.A. and President Kennedy had to make some amends for the same privately?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): I do not exactly remember this past incident, but it is a fact that some people, mainly Mr. Adlai Stevenson. hold a certain opinion which, we think, is absolutely unjustified. knows it and everybody knows it that it is our opinion about his opinion. I do not think his opinion has gone very far. So far as the Nations and others are concerned, my colleague has already read out to you the Resolution passed by it in regard to Goa.

Shri Hari Vishau Kamath: Is it a fact that India's voice, once powerful, against colonialism and imperialism has not been heard with respect in the comity of nations, particularly in Europe and America, barring the small number of pro-China countries, since Government's cowardly acquiescence in China's colonial and neo-imperialist hold over Tibet; if so, does this have anything to do with this misunderstanding on this matter on America?

Shri Jawaharlal Nehru: I think, what the hon Member has said is absolutely wrong, 100 per cent wrong.

Shri Hari Vishau Kamath: What is wrong?

Shri Jawaharlal Nehru: It is wrong that it has anything to do with our attitude towards China's invasion of Tibet. That happened 10 or 12 years ago.

Shri Hari Vishnu Kamath: I said it appears that Government's stand as regards China's hold over Tibet . . .

Shri Jawaharlal Nehru: Whether we acquiesced or not before, it is absolutely wrong, that is, the effect of that on this because what he refers to perhaps-I do not think he is correct but still-maybe, is due to something recent in regard to our position in regard to those matters, not 7, 8 or 16 years old. That is due to many causes which can be investigated and which are being investigated. It is wrong to think that India's influence is very much less than it used to be. It is less in the sense that we do not quite shout as loudly . . .

Shri Hem Barua: We did a lot of shouting before.

Shri Jawaharlal Nehru: Whether we did shout before or not, others shout louder . . .

Shri Hem Barua: On a previous occasion you admitted that we shouted loudly.

Shri Jawaharlal Nehru: like, if I may say so, the hon. Member who is putting the question. I do not think fundamentally it is correct. Our influence is very considerable. Sometimes we feel that we do not—I would use again the word 'shout' enough; we talk in a more mature way but our basic positions are the same as we took up.

Shri Hem Barua: Great power Chauvinism.

श्री सिद्धेक्वर प्रसान्वः भ्रभी वैदेशिक-कार्यं मन्त्रालय की राज्य-म त्री ने बताया कि यह श्रा एडलाई स्टीवन्सन का वैयक्तिया विचार था, लेकिन दो तीन साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के प्रतिनिधि की हैसियत सं उन्होंने ऐसा ही विचार व्यक्त किया था और अब फिर उन्होंने उस बात को दोहराया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा इस कारण है कि भारत अपने पक्ष को वहां पर प्रस्तुत करने में असफल रहा है या श्री एडलाई स्टीवन्सन ने अकान और पूर्वाग्रह के कारण ऐसा विचार प्रकृट किया है।

Mr. Speaker: Is it due to our inability that Mr. Adlai Stevenson has not been able to appreciate our standpoint or is it that he has that particular notion or personal views?

Shri Jawaharlai Nehru: I regret, ft may be our inability to explain something to Mr. Adlai Stevenson, or it may be his inability to understand.

Shri Hari Vishnu Kamath: Our Embassy's public relations in the United States is the unfortunate part.

Shri Harish Chandra Mathur: Mr. Adlai Stevenson is more than a private individual being a representative of the U.S. Government at the U.N.

An Hon. Member: He is the Chief Delegate.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know whether this is his personal view or it is also the view of the U.S. Government? When he expresses such an opinion, the world takes it to be the opinion of the U.S. Government. In the light of the U.N. Resolution just now quoted may I know whether the matter has been taken up with the U.S. Government rather than with Mr. Adlai Stevenson?

Shri Jawaharlal Nehru: I suppose, it is his personal view and not the view of the U.S. Government. The

matter has not been taken up with the U.S. Government. We take it as his personal view.

Shri Harish Chandra Mathur: What gives us to think that it is not the view of the U.S. Government? If it is not the view of the U.S. Government, could we not ask the U.S. Government to ask this gentleman to hold his tongue?

Shri Jawaharlal Nehru: The U.S. Government does not funtion in that way. They have not taken Shri Mathur's advice as to how they should function.

Dr. Ranen Sen: I want to ask the same question asked by Shri Harish Chandra Mathur in a different way. It is a well known fact that Mr. Adlai Stevenson has always been an important representative of the U.S. Government. What is the reason that the Government has taken the statement that he made about the invasion of Goa by India as his personal opinion and not as the opinion of the U.S. Government?

Shri Jawaharla Nehru: Mr. Adlai Stevenson was speaking at a university function—I think, at the Princeton University—which has nothing to do with the Government. There people are in the habit of giving expression to their personal opinions. The Government's policies are not stated there. We, therefore, presume that it was so and we have previously too said so. Mr. Adlai Stevenson's opinions about Goa are notorious for their wrongness.

Dr. Sarojini Mahishi: May I know the context in which Mr. Adlai Stevenson made this remark that the take-over of Goa by India is an outright invasion?

Shrimati Lakshmi Menon: He was delivering the Dag Hammarskjoeld Memorial Lecture at the Princeton University.

श्री यशपाल सिंहः क्या गवनेमेंट के पास भ्रमरोका के किन्हीं ऐंत मुदब्बरों के बयान हैं जिनमें उन्होंने गोग्रा के मामले में या काश्मीर के मामले में हिन्दुस्तान को स्पोर्ट किया हो ?

भी जवाहरलाल नेहर : बहुत सारे व्यान हैं, कुछ व्यान तो ऐसे हैं लेकिन श्रकसर ब्यान इसके खिलाफ भी हैं।

Shri Hem Barua: The hon. Minister has said that the U.N. Security Council by a Resolution has endorsed the emancipation of Goa.

Shrimati Lakshmi Menen: I said, the General Assembly.

Shri Hem Barua: That is all right. The General Assembly has by a Resolution endorsed the emancipation of Goa and Mr. Stevenson is the Chief U.S. Delegate to the UNO. After the adoption of this Resolution when he goes about making speeches to the contrary, do the Government not think that he is violating the Resolution of the U.N. General Assembly?

Shri Jawaharlal Nehra: We do not think so; in any event, Government is not going to draw attention to this fact. It is up to him to violate it in his speech as much as he likes.

Pakistani Ambush in Kashmir

- *1199. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 599 on the 16th March, 1964 and state:
- (a) whether the inquiry by U.N. Observers in Kashmir into the recent Pakistani ambush of Indian patrolmen near the cease-fire line has been completed; and
- (b) if so, their findings and conclusions?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. R. Chavan):
(a) Yes, Sir.

(b) The U.N. Chief Military Observer has awarded a violation of ceaseare against Pakistan for crossing the cease-fire line and for firing on our police patrol.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is there any truth in certain reports to the effect that some of the patrolmen who were believed to have been killed in the ambush are now prisoners in Pakistani territory; if so, has Government demanded the return of those patrolmen?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): It is true that there are nine persons who are in the captivity of Pakistan and we have demanded their return. About the killed persons, it seems that 14 persons have been killed and their bodies were thrown in the Kishenganga River.

Shri Hari Vishnu Kamath: Has any compensation been demanded by the Government from Pakistan in respect of those who were killed by them in this ambush?

Shri Y. B. Chavan: Yes, we have demanded compensation.

Shri Hari Vishnu Kamath: How much?

Shri Y. B. Chavan: Compensation has been demanded for the families of 14 persons who are believed to have been killed.

Dr. L. M. Singhvi: In what way have Government satisfied themselves that as a matter of fact certain persons who are alleged to have been dead in the ambush or who were actually killed are not detained by Pakistan? What efforts have been made to obtain the list of names of those who are at present detained with Pakistan?

Shri Y. B. Chavan: We have got only general information about the number of persons but we have not got the detailed information about the names etc. We shall try to get the information from Pakistan.

12913

Shri Sham Lal Saraf: May I know what steps have been taken to make it difficult for Pakistan patrol troops to cross Kishenganga river and ambush our people in view of the fact that that part of the area was lying unprotected?

Shri Y. B. Chavan: I think, the only effort that can be made is to be rather more vigilant about their activities and try to be strong in punishing them if they do so.

भी बड़े: प्रभी बताया गया है कि कम्पेंसे-मन या उमिजिज मांगे गये हैं। १६ मार्च को यह इंसीडेंट हुम्रा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान का कोई जवाब म्राया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जवाब तो नहीं श्राया है।

Shri Hem Barua: The U.N. Observers' team has submitted a report holding Pakistan responsible for this vandalism. May I know whether the Government have asked the U.N. Instead of putting this report in the official pigeon-holes to move in the matter?

Shri Y. B. Chavan: We have asked our Permanent Representative to take up the matter with the President of the Security Council.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether some bodies have been recovered from the river and whether they have been identified or not, and if they have been identified what compensation has been paid to the families of those people from the side of the Indian Government?

Shri Y. B. Chavan: In such cases, certainly we give some sort of an aid to the families concerned and it continues to be given. No bodies have been found and so no question of identification arises.

भी क० ना० तिवारी: माननीय मन्ती जी ने कहा है कि कम्पेंसंशन मांगा गया है श्रीर कोई जवाब नहीं श्राया है। इसके सम्बन्ध में हाई कमिश्नर पाकिस्तान को क्या कोई इंसट्रकशन दी गई हैं कि वह इस बात को प्रेष्ठ करे श्रीर उनका जवाब ले ?

Shri Y. B. Chavan: The award came sometime in the first week of April. We have moved them after that. We must give them the usual time to reply.

भी प्रकाशवीर शास्त्री: संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रेक्षक यहां रहते हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होने के कारण इस प्रकार की घट-नायें बढ़ रही हैं। ग्रभी उनके प्रतिनिधि प्राए ये देखने के लिए और निण्चय हुश्रा था कि इनकी संक्या को बढ़ाई जाए। हम भी ग्रनुभव करते हैं कि संख्या को बढ़ाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई श्रन्तिम निण्य हो गया है, यदि हो गया है तो वह क्या है?

भी यशवन्तराव चव्हाण : मन्तिम निर्णय तो नहीं हुन्ना है। लेकिन यह बात फिर दोहराई गई है। उनके रिप्रिजेटेटिव डा० राहफ़ बंच के साथ यह सवाल उठाया गया है।

Shri Kapur Singh: Is this cease-fire line regarded by us for all practical purposes as the international boundary or merely a line of confrontation between two opposing armies on disputed territory?

Shri Y. B. Chavan: Cease-fire line is a cease-fire line.

Mr. Speaker: Shri Kashi Ram Gupta.

Shri Kapur Singh: My question has been evaded. He says, cease-fire line is a cease-fire line. This is not any reply to my question either directly or indirectly.

Mr. Speaker: Probably he does not accept both alternatives that the hon. Member conveyed to him. This is the third one.

भी काशीराम गुप्त : पाकिस्तान ने इस बात का विरोध किया है कि य० एन० म्राम्जवज की संख्या बढाई जाए, क्या यह सच है ? यदि यह सच है तो भारत सरकार ने इनकी संख्या बढाये जाने के बारे में पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या रुख ग्रखत्यार किया है ?

Shri Y. B. Chavan: We have no information about the reaction of the Pakistan Government about raising the number of observers. We have no information on that.

थी प्र० प्र० शर्मा : ग्रभी बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं स्राया है। पत्र कांभजे हुए एक महीने से अधिक हो गया है। मैं जानना चाहता हं कि और कितने दिन तक इन्तजार किया जाएगा ? ग्रगर जवाब नहीं ग्राएगा तो क्या कदम उठाया जाएगा ?

ग्रम्यक महोवय : यह हिपोथैटिकल है कि क्या कदम उठाया जाएगा। कब तक जवाब पाने की उम्मीद है, यह बतला दिया जाए।

भी ग्र० प्र० शर्मा: ग्रीर कितनी इन्त-बारी की जाएगी?

Shri Y. B. Chavan: We will have to wait for some time. Again, we will have to remind them over.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know what was Pakistan's version about this incident, which was not held to be correct by the U.N. Observers, and may I know whether they have accepted that they have captives with them.

Shri Y. B. Chavan: Their version was that the Indian patrol attacked their villages, which not true.

Indians in Ceylon

*1200 Shri Ramanathan Chettlar: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether any new restrictions have recently been imposed on Indian Nationals in Ceylon in regard to remitting money to their families in India: and
- (b) if so, what are those restric-

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). No new restrictions have been imposed. However, with effect from 1-2-1964, a tax 10% is payable on remittances abroad regardless of the nationality of the remitter.

Shri Ramanathan Chettiar: May know whether apart from this tax of 10 per cent, there are other restrictions imposed by the Foreign change Controller in Colombo in regard to remittances by nationals to India?

Shri Dinesh Singh: There are new restrictions. We are aware the old restriction that about 33 1|3 per cent of their earnings up to a total of Rs. 750 per month, subject to the need of the families, can be sent.

Shri Ramanathan Chettiar: Has it been brought to the notice of Government that people who want to wind up their business informed the Foreign Exchange Controller in Colombo during the process of winding up; that they wanted to remit funds out of the sale proceeds of their property, and yet, they are being prevented from doing so; and if so, what steps will Government take to take up this matter with the Ceylon Government?

Shri Dinesh Singh: I am not aware of any such difficulties. In fact, the Government of Ceylon are some incentive for them to come away.

Shri P. Venkatasubbaiah: May know whether the attention of Government has been drawn to the fact that nearly 80,000 people from Ceylon are waiting before the Indian High Commission there, and most of them are South Indians and they are not able to get back to their country because of these financial difficulties, and if so, what arrangement Government propose to make in this regard?

Shri Dinesh Singh: I am not aware that it is 80,000.

Shri Hem Barua: May I know whether the attention of Government has been drawn to a recent report coming from Ceylon to the effect that although sufficient time has been given to the Indian Government to come to an agreed solution about the Indians and persons of Indian origin in Ceylon, it is the Indian Government that has not moved in the matter, and if so, may I know how far this allegation is correct?

Shri Dinesh Singh: That is not true. We have mentioned on the floor of the House that a reply has been sent by the Prime Minister, and we are now awaiting the reply of the Prime Minister of Ceylon about her coming here to discuss this matter.

श्री श्रोंकार लाल बेरवा: एक तरफ तो उन्होंने यह मांग की थी कि भारत के व्यापारी हमारे यहां आकर कुछ व्यापार को बड़ायें भीर दूसरो तरफ यह प्रतिबन्द लगा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जनको को ई लेटर लिखा है।

श्री दिनेश किह: मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने हमारे व्यापारियों को बुलाया है।

श्री गुलझन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है कि जो लोग जंजीबार, पूर्वी पाकिस्तान, खंका और बर्मा से निकल कर भा रहे हैं उन भारतवासियों को यहां बसाने का कुछ प्रवन्ध किया जाये, यदि हां, तो क्या।

भी दिनेश सिंह: जी हां, जो मारतवासी वापस श्रा रहे हैं उन को बसाने के लिये हम कुछ इन्तजामात कर रहे हैं।

Shri Ranga: In view of the fact that Government admitted the other day that several thousands or lakhs of these Stateless Indians, who are supposed to be Stateless citizens in Ceylon have been offered inducements by that Government and yet our people are not prepared to accept them because they were either inadequate or they like them, may I know whether Government have made any representation to the Ceylon Government in regard to this matter, either to increase the quantum of that inducement or to provide for them some employment? In the absence of citizenship and citizenship rights, what is the position of these Stateless people? Are they completely unemployed, or do they continue employed there?

Shri Dinesh Singh: It is not a question of the inadequacy of the compensation. Those people feel that they are Ceylon citizens, and they have applied for Ceylon citizenship, and they feel that they should be given Ceylon citizenship to stay on there. It is not a question of their wanting to come away at all.

Shri Ranga: In the meanwhile, what is their position? Are they employed there or are they being provided with any employment, or are they being given any trouble there?

Shri Dinesh Singh: Most of them are employed. There may be some who are not employed,

*1202.

Pakistani Raid in a Village near Jamma

+

Shri D. C. Sharma;
Shri Bade:
Shri Hukam Chand
Kachhavaiya;
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri S, L. Verma;
Shri Brij Raj Singh;
Shri D. D. Mantri;
Shri P. C. Borooah;

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether an entire family of five Indians was killed on the 7th April, 1964 in a border raid by Pakistanis. in village Mora Romani near Jammu; and
- (b) ff so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. R. Chavan):

(a) On the night of 7th|8th April 1964, an Indian family of five members was murdered in village Mora Romani, Police Station Hiranagar, District Kathua The village was inhabited by the only house belonging to the deceased family. The identity of the culprits responsible for the crime is not known.

- (b) The local police are investigating the case.
- Shri D. C. Sharma: What is the distance of Mora Romani from Jammu and how far is it from the border, because that would show how far the Pakistanis can come into our territory after straying from the border?
- Shri D. B. Chavan: It is about 8 miles to the north of the police station I have referred to. Then it is 10 miles to our side of the border.
- Shri D. C. Sharma: How is it that Pakistanis can come beyond ten miles of the border into our territory and murder a family of 5 Indians? Have we not got any kind of vigilance 472 (Ai) LS—2.

so that they cannot come into our territory?

Shri D. R. Chavan: There is no evidence to show that the Pakistanis came and committed this crime. Actually, as a matter of fact, the evidence is otherwise. It is the culprits from our side who are responsible for the crime.

Shri Hem Barua: On a point of order. Just now the Minister stated that the matter is being investigated by the Police. But now he comes out with a statement.

Mr. Speaker: I agree with the hon. Member. He ought not to have given his opinion.

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि जम्मू एरिया में यह आतंक फैल गया है कि प्रत्येक पाकिस्तानी को जो कि एक हिन्दू का सिर लायेगा १००६० मिलेंगे और इन पांच मडंसे में जो लोग मारे गये उनके सिर नहीं थे तथा गांव वालों की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी लोग आये ये और उन्होंने मारा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चृकि आपने वहां शस्त्र नहीं दिये थे इस वास्ते वे अपने को डिफेन्ड नहीं कर सके। यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको शस्त्र देने का कोई विचार किया है...

श्रध्यक्ष महोदय: श्री वड़े वही बात कहना चाहते हैं जिस पर श्री हेम बरुझा ने ऐत-राज किया था।

श्री बड़े: मेरा कहना है कि इस र्यूमर से वहां बड़ा श्रातंक फैल गया है। उस गांव के श्रन्दर यह र्यूमर है कि जो पाकिस्तानी एक हिन्दू का सिर लायेगा उसको १०० ६० दिये जायेंगे श्रीर उन पांच भादिमियों के सिर नहीं थे।

प्राप्यक्ष महोदय : क्या श्री बड़े फिर चाहते हैं कि यह कहा जाये कि पाकिस्तानी नहीं भाये हैं। 12921

श्री बड़े: मैं जानना चाहता हूं कि यह र्यमर है या नहीं।

ग्राध्यक्ष महोदय : ृइसके लिये क्या कहा जा सकता है।

भी बड़े: मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के सिर थे या नहीं या मर्डरसं उनके सिर काट कर ले गये थे।

म्राच्यक्ष महोदय : क्या मर्डरर्स उनके सिर काट कर ले गये थे।

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): It is not so.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that about a couple of months ago the Chinese Military Attache to the Chinese embassy in Karachi along with high Pakistani military officers paid a visit to the cease-fire line in Kashmir, and since then these border raids have been stepped up there?

Shri Y. B. Chavan: I have no definite information.

Shri Sham Lal Saraf. This area is near the international border; there is no rease-fire line there. Is Government aware of the fact that raids are taking place on this side of the border also from Pakistan? If so, what precautions are being taken and will be taken to put a stop to them?

Shri Y. B. Chavan: I have answered that in the case of these raids, at present we are taking quite active steps to see that they do not happen and in case they happen, we have taken messures to see that they are severely punished.

Shri Sham Lal Saraf: My question is very important. Till now raids were taking place across the cease-fire line. But this international border was free from them. Now Paking tan has started raids on this part of the border also. What precautions are being taken to stop raids at least in this part of the State?

Shri Y. B Chavan: The same precautions which are taken in the case of the cease-fire line are being taken in this part of the international border.

Maharajkumar Vijaya Ananda: May I know how many men, women and children were involved in this killing?

Shri Y. B. Chavan: Five—two men, two women and one child.

Maharajkumar Vijaya Ananda: Muslims or Hindus?

Shri Y. B Chavan: Hindus.

Shri A. P. Jain: This village of Mora Romani is ten miles within Indian territory. During the last one year, what is the maximum distance to which any Pakistani raiders have infiltrated into our territory?

Shri Y. B. Chavan: I think it is not more than two or three miles.

Mr. Speaker: Shri Tulsidas Jadhav.

Shri Hem Barua: Again, on a point of order.

Mr. Speaker: After I have heard him.

श्री तुलशीदास जायवः : जब बार्डर के गांवों में बार बार ऐसा होताहै, तो वहां एक्स्ट्रा पुलिस और मिलीटरी क्यों नहीं रखीं जाती ?

Shri Y. B. Chavan: I think the police are there, and the minimum or maximum that we can place according to the cease-fire agreement is there.

Shri Hem Barua: The hon. Minister just now said that it is not more than two or three miles, but his Deputy said it was beyond ten miles. Which statement are we to accept, are you to accept?

Shri Y. B. Chavan: No, he did not ask about this particular case, he asked generally what happened during the last year.

Shri A. P. Jain: This was also during the last one year.

गोम्रा में ईसाई मिशनरी

+ ∱श्री प्रकाशवीर शास्त्री : *१२०३. {श्री झोंकार लाल बेरवा : श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि गोग्रा के मुख्य मन्त्री ने गोग्रा में विदेशी ईसाई मिश-नरियों की गतिविधियों पर चिन्ता प्रकट की है;
- (ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि एक विशिष्ट भिशनरी संस्था श्रागामी दिसम्बर में एक धार्मिक सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है; और
- (घ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित सम्मेलन के श्रायोजकों को वित्तीय सहायता देने का श्राश्वासन दिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) श्रीर (ख). भारत सरकार ने गोश्रा के मुख्य मन्त्रो द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में अखवारों में रिपोर्ट देखी हैं, लेकिन गोश्रा की स्थानीय सर-कार द्वारा गोश्रा में विदेशी ईसाई धर्म प्रचा-रकों की कथित कार्यवाइयों के विषय में श्रभी तक सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है!

- (ग) जहां तक सरकार को मालूम है, नवम्बर-दिसम्बर, १६६४ के दौरान बम्बई में एक अन्तराष्ट्रीय यूकेरिस्ट कांग्रेस होगी और गोग्रा में इस वर्ष दिसम्बर में उन्ट फांसिस जैवियर के अवगेजों का दर्शन कराया जायगा।
- (व) संन्ट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के दर्शन के अवसर पर आने वाले तीर्थ यात्रियों

को सुविघाएं देने की प्राथमिक जिम्मेदारी गोग्रा प्रशासन पर है।

- [(a) and (b). The Government have seen reports in the Press about the statement reported to have been made by the Chief Minister of Goa, but no official confirmation about the alleged activities of the foreign Christian missionaries in Goa has been received from the local Government so far.
- (c) As far as the Government are aware, an International Eucharistic Congress will meet in Bombay during November-December, 1964 and the Exposition of the remains of St. Francis Xavier will be held in December this year in Goa.
- (d) It is primarily the responsibility of the Goa Administration to provide facilities to pilgrims visiting Goa on the occasion of the Exposition of the remains of St. Francis Xavier.]

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: माननीय मंत्री जी को मुन्दर हिन्दी में उत्तर देने के लिए घन्यवाद देते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि गोग्रा में इस समय कितने फारिन मिशनरी हैं ?

Shrimati Lakshmi Menon: I want notice for that.

श्रध्यक्ष महोदय : श्रापने जो सुन्दर हिन्दी में जवाब दिया उसके लिए वह श्रापकी प्रशंसा करते हैं ।

Shrimati Lakshmi Menon: There are very few, hardly any I think.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: पीछे गोधा में जो सामान्य निर्वाचन हुए उनमें यूनाइटेड गोधन्स पार्टी मुख्य विरोधी दल के रूप में श्रायी है। उसके बारे में कानों में कुछ ऐसी भनक पड़ी है कि इसको विदेशों से भी कुछ सहायता प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है तो इस बारे में सरकार की क्या जानकारी है ?

Shrimati Lakshmi Menon: We have no information that they have received any help from foreign sources.

Oral Answers

श्री ग्रोंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हं कि जहां और संस्थाओं के घार्मिक काम होते हैं वहां भी क्या हमारी सरकार इस प्रकार की सहायता देती है ? यदि नहीं तो इस संस्था को क्यों ये सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्रध्यक्ष महोदय : हमारी सरकार ने सहायता नहीं दी है।

श्री भ्रोंकार लाल बेरवा : गोम्रा की सरकार ने तो दी है।

Shrimati Lakshmi Menon: When there is a big Exposition like that, thousand of people will come from all over the world, and certainly it is the responsibility of the Goa Government to provide amenities necessary for the occassion.

Shri Hari Vishnu Kamath: She said "primarily", not wholly,

Shri Ramanathan Chettiar: Is it a fact that the foreign missionaries in Goa are getting large remittances from foreign countries to do propaganda?

Shrimati Lakshmi Menon: I have answered that question. I said had no information about that.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: May I know if it is a fact that the Patriarch of Goa took up a very hostile attitude after liberation, and whether there has been any change in his attitude since then after complete merger?

Shrimati Lakshmi Menon: I do not vouch for it. As far as I am aware, the patriarch, that particular person the hon. Member refers to, is not there anymore.

Shri Swell: Is it a fact that the Christian missionaries have, by their selfless service, contributed a great deal towards the growth of social and educational uplift of this country and, if so, have Government considered the possibility that these criticisms against the Christian missionaries may be inspired by narrow, political and sectarian interests?

Shrimati Lakshmi Menon: That is a matter of opinion.

Shri Shinkre: In view of the fact that most of these missionaries, together with education and other services they usually impart, have always some sort of proselytizing work also carried in a guarded manner are Government considering any steps to check these activities?

Shrimati Lakshmi Menon: I have already said that all these allegations made have to be confirmed from the State Government and we have not received any confirmation.

Shri P. G. Sen: May I know if there is anything behind the scene these activities of Christian missionaries in relation to Goa?

Shrimati Lakshmi Menon: I do not know what happens behind the scene.

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी सन् १९४७ के बाद, गोग्रा में फारिन मिशनरी ज्यादा बढ गये हैं भ्रीर वे सरकार के खिलाफ प्रचार करते हैं और क्या ऐसा नागालैंड और झार-खंड में भी हो रहा है ?

म्राच्यक्ष महोदय : भ्राप गोभ्रा तक ही रहिये ।

श्री बड़े: क्या गोग्रा में भी कुछ इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं और क्या इन की ग्रीर सरकार का ध्यान गया है ?

Mr. Speaker: He says that in general the activities of Christian missionaries have increased since Independence?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): For the whole of India or in Goa?

Mr. Speaker: He may say about Goa.

Shri Bade: Nagaland also.

Shri Jawaharlal Nehru: There are no outside missionaries in Nagaland—not one in Nagaland. In Goa, I do not think that any new missionaries have come. A few people are there; a few may have changed and they are carrying on in the old way. We have not heard of any special activities.

युद्धविराम रेखा का उल्लंघन

+ श्रीसिद्धेश्वर प्रसाद : *१२०४. श्रीसु० ला० वर्षा : श्रीश्रोंकार लाल बेरवा :

क्या प्रसिरक्ता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) जम्मू तथा काश्मीर के भारतीय राज्य क्षेत्र में पाकिस्तानियों ने कितनी बार छापे मारे तथा मार्च, १९६४ में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया;
- (ख) उनमें कितने भारतीय सैनिक मारे गये, घायल हुए; ग्रौर
- (ग) कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे मये, घायल हुए ध्रयवा बन्दी बनाये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रास्य में उपमंत्री (श्री बा० रा० चरहाण): (क) पाकिस्तानियों ने मार्च १६६४ में युद्ध विराम रेखा-ग्रन्त-र्राष्ट्रीय सीमा का ३६ बार उल्लंघन करने के मितिरक्त, जम्मू-कश्मीर में युद्धविराम रेखा तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार ७ बार धाकमण किया।

- (ख) कोई भारतीय सैनिक मारा नहीं गया; परन्तु एक घायल हुम्रा था।
- (ग) २४ पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिक मारे गये थे । कोई बन्दी नहीं बनाया गया । षायल होने वालों की संख्या मालूम नहीं है ।

- [(a) During March 1964, Pakistanis carried out 7 raids across the cease-fire line and international border in Jammu and Kashmir, apart from violating the cease-fire line|international border on 36 occasions.
- (b) No Indian soldier was killed but one was wounded.
- (c) 24 Pakistani armed personnel were killed. None was captured. The number of those wounded is not known.]

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ग्रभी दूसरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय रक्षा मंत्री ने बताया था कि हाल ही में पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन में वृद्धि हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Well, Sir, in the month of March there are normally larger violations. It is difficult to say why it happens so, but, as we said last time, possibly it has something to do with the Security Councils meeting. That is the normal pattern of things. Whenever there is talk about the Kashmir problem publicly either in India or Pakistan or in the Security Council, this number increases.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या पाकिस्तानियों द्वारा जो युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया गया उस में कुछ हथियार भी पाये गये हैं ? यदि हां, तो वे किस देश के बने हुए हैं।

Mr. Speaker: Of what make is the weapon seized?

Shri Y. B. Chavan: So far we have got evidence that they had their own Pakistani manufactured weapons and some of the weapons which they had got at the time of partition of India and Pakistan.

Shri Sham Lal Saraf: In view of the fact that two vigorous and aggressive voluntary organisations have been set up by Pakistan known as Khansars and Ujhaids—they are crossing the cease-fire line and also in East Pakistan—may I know what effective steps are being taken to counter these guerilla tactics that are being adopted by Pakistan on these two wings?

Shri Y, B. Chavan: I think the only effective step that we are taking or we should take is to make use of our own armed forces and materials there under the agreement of the cease-fire line. We are not doing anything else now.

Shri Jashvant Mehta: When the question was before the Security Council, and day in and day out Pakistan had started a crusade against India, at that time may I know what steps the Government has taken to counteract the propaganda by Pakistan and the mischief created to the border by raiding across the cease-fire line?

Shri Y. B. Chavan: I have explained what steps we are taking to prevent these raids.

श्री भ्रोंकार लाल बेरवा : इन घटनाश्रों में निरन्तर बढ़होतरी होती जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन रेड्स को रोकने के लिए क्या सीमाश्रों पर तैनात हमारी सेनाश्रों में कुछ बढ़होतरी की गई है ?

श्री यशवन्त राव चल्हाण : वृद्धि करने की बात है नहीं लेकिन जैसा मैं ने पहले कहा रेड्स को रोकने के लिए हमारी तरफ से कार्यवाही हो रही है। उसका कुछ असर भी हो रहा है और यह रेड्स इघर कुछ कम भी हो गये हैं।

WRITTEN ANSWERS TO QUES-TIONS

प्रचान मंत्री को प्राप्त उपहारों के लिए संग्रहालय

*११६२. श्री विश्वनाय पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार प्रधान मंत्री को ग्रापने विदेशी मित्रों से उपहार स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुग्रों का प्रदर्शन करने के लिए एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार कर रही है; श्रौर
- (ख) यदि हां, तो यह संग्रहालय कब तथा कहां पर स्थापित होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Praga Tools Ltd., Secunderabad Shri Maheswar Naik: *1193. { Shri Ram Harkh Yadav: Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether the administration of Praga Tools Ltd., Secunderabad has been taken over by the Defence Ministry from the Department of Heavy Engineering;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) to what specific use the factory will be put under the new management?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

- (b) The transfer was made to facilitate the effective utilisation of the capacity available in Praga Tools Ltd. for the production of Defence equipment and stores. This will be done without serious detriment to the projects already undertaken by Praga Tools e.g. lathe chucks etc.
- (c) The following new schemes are under consideration:—
 - (i) Manufacture of carbines and gun carriages:
 - (ii) Manufacture of jigs, toolings etc. required for Ordnance Factories.
 - (iii) Expansion of forging capacity

Benefits to children of Deceased Army Officers

*1194. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether Government have of late decided to extend the gratuity benefits to the children of deceased Commissioned Army Officers in the absence of the widow;
- (b) if so, to what extent and upto what age the children would be eligible to receive the gratuity; and
- (c) the reason why this benefit has not been extended to the children of deceased Non-Commissioned officers also?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir.

- (b) When there is no widow, the children of a deceased Indian Commissioned Officer under the age of 18 years will normally be granted the gratuity at 50 per cent of the rate laid dow_n for the widow.
- (c) Children of deceased personnel below officer rank are already eligible under the Regulations to receive the gratuity at the full rate.

Indian High Commission in U.K.

*1201. Shri Andrajit Gupta: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether three different types of service conditions are in force for the staff of the Indian High Commission in U.K.;
- (b) whether this is having a harmful impact on the efficiency of work;
- (c) whether Government have reviewed the staff position from the point of view of both efficiency and economy; and
- (d) whether there is any proposal to remove the differences in service conditions, particularly those which are legacies of pre-independence days?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) Yes, Sir

- (b) No, Sir.
- (c) Yes, such reviews had been undertaken periodically by officers and teams of officers from India. The High Commission have also a permanent Economy Board of its own with heads of various Departments and the Financial Adviser as its members. This Board reviews the High Commission's staff position from time to time from the point of view of both efficiency and economy.
- (d) A start in this direction has already been made by introduction of a scheme of Local Cadre, by which the bulk of staff has been drawn away from adherence to U.K. terms of service and has been brought into proximate relation with the organic pattern of the Government of India.

Aircraft Production

- *1205. Shri Indrajit Gupta: Will the Minister of Defence be pleased to state:
- (a) whether it has been decided to set up a single integrated concern to manage the various aircraft production projects under his Ministry;
- (b) if so, the main features of the plan; and
- (c) the advantages expected to accrue from such integration?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramalah): (a) Yes, Sir.

- (b) The details are being worked out.
- (c) Economies of large scale production and conservation of technical and design effort will accrue from the formation of an integrated corporation for the manufacture of all types of aircraft and components.

Import of Newsprint

Shri P. C. Borooah:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kapur Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand
Kachhavaiya:
Shrimati Johraben Chavda:

Will the Minister of Information and Breadcasting be pleased to state:

- (a) whether his Ministry has been successful in securing some more foreign exchange for newsprint so as to be able to avoid further cuts in the imports of newsprint quotas during 1964-65 as announced earlier;
 - (b) if so, how much additional foreign exchange has been secured for the purpose; and
 - (c) which section of the press was likely to be affected by the cuts announced earlier?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):
(a) and (b). Efforts are being made to maintain the level of licensing as during the year, 1963-64 and most of the cuts announced on 2nd April 1964, are likely to be removed.

(c) Newspapers and periodicals whose annual entitlement of standard newsprint was more than 500 metric tonnes per annum and users of glazed newsprint with annual entitlement of more than 25 metric tonnes are affected by the cuts announced in the Public Notice dated the 2nd April, 1964.

Atrocities Committed on Women in East Pakistan

*1207. Shri D. C. Sharma: Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether the All India Women's Food Council has demanded that the Union Government bring the atrocities committed on women in East Pakistan to the notice of the United Nations through a delegation consisting of women leaders which may also visit other countries to seek support of women (iganisations; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto?

12934

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi-Menon): (a) and (b). It is understood that the President of the All-India Women's Food Council feels that a deputation of women leaders should bring to the notice of the United Nations the atrocities committed on women in East Pakistan. She has not, however, approached the Government of India in this matter.

Indian Embassy in Vienna

*1208. Shri Indrajit Gupta: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Indian Embassy at Vienna had been without an Ambassador for several months until very recently;
- (b) whether it is also a fact that some other important posts in the Embassy were also lying unmanned; and
 - (c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (c). Yes, there has been some delay but this is partly due to the fact that it takes some time to complete obligatory protocol formali-Ambassador Our former ties. Vienna, Shri A. S. Lall, handed over charge on the 1st August, 1963 and the announcement of Shri P. N. Haksar as our new Ambassador at Vienna was made on 27th November, 1963 as soon as the formalities were completed. Hehas already reached Vienna.

(b) No.

Nationalisation of Land in Zanzibar

Shri P. C. Borooah:
Shri Prakash Vir Shastri:
*1209. Shri Jashvant Mehta:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether the Zanzibar Govern-

ment have decided to nationalise land in that country;

- (b) if so, how far the land belonging to the Indians is to be involved in this move; and
- (c) the number of those Indians who have already left Zanzibar and the steps being taken to settle the accounts relating to acquisition of their property by Zanzibar Government and to repatriate rest of their assets?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) The Government of Zanzibar have on the 17th March, 1964 promulgated a decree providing for the confiscation of property where it appears to the President that such acquisition is in the national interest and that the acquisition of such property without payment of compensation would not cause undue hardship to the owner.

(b) and (c). No reports have so far been received as to the effect of this decree in actual application. We understand that about 1300 persons of Indian origin would have left Zanzibar by the end of April, 1964.

Merger of National Cadet Corps with N.C.C. Rifles

*1210. Shri D. C. Sharma: Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether the National Cadet Corps and the N.C.C. Rifles have been or are being merged; and
 - (b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Merger of the existing N.C.C. Senior Division, Infantry Units and N.C.C. (Rifles) Battalions (Boys)

and Girls Units and their re-organisation on a uniform pattern, was sanctioned on the 2nd April, 1964.

(b) The Scheme was sanctioned in response to persistent request from educational authorities and State Governments for raising the standard of N.C.C. (Rifles) and to remove disparities between the existing N.C.C. Senior Division and the N.C.C. (Rifles) in the matter of training of cadets and pay and allowances of N.C.C. Officers. Need for economy in the matter of provision of equipment, instructional staff and also for improvement of Command and Control of Units was kept in view while preparing the Reorganisation Scheme.

सामूहिक सम्पर्क

२५००. ्रश्चीसिद्धेश्वर प्रसाद : श्चीवी० चं० शर्माः

क्या सूचना श्रीर प्रसारण मंत्री १७ फरवरी, १६६४ के श्रतारांकित प्रश्न संख्या २६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सामूहिक सम्पर्क (कम्यू-निकेशन) के उच्च अध्ययन के केन्द्र की स्थापना के लिए क्या फोर्ड फाउंडेशन टीम के विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार करके कोई भन्तिम निर्णय कर लिया है:
 - (ख) यदि हां, तो वह क्या है; भ्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) से (ग). प्रस्तावित सामूहिक सम्पर्क केन्द्र की स्थापना पर खर्च और सामान, इत्यादि की आवश्यकताओं का ध्रनुमान लगाने के लिए एक विभागीय समिति स्थापित की गई थी। समिति की रिपोर्ट ग्रभी हाल ही में मिली है और शीघ्र ही उस पर विचार किया जायेगा।

एशियाई प्रसारक संघ

Written Answers

२५०१. श्री सिढेश्वर प्रसाद : क्या सूचना श्रीर प्रसारण मंत्री १७ फरवरी, १६६४ के श्रतारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या श्राकाशवाणी को एशियाई सारक संघ का सदस्य बनाने के सम्बन्ध में होई निर्णय कर लिया गया है; श्रीर
- (ख) षदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) जी, हां। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि श्राकाशवाणी की एशियाई प्रसारण संघ का पूरा सदस्य बनना चाहिए।

(ख) सदस्यता की प्रमुख बातों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या प्लटो—२७८३।६४)

विदेशों को भेज गये भारतीय शिष्टमंडल

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : २५०२. श्री प्र० चं० वरूप्रा : श्री पॅ० वॅकटसुब्वथ्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १६६४ से अब तक पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कितने शिष्ट मंडल विदेशों में भेजे गये, वे किन किन देशों में और कब भेजे गये ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहर): प्रश्न में जिस उद्देश्य का उल्लेख है, उसके लिए कोई सरकारी शिष्टमंडल बाहर नहीं भेजा गया। ऐसा समझा जाता है कि कुछ कोग पश्चिम एशिया और उत्तर श्रफ़ीका के देशों का दौरा कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जायगी और बाद में सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

सूचना भ्रौर प्रसारण मंत्रालय में बचत के उपाय

२५०३.∫श्रीम० ला० द्विबेदीः सावित्री निगमः

क्या **सूचना भीर प्रसारण मं**त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) श्राकाशवाणी श्रोर प्रेस सूचना विभाग में श्रापात काल के कारण कितने कितने वेतन वाले कुल कितने वार्षिक व्यय वाले पद समाप्त किये गये;
- (ख) क्या इन विभागों में कोई नये पद बनाये गये हैं और यदि हां, तो कितने पद बनाये गये हैं और उनके वेतन मान क्या हैं और उन पर कुल कितना वार्षिक व्यय होगा ; और
- (ग) पुराने पदों को समाप्त करने श्रौर नये पदों को बनाने के फलस्वरूप वास्तव में कितनी बचत हुई या चाटा हुग्रा ?

ससद्-कार्यं मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) ब्राकाशवाणी के बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है [पुस्तकालय रें रखा गया देखिये संख्या एल-दी-२७८४।६४]। पत्र सूचना कार्यालय में श्रापात काल के कारण कोई पद समाप्त नहीं किया गया।

- (ख) जी, हां; एक ग्रीर विवरण सभा पटल पर रखा गया है [पुस्तकासय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२७=४।६४]।
- (ग) पुराने पदों को समाप्त करने ग्रीर नए पदों की स्थापना के फलस्वरूप, वार्षिक व्यय में ६,१४,१४६ रुपये की वृद्धि हो गई है ।

Indians in Nairobi

2504. Shri Maheswar Naik: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether his attention has been drawn to the reports of robberies with violence committed against the residents of Indian origin in the city of Nairobi; and
- (b) if so, the steps taken or proposed to be taken in the matter?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):

(a) and (b). Government have seen press reports of incidents of robberies etc. in Nairobi, from time time the However, they have not been directed exclusively at persons of Indian origin.

The Government of Kenya are aware of the situation and have taken strong action to deal with such law-less elements.

Reservists in 505 EME Workshop, Delhi

2505, Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Defeace be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that almost all the reservists in the 505 Central EME Workshop, Delhi Centt. were recalled for active duty during the emergency in October. 1962:
- (b) if so, whether the individuals concerned suffered any financial loss and recovery was also made by Government for rations and uniforms supplied to them; and
- (c) the steps proposed to be taken to compensate the loss and also to refund the amount recovered from them?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) 62 reservists who were serving as Civilians in 505 Central EME Workshop, Delhi Cantral EME workshop, Delhi Cantral emergency and posted to various arms/services. Of these 17

were serving in 505 Central Workshops on 1st March, 1963.

(b) and (c). Reservists who are recalled for active service are entitled to draw either civil rates of pay and allowances or military rates of pay and allowances, whichever are more favourable. Those reservists who draw military rates of pay and allowances are entitled to free rations, while, in the case of those who draw civil rates of pay and allowances, a deduction of Rs. 25 p.m. is made on account of rations supplied to them. The civil rates of pay and allowances are considered to be more favourable if they are at least Rs. 25 more than the military rates of pay and alowances.

So far as clothing items of reservists are concerned the Kit items are withdrawn and stored in regimental centres at the time of transfer to reserve. On recall to colour service, the items are issued without any cost to the individuals. In cases in which the reservists were allowed to take Kit items with them on completion of final reservists training, in certain cases they were not able to bring back such items on recall to service. In such cases new sets are reissued at a nominal cost of 10 per cent of the special recovery rates.

The question of reservists suffering any financial loss when recalled to service and consequently, the question of compensating them, does not, therefore, arise.

Tuskar Project

2506. Shri Ramachandra Ulaka: Shri Dhuleshwar Meena; Shri D. D. Mantri:

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 125 on the 17th February, 1964 and state the latest progress made in regard to the investigation in respect of allegations of corruption against certain officers engaged in Tuskar Project at Dibrugarh (Assam)?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Three cases have been taken up for investigation after examination of allegations against officers at Dibrugarh. Investigation in respect of one has been completed and the final report of S.P.E. is awaited. The enquiries in respect of another are expected to be completed by the end of this month. Investigation is in progress in the third case.

"Combat Development" in Army Headquarters

2507. Shri Sham Lai Saraf: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether a new Directorate of 'Combat Development' has been created in the Army, Headquarters; and
- (b) if so the work being entrusted to this Directorate, both at the Headquarters and in the Field?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. R. Chavan): (a) Yes, Sir.

- (b) This Directorate will have the following main functions:-
 - (i) To consider and formulate tactical concepts in the light of our own and possible enemy weapon development.
 - (ii) To indicate how organisations and material should be developed to meet the changing tactical concepts.
 - (iii) To arrange trials and experiments in existing institutions and experiemental formations to test out the combat development concepts as are approved.

S. C. and S. T. in Ministry of Defence

2508. Shri Heda: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Home Affairs issued orders in 1959-60 for treating Scheduled Caste Scheduled Tribe employees who are confirmed, senior to other temporary|quasi-permanent employees;

- (b) whether his Ministry has implemented these instructions and if so, to what extent; and
 - (c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) The instructions on the subject were issued by the Ministry of Home Affairs in April, 1961.

- (b) These instructions have been fully implemented in so far as the Ministry of Defence Secretariat and the Armed Forces Headquarters are concerned, but have not yet been extended to the civilians working in the lower formations.
- (c) The instructions referred to. above were in clarification of the general orders issued in 1959 regarding the principles to be observed in determining the seniority of The question of ployees. applying these orders to lower formations being examined in the light of circumstances which are peculiar Defence Establishments.

Ambala and Ferozepur Cantonment Boards

2509. Shri A. N. Vidyalankar: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that conciliation proceedings had taken place in the dispute between the employees of the Ambala and Ferozepur Cantonment Boards and the Board Administration long ago and the Conciliation Officer had submitted failure report:
- (b) when Government received the Report of the conciliation officer; and
- (c) the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) On 24th April, 1962 and 22nd April. 1963 respectively.

(c) Government's decision on the Report relating to Ambala Cantonment Board that the dispute did not merit adjudication was communicated to the Ambala Cantonment Board Employees Association in September 1962. Subsequently, representations were received from the All India Cantonment Board Employees Federation requesting for reference of certain demands to adjudication. The matter is under examination by Government.

Failure of Conciliation report of the Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur in the case of Ferozepur Cantonment Board is still under consideration of Government.

A.O.C.

2510. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that several representations have been received from the civilians in the Army Ordnance Corps regarding their service conditions;
 - (b) if so, the nature thereof;
- (c) whether Government propose to appoint an impartial high-power Committee to inquire into the organisational set-up and rank structure of the Army Ordnance Corps, and rationalize the same in order to afford equal opportunities to both military; and civilian personnel; and
 - (d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). A few representations have been received from civilians employed in the Army Ordnance Corps regarding their service conditions. The gist of the representation is briefly given below:—

 (i) betterment of career prospects, in that change in the ratio of UDCs: LDCs. Clerks: Head Clerks, Improvement of the existing ratio between

- the various grades of Storekeepers and also creation of Class I posts.
- (ii) revision of the existing scale of pay of Class II posts.
- (iii) increase in promotional avenues to Gazetted ranks.
- (iv) provision of residential accommodation.
- (c) and (d). These questions are already under examination and there is no proposal to constitute highpower Committee to inquire into these matters.

Ordnance Officers for Border Roads Organisation

2511. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a majority of the officiating Ordnance Officers (Civilian) who have been assigned to the Border Roads Organisation are in the age group of 48—54 years;
- (b) if so, the criteria for such selection;
- (c) whether it has been suggested to Government that in view of the difficult terrain of the area, younger military officers recruited and trained for active service, should be posted to Border Roads Organisation; and
 - (d) if so, the action taken thereon?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir; of the 4 Ordnance Officers (Civilian) on deputation to the Border Roads Organisation, only one, who is working in the Director General's Office, New Delhi, is in the age group of 48—54 years.

- (b) Willingness to serve in that Organisation on the deputation terms offered, physical fitness and satisfactory service record were the criteria for the selection.
 - (c) Yes, Sir.

(d) The matter is under consideration of the Government.

Written Answers

Second Wage Board for Cement Industry

- 2512, Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
- (a) whether the Indian National Cement Workers' Federation has urged Government to appoint a second wage board for the cement industry; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): (a) Yes.

(b) The matter is being considered.

Radio Sets for Punjab

2513. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

- (a) the number of radio sets allotted during 1963-64 for supply in rural areas of Punjab; and
- (b) the total number of radio sets proposed to be supplied during 1964-65 to that State?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):
(a) 2,500.

(b) The matter is under consideration.

Promotion of Assistants in AFHQ

- 2514. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Defence be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that a panel of Assistants for promotion to the grade of Superintendent in the AFHQ was drawn up in 1963;
- (b) whether it is also a fact that the aforesaid panel was drawn up in accordance with the well-established conventions and principles; and

(c) if so, when the list of promotees will be published?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes. Sir.

- (b) The panel was drawn up in accordance with the principles laid down by Government from time to time for filling selection posts.
- (c) Promotions from the panel are made and published as and whem vacancies become available in the grade of Superintendent.

Nationalisation of Shops in Burma

2515. Shri Ramanathan Chettiar: Will the Prime Minister be pleased to to state the number of Indian shops with a capital of Rs. 10,000 and above, which have been nationalised by the Government of Burma recently?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): The number of shops belonging to Indians nationalised in Burma is estimated at about 2500. It is not possible to say now how many of them have a capital of Rs. 10,000 and above.

भविष्य निधि योजना

२५१६. श्री हुकम चन्दः क्या श्रम शौर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा क्पेंगे कि :

- (क) क्या मरकार को मजदूर संस्थाओं की ब्रोर से यह मांग प्राप्त हुई है कि भविष्य निधि योजना उन उद्योगों तथा व्यापार प्रतिष्ठानों पर भी लाग की जाये जहां कर्मनारियों की संख्या २० से ब्रधिक न हो ; और
- (ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम श्रीर रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चि० रा० पट्टामि-रामन्) : (क) जी हां । (ख) यह निश्चय किया गया है कि कमंचारी भविष्य निधि श्रिधिनियम, १६५२ को इस समय छं.टे प्रतिष्ठानों पर, जिनमें २० से कम व्यक्ति काम करते हैं, लागू नहीं किया जाना चाहिए।

Radiation Genetics Project

2517. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether any experiments have been conducted by the radiation genetics project of Osmania University, Hyderabad; and
 - (b) if so, the details thereof?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):
(a) Yes. The Department of Atomic Energy is financing the research project entitled "Induction of translocations in spermatogonia of mice by irradiation and genetic recovery in spermatoza of drosphilia", briefly known as the Radiation Genetics Project at Osmania University, Hyderabad.

(b) A brief note explaining the project is as under:

Note

It is well recognized that exposure of organisms to ionizing radiations, even at low levels, can result in genetic damage which could be propagated in further generations. The Radiation Genetics Project at the Osmania University, Hyderabad, supported by research grants from the Department of Atomic Energy, is engaged in the study of these problems. The investigator-in-charge has selected two organisms for these studies, viz., (i) Drosphila Melanogaster commonly known as the Fruit-fly, (ii) mice.

The fruit fly has been widely used for genetic work since the genetic constitutions of these flies are well worked out and more clearly understood. Thus a wide variety of flies with different hereditary characteristics are available for precise studies of the type of damage. The work carried out so far with x-rays, gamma rays and neutrons largely confirmed the findings of other workers in this field. Some experiments have been performed introducing certain factors like effects in the absence of oxygen and rapid spinning of centrifugation to obtain information on the role of environmental changes.

A similar study with male mice hasbeen carried out to determine the sensitivity to genetic damage of various cells which ultimately go toform the sperms. These studies have been confirmatory of similar work by other workers.

The work on the Project was started in September 1961, and the following grants have been sanctioned by the Department of Atomic Energy during the last three years:

1961-62	Rs.	31,300
1962-63	Rs.	15,964
1963-64	Rs.	17,187
Total	Rs.	64,451

Office Hours in Armed Forces Headquarters

Shri Bade:
2518 Shri Hukam Chand
Kachhavaiya:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is a discrimination in the office working hours of the three wings of the Armed Forces Headquarters, New Delhi;
- (b) why the staff working in the Air Headquarters is required to put in about three hours more per week than their counterparts in the Army and Naval Headquarters;

- (c) whether Government have received any representation from the staff in this behalf; and
- (d) if so, action taken in the mattter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). It is true that the working hours observed by the three Service Headquarters at New Delhi are not uniform, Each Service Headquarters works according to its own requirements as determined by the Chief of the Service concerned.

(c) and (d). No complaint has been received from the staff about the difference in the quantum of working hours. However, the Armed Forces Headquarters Association have made a request that the working hourse in the three Service Headquarters and Inter-Service Organisations should be uniform. This request is under examination.

डेपुटेशन पर बिदेश भेजे गये पदाधिकारी

्रिभी हुकम चन्द कछवाय : २४१६. े श्री यशपाल सिंह :

क्या श्रम ग्रीर रोजगार मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि । :

- (क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय कि अनेक पदाधिकारी विभिन्न योजनाओं तथा छत्त्रवृत्तियों के अन्तर्गत विदेश में गत पांच वर्गों में डेपुटेशन पर भेजे गये ;
- (ख) उत्में से कितने नौकरी में हैं भौर कितने सेवा-निवृत हो गए ; कितनों ने त्याग-पत्न दे दिया या भ्रन्य मंत्रालयों में उनका सवादला हो गया ;
- (ग) क्या यह एच है कि उन में से अधिशांश उन कामों पर नहीं लगाये गये हैं जिनके लिए उन्हें विदेश में प्रशिक्षण दिया गया था ; ग्रौर
- (घ) इन ग्रनियमिततात्रों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्रम श्रौर रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चि॰ रा॰ पट्टा-भिरामन्) : (क) जी हां ; विभिन्न योजनाग्रों श्रौर शिक्षा वृत्तियों के ग्रन्थांन प्रशिक्षण के लिये ७० पदाधिकारी डेपुटेशन पर विदेश भेजे गये ।

- (ख) ६६ नौकरी में हैं। एक पदाधि-कारी सेवा-निवत्त हो गया है और एक क लार गोल्ड माइनिंग अंडस्टेकिंग में प्रवर श्रम अफनर के रूप में अस्थायी डेप्युटेशन पर है।
- (ग) जी नहीं । श्रिश्चिमंत्रण पदाधि-कारी उन कामों पर लग ए गए हैं जिनके लिए उन्हें विदेश में प्रशिक्षण दिया गया था ।
 - (घ) प्रश्न नहीं उठना ।

Welfare of Jawans

2520. Shri A. V. Raghavan: Shri Pottekkatt:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether there i_S any proposal to appoint welfare officers to hear individual grievances of the Jawans; and
- (b) the procedure followed now to redress their grievances?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

- (b) Under existing arrangements, jawans can have their grievances heard and attended to as far as possible in the following ways:—
 - (i) They can represent their grievances to their Company Commanders through Platoon Commanders at any time. Such cases are referred to the authorities concerned for necessary action.
 - (ii) They have opportunity to express their grievances, if any, in the monthly Darbar

held by the Officer Commanding of the Unit in which they serve. The Officer Commanding tries to redress their grievances.

(iii) In some Units, certain days are fixed for submission of petitions and expressing grievances in person by jawans to the Officer Commanding of the Unit. These petitions are examined and forwarded to Departmental or Civil Authorities or the District Soldiers', Sailors' & Airmen's Board as the case may be for necessary action.

Parliamentary Proceedings on A.I.R.

2521. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 246 on the 17th February, 1964 and state:

(a) whether a copy also of that part of the script of each news bulletin broadcast on the A.I.R. relating to Parliamentary proceedings is being supplied to the Library of Parliament after broadcast; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): (a) No. Sir.

Parliamentary (b) proceedings form part of the total news bulletins broadcast by the All India Radio in different languages and their contents and duration vary from bulletin to bulletin in view of the relative importance of other items of news in a particular bulletin and the time at which it is broadcast. To make a comprehensive analysis of all the bulletins which are broadcast it different times of the day and night in different languages, and to take extracts therefrom, would mean an enormous amount of work necessitating considerable labour and additional staff. The advantage to be derived from 472 (Ai) LSD-3.

this analysis would also not be commensurate with the cost involved. Moreover, as a copy of the script of each broadcast on the A.I.R. relating to the review of Parliamentary proceeding is already available in the Parlament Library and any script of any particular news bulletin broadcast can also be called for from the A.I.R. when needed, no useful purpose would be served by placing a copy of the relevant extracts from the scripts of each of the news bulletins.

Pak Firing

Shri D. C. Sharma: Shri P. C. Borooah: Shri S. M. Banerjee: Shri Onkar Lal Berwa: Shri Gokaran Prasad: Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether the Pakistan Army opened intensive firing on an Indian border picket on the 9th April, 1964 near Betar Dam area in the Poonch area of Jammu resulting in injuries to one Indian border policenian; and
- (b) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Defence 'Shri Y. B. Chavan': (a) On the morning of 10th April, 1964 (not 9th April as mentioned in the question), our police patrol was fired at by Pakistan troops and civilians from an area about five miles north-west of Punch. Our troops returned fire. The exchange of fire lasted for about one and a half hours. In the exchange of fire, a sub-inspector of our police patrol was wounded Pakistani casualties are not known.

(b) A cease-fire violation complaint has been lodged with the U.N. Military Observers. Necessary precautionary steps have also been taken.

Refugees from East Pakistan

Shri P. C. Borooah: Shri D. C. Sharma:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether correctness or otherwise of the press reports that East Pakistan Government had sealed the entire border with West Bengal to stop emigration of minorities from there into India, has been ascertained by Government; and

(b) if so, the result thereof?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Energy Atomic (Shri **Jawaharlal** Nehru): (a) and (b). We enquired into the press reports and the factual information is that though the entire border has not been sealed, Pakistan athorities have considerably increased their vigilance especially in the Jessore-Khulna sector of their to prevent minorities from crossing the border into India. These measures are directed against n.inorities who are attempting to cross the border without valid travel documents.

Inspection of cease-fire Line in J & K

2524. Shri P. C. Borooah: Will the Prime Minister be pleased to state:

- (a) whether a high U.N. official recently visited the cease-fire line area in Jammu and Kashmir and met Indian officials:
 - (b) if so, the purpose of his visit;
- (c) whether the team of U.N. Observers in the cease-lire line area is to be further augmented in the light of his study; and
 - (d) if so, to what extent?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri **Jawaharlal** Nehru): (a) Yes, Sir, Dr. Ralph J. Bunche Under Secretary for Special Affairs, United Nations recently visited the cease-fire line area in Jammu and Kashmir and met Indian officials at New Delhi.

12954

(b) As stated in the United Nations press release, the purpose of his visit was as follows:

"The purpose of the visit is to to provide the Secretary-General with information about problems and needs of the missions (United Nations Military Observer group in India and Pakistan) and an appraisal of their functioning with particular reference to the means by which the headquarters may afford them more effective support. . . .

"Before proceeding to Kashmir. Bunche wil make one-day visits to Rawalpindi and Delhi to consult with appropriate authorities of the Governments of Pakistan and India on matters relating to the United Nations in Kashmir".

(c) and (d). Before leaving sub-continent, Dr. Bunche is reported to have stated that India and Pakistan wanted the cease-fire line not only to be maintained but also to be strengthened and that he would recommend to the Secretary-General strengthening of the Observers' team both in numbers and equipment.

C.G.H. Scheme for Defence **Employees**

2525. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Central Government Health Scheme has not yet been applied to the civilian Defence employees working and residing in the Delhi Cantt. area; and
- (b) if so, how long it will take to extend this scheme for the benefit of these employees?

The Minister of Defence (Shrl Y. B. Chavan): (a) and (b). The Central Government Health Scheme has not yet been extended to this category of civilian Defence Employees. The extension of the Scheme is the responsibility of the Ministry of Health and measures in this regard are being considered in consultation with that Ministry. It is not possible to indicate the time by which the Scheme will be extended to that area.

विल्ली के भट्टा यजदूरों की मांगें श्री हुकम चन्द कछवाय : २५२६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री बड़े :

क्या **श्रम ग्रोर रोजगार** मंत्री यह बताने की करा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली के भट्टा मजदूरों ने केन्द्रीय सरकार के पास श्रपना वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन भेजा है श्रीर यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि यदि उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो वे हड़ताल कर देंगे इन आशय का भी सरकार के पास कोई पत्न आया है ; स्रोर
- (ग) क्या सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय करने वाली हैं।

श्रम भीर रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) भारतीय रिपब्लिकन पथेरा यूनियन, दिल्ली, हारा दिल्ली प्रशासन को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें अन्य वातों के साथ साथ ४ रू० प्रति हजार ईट की मजूरी को बढ़ा कर ४ रू० प्रति हजार ईट करने और भट्टा मालिकों हारा प्रति हजार ३० ईटें काटने की प्रया को समाप्त करने की मांग की गई है ।

(खा) जी नहीं।

 (ग) दिल्ली प्रशासन का समझौता संगठन इस सम्बन्ध में समझौता कराने का प्रयत्न कर रहा है ।

ग्रमरीका से ग्रतिस्वन विमान

२५२७. श्री ग्रोंकार लाल बेरवा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि ग्रमरीका ने भारत को अतिस्वन विमान देना स्वीक∵र किया है ; और
- (ख) यदि हांती कथ तक और थे किन शर्तीपर दिये जारहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राश्र चल्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रम्बाला के पास विमान दुर्घटना

२५२८ श्री ग्रॉकार साल बेरवा : वस्य प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की बृत्या करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि १५ अप्रैल, १९६४ को श्रम्बाला के पास हुई विमान दुर्घटना में फ्लाइंग श्राफिसर एम० जे० कमिसरियट की मृत्यु हो गई ; और
- (ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच करने के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी की आजा दे दी गई है । दुर्घटना का कारण कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जात हो सकेगा ।

English News Readers in A.I.R., Delhi

2529. Shrimati Gayatri Devi: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state.

(a) the number of English Newsreaders employed by the Delhi Station of All India Radio; and

(b) the emoluments and grades of the above and the basis of their salaries, i.e., ad-hoc or otherwise?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): (a) English News-readers are not employed by the Delhi Station but by the

Calling Attention to 12958 Matter of Urgent Public Importance

News Services Division of the All India Radio. The present number English News-readers is five.

(b) There are the following categories of News-readers with ranges shown against each :--

Category Fee Ranges News Reader (Junior) Rs. 250-500 News reader (Senior) Rs. 45 -800

News-readers are employed on Staff Artist contract for specific periods. Their initial fee within the ranges mentioned above is fixed after taking into account their qualifications and suitability for the job. They are allowed ad hoc raise in fee at the time their contract is renewed. The size of the increment depends upon whether a staff artist's performance during the period of the previous contract is adjudged to be outstanding, very or good.

पाक ब्रिचिकृत काश्मीर के मुफ्ती का मक्का में दिया गया कथित वक्तव्य

२५३०. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या प्रवान मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

- (क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार श्रीर दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादकीय लेख की ग्रोर दिलाया गया है जिनमें यह कहा गया है कि काश्मीर के तथाकथित बड़े मफ्ती ने मक्का में नावाज पढ़ाते समय काश्मीर को शीघ्र मक्त कराने की अपील की :
- (ख) क्या सरकार ने उस देश को विरोधपत भेजा है जो धार्मिक स्थानों को भारत-विरोधी प्रचार के काम में लाने की श्रनमति देरहा है ; श्रीर
- (ग) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर प्राप्त हम्रा ?

प्रशन मंत्री, वंदेशिक कार्य मंत्री तथा श्रणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं जिनके अनुसार मीर के मोहम्मद यूसुफ शःह ने पवित्र काबा में काश्मीरियों की एड सना में ये शब्द कहे: "इंशाग्रल्लाह,

म्राप जिस वक्त फतह पाने की उम्मीद रखते हैं, उससे भी पहले ग्रापकी जीत होगी।"

(ख) ग्रीर (ग). ग्रस्पष्ट समाचारों की वजह से सरकार ने इस मामले को सजदी अरव की सरकार के सामने नहीं उठाया है।

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

FIRING BY NAGA HOSTILES ON KOHIMA Town

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Sir, I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"Firing by Naga hostiles on Kohima town on the 16th April 1964".

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): At about 7-30 p.m. on the 16th April, 1964 about 150 Naga hostiles, using stenguns and rifles etc. opened fire on Kohima town from three directions. The firing continued till about 8-30 P.M. Security forces rushed armoured cars to the spot. The hostiles again opened fire at about 11-30 P.M. and at 4-30 A.M. Fire was returned on both the occasions and the hostiles made their escape. Three villagers of Kohima were killed while 17 sustained injuries.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know what accounts for such demoralisation and ineffectiveness of our forces even when the Nagas made such a confrontation-we can understand their challenge-but they ran away without any fear of action? May I know what are our Government's to the Administration instructions there for dealing with the Naga rebels and what steps are being taken to create confidence in the people's minds?

Shrimati Lakshmi Menon: The Government's instructions are that the hostiles should be dealt with properly. Here, you find that they came in large numbers and we fired back and they returned.

Shri Harish Chandra Mathur: It was a confrontation. May I know how many Naga rebels were killed? Why could they not be pursued, and what is the impression that is created in the minds of the people when there is such a confrontation? You say there are dense forests and so you cannot deal with them, but they come and challenge and then go away without fear of action; how does it happen? How is it that you are so ineffective?

Shrimati Lakshmi Menon: I have stated that three villagers were killed and 17 sustained injuries.

Mr. Speaker: They were our people: the question is whether any of the hostiles were killed.

Shrimati Lakshmi Menon: I have no information about the hostiles having been killed.

Shri Hem Barua (Gauhati): Now that the violent activities of Naga hostiles are intensified with arms from Pakistan, may I know whether Government asked the Baptist sion, sponsoring the Peace Brigade with Rev. Michael Scott in it, that there should be a sort of cease fire on the part of the Naga hostiles so that the negotiations might proceed in an atmosphere of understanding because I think that the negotiations for peaceful co-operation and the violent activities do not go hand in hand?

Shrimati Lakshmi Menon: That is exactly the purpose for which the peace Mission is touring in Nagaland.

Mr. Speaker: The question is whe ther the Government have told them that there ought to be a cease fire till these negotiations are complete.

Shrimati Lakshmi Menon: It is for the Nagaland Administration to tell them. Shri Hem Barua: When the Nagaland Administration agreed to this proposal of this Baptist mission, it consulted the Indian Government and it is in the full knowledge of the Indian Government that they are operating. Therefore, I just wanted to know, because you cannot say that there should be negotiations for peaceful cooperation and at the same time the Naga hostiles firing on you.

Mr. Speaker: I follow what he wanted to know. That question is very clear.

Shri Hem Barua: It is clear to you, but not to them, Sir. That is the trouble.

Shrimati Lakshmi Menon: The Nagaland Administration has already sent an appeal to the hostiles that there should be cease-fire.

Mr. Speaker. The objective of the question is this. When we agreed to have Baptist intervention and there ought to be talks on this settlement, whether we had asked those people—the missionaries or those who were coming in as intermediaries—that at least for the period during which negotiations are carried on, there ought to be cease-fire.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): That is presumed; it is obvious.

Mr. Speaker: He puts a definite question whether positively we have put that suggestion across to them.

Shri Jawaharlal Nehru: The Nagaland Administration have done so. We, the Government of India, have not done so, because we do not come into the picture.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshan-gabad): The Prime Minister has said that the Nagaland Administration deals with the matter. The security and defence of India, with which the cease-fire is bound up, is the responsibility of the Central Government and not of the Nagaland Government.

Mr. Speaker: He says that that Administration has put it across them.

Calling

Shri Hari Vishnu Kamath: On behalf of the Central Government?

Mr. Speaker: Yes.

Shri Hem Barua: But where is the cease-fire?

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): On a point of order, Sir. "Ceasefire" is not an expression to be used with regard to people who are hostile within our own territory.

The Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs (Shri S. C. Jamir): The missionaries who are working for peace have made an appeal to the hostiles to cease firing for three months and we are waiting for the reply.

Shri Hem Barua: On a point of order, Sir. The Law Minister has taken objection to the use of the word "cease-fire". But here the Government have asked a foreigner to come and work for peace in a part of our country, to negotiate with the hostiles.

Mr. Speaker: What is the point of order?

Shri Hem Barua: If you can invite the services of a foreigner, what is the harm if I use the word "ceasefire"?

Speaker: The Parliamentary Secretary has used the correct expression, namely, that they have been asked to cease the firing.

Shri Hari Vishnu Kamath: Tweedledum and tweedledee!

Shri Hem Barua: There is no difference between the two.

श्री बागड़ी (हिसार) : ग्रध्यक्ष महोदय, इसका हिन्दों में जरा तर्जुमा कर के पढ़वा दिया जाय ।

श्रष्टयक्ष महोदय : यह मुश्किल होगा । इसके लिए माननीय सदस्य थोड़े दिन मोर इतकार कर कें।

श्री बागडी : बात यह है कि हर हिन्दी के सवाल का अंग्रेजी में तर्जमा होता है तो इसी तरह संग्रंगेजी का . . .

Attention to Matter

of Urgent Public Importance

ग्रह्मक महोदय : ग्रमी इंतजार करें। श्रगली दफ़ा से साइमलटेनियस टान्सलेशन का इन्तजाम होने जा रहा है। ग्रभी यदि माननीय सदस्य को कोई सबाल पूछना हो तो वे पूछ

श्री बागडी : मझे पहले हिन्दी में समझा तो दिया जाय तब मैं श्रागे कोई सवाल कर सकता हं।

म्राच्यक्ष महोदय : ग्रगर माननीय सदस्य कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें।

श्री बागडी : मैं सवाल क्या करूं जब तक कि मुझे समझाया न जाय ?

म्र**ध्यक्ष महोदय**ः हर एक चीज का तर्ज मा मैंने पहले कहा हमा है, हाउस की एप्रवल है और हम उम्मीद रख रहे हैं कि अगले सेशन तक साइमलटेनियस टान्सलेशन करने की व्यवस्था चालु हो जायेगी लेकिन जब तक वह नहीं होती है तब तक हमें इसी तरीके से गुजारा करना होगा । माननीय सदस्य जो कुछ कहा गया है उसे ग्रन्छी तरह समझ सकते हैं इसलिए ग्रगर उन्हें कोई सवाल करनाहो तो वेकर लें।

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): May we know what is going on between Mr. Bagri and you, Sir?

श्री बागडी : ग्रध्यक्ष महोदय, है तो यह मेरे साथ ज्यादती . . .

एक माननीय सदस्य : श्री बागड़ी ग्रंग्रेजी समझते हैं।

भी बागड़ी: अब वह श्राधा गलत होगा भीर भावा सही होगा।

Urgent Public Importance

ग्रध्यक्ष महोदय: ग्राप सवाल करें।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, कोहोमा पर जवाब देते हुए मंत्रो महोदय ने कहा है कि दो दक्षे हमला हुआ है। उस के अन्दर मैं जानना चाहंगा कि एक दक्ष पहले हमला हुआ और दूसरो दक्षे हमला हुआ, जो तीन व्यक्तियों को मृत्यु हुई है, वह पहले हमले में हुई है या दूसरे हमले में हुई है और प्रगर ये मृत्युयें

श्रष्टयक्ष महोदय: माननोय सदस्य श्रव बैठ जायों।

श्री बागड़ी: मेरा सवाल तो पूरा हुन्ना नहीं है। ग्रगर ये मृत्युयें दूसरे हमले में हुई हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया आयेगा, जिनके उत्पर वहां का बचाव करने की जिम्मेदारी हैं?

Mr. Speaker: Three persons were killed. He wants to know whether they were killed in the first instance or in the second instance.

Shrimati Lakshmi Menon: I cannot say.

Shri S. C. Jamir: They were killed in the course of the firing which took place in the night and we discovered in the morning that they were dead. It is very difficult to say whether it happened in the first instance, the second instance or in the third instance.

Mr. Speaker: He further enqpires whether any action has been taken against the persons if they were really found negligent in their duties when this took place.

Shri S. C. Jamir: No one was found negligent in this matter, because it was in the night that the firing took place from the outskirts of Kohima. It is very difficult to say.

श्री बागड़ी: कोहीमा मेरा देखा हुमा है। यह तो कोई जब!ब ही नहीं है। म्राच्यक्त महोदय: जवाब तो हो गया है। म्रब माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री बागड़ी : ग्राप जरा मुझे समझा दोजिये कि क्या जवाब दिया गया है।

श्रध्यक्ष महोवय : उन्होंने कहा है कि रात को वं लोग श्राये श्रीर सुबह को तीन श्रादमी मरे हुए पाये गये । इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मोतें पहले हमले मे हुई या दूसरे में, क्योंकि सुबह देखा गया कि श्रादमी मरे हुए थे ।

श्री बागड़ी : क्या हमारी तरफ़ से दोनों दफा गोली नहीं चलाई गईं? क्या उन लोगों का पीछा किया गया या हमारे श्रादमी घरों में छिप कर बैंठ रहे?

श्री **ग्रोंकार सास बेरवा** (कोटा) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Hem Barua: May I seek one information from you.

Mr. Speaker: No, Sir. He will kindly resume his seat. There is another hon. Member who wants to raise a point of order.

श्री धोंकार लाल बेरवा: श्रीमन्, मैं ने एक स्थगन-प्रस्ताव पेश किया था और वह इस बारे में था कि जैसे पहले सियालदह और खुलना में हिन्दू लड़कियों के साथ गाड़ी में बलात्कार किया गया, जिस के कारण वहां पर हड़ताल हो गई और गाड़ी उधर की उधर रोक दो गई, उसी तरह कल काश्मीर में एक हिन्दू लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उस के भाई को मारते मारते मुख्ति कर दिया गया और कुछ लोग लड़की को पकड़ कर ले गये। यह सारा उत्पात शेख प्रन्दुत्सा के बयानों के कारण हो रहा है।

ग्रध्यक्ष महोदय : श्रार्डर, ग्रार्डर ।

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : यह केवल काश्मीर का अश्न नहीं है, यह सारे देश का [श्री स्रोंकार लाल बेरवा]

प्रश्न है। जगतक शेंख अब्दुल्ला को पकड़ कर बन्द नहीं किया जायेगा, स्थिति काबू में नहीं आने वाली है।

Mr. Speaker: He will kindly resume his seat. He knows it very well that I do not answer those questions here in the House.

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : सारे उपद्रव इसी क्वेस्टियन को लेकर होते हैं ।

श्रघ्यक्ष महोदय: अगर इसी का सवाल है, तो यह तो आर्डर पेपर में आया हुआ था, इस लिये अगर माननीय सदस्य ने आज दिया, तो उन का नाम इस में नहीं आ सकता था।

श्री ग्रॉकार लाल बेरवा : क्यों ?

Mr. Speaker: Order, order. Would he not listen to me now?

ग्रगर इसी के सम्बन्ध में है, तो माननीय सदस्य का नाम इस में नहीं ग्रा सकता था, क्योंकि वह ग्राइंर पेपर में ग्रा चुका है। ग्रगर इस से ग्रलाहिदा कोई दूसरा सवाल है, तो माननीय सदस्य मुझ से पूछ सकते हैं कि वह क्यों नहीं ग्राया, क्यों नहीं मंजूर किया गया। लेकिन माननीय सदस्य यहां नहीं पूछ सकते हैं। मैंने यह बात हाउस में कई दफा कही है।

श्री श्रोंकार लाल बेरवा : श्राप मुझे तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन देश को तसल्ली नहीं दे सकते हैं। शेख श्रव्दुल्ला के भाषणों सं वहां पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है।

श्रष्टपक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । मान-नीय सदस्य श्रव बैठ जायें । मैंने इस हाउस में कार्यवाही चलानो है, बाहर देश के बारे में मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री श्रोंकार लाल बेरवा: इस घटना की जांच होनी चाहिये श्रीर शेख श्रव्हुल्ला के खिलाफ कार्यवाही कर के उस को फौरन बन्द कर दिया जाये। अगर इस तरह से हिन्दू लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो . .

Importance

श्रम्थक्ष महोदय: ध्राडर, ब्राडर। प्रगर माननीय सदस्य नहीं बैठेगे, तो मुझे ब्रौर कदम उठाना पड़ेगा।

श्री बड़ें (खारगोन) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि हम ने

श्रष्टियक्ष महोदय: मैंने कहा है कि स्रगर स्राप को तसल्ली नहीं हुई, तो स्राप स्राकर मुझ से पूछ सकते हैं।

श्री बड़ें: समय निकल जाने के बाद क्या लाभ होगा ?

श्रम्थक्ष महोदय : क्या मैं इस वक्त उस के बारे में बहस करूं। श्रगर मेरे पास तीस नोटिस श्रायें, तो क्या मैं उन सब के बारे में यहां बता सकता हूं ? माननीय सदस्य की इत्तिला दे दी गई है।

श्री भ्रोंकार लाल वेरवा : यह स्थगन प्रस्ताव था । कालिंग एटेन्शन नोटिस नहीं था ।

प्रध्यक्ष महोवय: अगर पार्टीज के लीडर अपने अपने मेम्बरों को काबू में नहीं रख सकते, तो मुझे उन को इंडिविडुअल तस्लीम कर के खुद एंक्शन लेना पड़ेगा। सुप्स के लीडर्ज पर यह भो जिम्मेदारी श्राती है कि वे अपने अपने मेम्बर्ज को डिसिप्लिन में रखें।

श्री हेम बरुग्रा।

Shri Hem Barua: Since the atmosphere is already surcharged with emotion, I do not want to raise my point of order.

Mr Speaker: That is good.

12968

PAPERS LAID ON THE TABLE CENTRAL GOVERNMENT CONVERSION LOANS

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): Sir, on behalf of Shri T. T. Krishnamachari, I beg to lay on the Table a statement indicating the result of the Central Government conversion loans floated in April, 1964. [Placed in Library. See No. LT-2781/

EMPLOYEES PROVIDENT FUNDS (EIGHTH AMENDMENT) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning) (Shri C. R. Pattabhi Ra-man): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Employees' Provident Funds (Eighth Amendment) Scheme, 1964 published in Notification No. G. S.R. 262 dated the 22nd February, 1964, under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952. [Placed in Library. See No. LT-2782/64].

ESTIMATES COMMITTEE

MINUTES OF SUB-COMMITTEE

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Minutes of the sittings of Sub-Committee of the Estimates Committee on Public Undertakings and Minutes of the Sitting of the Estimates Committee relating to the Fortynineth Report on the Ministry of International Trade-State Trading Corporation of India Limited New Delhi (Reports and Accounts).

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 97 the Rules Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1964, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st April, 1964".

DRUGS AND COSMETICS (AMEND-MENT) BILL

LAID ON THE TABLE AS PASSED BY *RAJYA SABHA*

Secretary: I lay on the Table of the House the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1964, as pased by the Rajya Sabha,

12.16, hrs.

APPROPRIATION (NO. 3) BILL

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Sir, on behalf of Shri T. T. Krishnamachari, I beg to move :-

"That the Bill to provide for the authorisation of approapriation moneys out of the Consolidated -Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1962, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration".

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1962, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.

[•]Moved with the recommendation of the President.

Mr. Speaker: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

'That clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

12.17 hrs.

(SEVENTEENTH CONSTITUTION BILL-Contd. AMENDMENT)

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Bibudhendra Misra on the 25th April, 1964, namely :-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration".

Shri Kashi Ram Gupta may continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): How much time is left?

Mr. Speaker: Out of 8 hours for general discussion, 2 hours and 35 minutes have been taken away and 5 hours and 25 minutes remain.

Shri Hari Vishnu Kamath: The whole day.

Mr. Speaker: A query has been made whether voting would take place today.

Shri Hari Vishnu Kamath: Tomorrow.

Mr. Speaker: I cannot give any undertaking. If it collapses, how can I postpone it? If there are hon, Members to speak, certainly it will take place tomorrow; but if there are no Members to speak on the Bill then certainly they ought to remain ready for that

(Seventeenth

Amendment) Bill

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): It is not likely to collapse. There are so many speakers

Mr. Speaker: Very well; then, I am not curtailing the time.

श्री काशी राम गुप्त (ग्रलवर): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं परसों बता रहा था कि आसाम का श्रधिकतम भिन-सीमा निर्धारण श्रधिनियम एक ऐसा अधिनियम है. जिस को सप्रीम कोट ने भी ठीक भाना है। प्रदेश सरकारों को चाहिये या कि वे म्राप्ते भाषते मधिनियम उसके मान-कल बनाती भीर इस प्रकार से नवें शिडयंब में उन काननों को लाने का प्रयत्न न किया जाता । माननीय सदस्य जिस जिस प्रदेश से आये हैं-- भीर जो कांग्रेस दल से सम्बन्धित हैं — उन का यह कर्त्तव्य था कि वह की सरकारों पर इस बारे में जोर डालते। किन्तू वे लोग ऐसा करते नहीं हैं ग्रौर यहां ग्रा कर प्रलाप करते हैं।

कांग्रेस दल से सम्बन्धित माननीय सदस्यों ने बार-बार इस बात को कहा है कि भमि की जो कोमत मिले, वह बाजार-दर पर मिलनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि भूमि-सूधार कानुन का मतलब ही यह है कि फालन जमीन गरीबों को दो जायेगी ग्रीर इस लिये ऐसी जमीन के लिये बाजार दर का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उन माननीय सदस्यों को यह चाहिये था कि योजना श्रायोग ने जो यह नीति श्रपनाई है कि किसी व्यक्ति के पास केबल उतनी जमीन रहे, जिस से ३६०० या ४००० रुपये की ग्रामदनी हो सके. उस में वे संशोधन कराते और भपनी ग्रशनी प्रदेश-सरकारों पर दबाव कि यह सोमा-निर्धारण टचित ग्रीर ठीक होना चाहिय ।

उसके बाद जो जमीन बचे उसको किन ब्राबारों पर ब्राप ले सकते हैं. क्या कीमत मिल सकती है भीर किन लोगों को दी जाए. इसके बारे में वह चर्चा कर सकते हैं। किन्तू ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। मुझे एक गांव की कहावत, एक गांव का उदाहरण याद आता है। हमारे गांव मे कहते हैं "ग्रवसर चुको डुमनो गावे ग्रास पाताल।" वहीं दशा इस कांग्रेस दल के लोगों की है। बास्तविकता को ग्राज ये देखते नहीं हैं। यदि मार्किट प्राइस लेने का हो प्रश्न है, बाजार दर लेने का हो प्रश्न है तो मैं नहीं समझता कि इन संशोधनों की कोई भी किसी प्रकार की ग्रावश्यकता है। इनकी ग्रावश्यकता है ही नहीं। वह सब कुछ तो लैंड एक्वि-जिशन एक्ट के तहत हो सकता है। फिरतो भमिहीनों को जभीन देने का प्रश्न भी पैदा नहीं होगा ।

यह भी कहा जाता है कि शहर भीर गावों के फर्क को मिटाया जाए। गरीब गांवों में भी रहते हैं और शहरों मे भारहते हैं। जाइस तरह की बात कहते हैं मेरा उनसे मतभेद है। मैं चाहला हं कि फर्क मिटाया जाए, उद्योगपतियों में, व्यापा-रियों में ग्रयवा जो किराये की ग्रामदनी करने बाले लोग हैं उनमें ग्रीर खेिहर लोगों मैं। इनमें जो फर्क है उसको मिटाया जाए । उस फर्क को मिटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने अब तक जो कुछ किया है, उसको मेरे साथी शायद नाकाफी मानते हैं भौर इसलिए शायद वे इसकी चर्चाभी करते हैं। यदि वास्तव में हमारे साथो इसको नाकाफो मानते हैं तो उनको जरूर सरकार पर दबाद डालना चाहिये।

कांग्रेस दल को नीति है भीर उसने घोषणा भी को है कि एक भीर तीस का अनुपात होना चाहिये भ्रामदनियों का । इसका अर्थ यह होता है कि कम से कम भ्रामदनी यदि साढे सात ग्राने रोज है तो प्रधिक से श्रधिक चौदह रुपये किसी व्यक्ति की हो सकतो है। इसका प्रयंहोता है कि एक महीने में ४२० रुपये से प्रश्चिक किसी एक व्यक्ति को श्रामदना नहीं हो सकता है। यदि एक कूटम्ब मे पांच शादमी हैं तो उस कूटम्ब को ग्रामदनी २१०० रुपये के करीब हो सकतो है, एक महीने में, इससे अधिक नहीं । यदि कांग्रेस को इस ध्येय को पूरा करना था तो उसको चाहिये था कि बहत सीधा सादा कानन बना देती कि किसी के पास भी शहरी सम्पत्ति जो है वह तोन लाख से ग्रधिक की न रहे। यदि ऐसा कर दिया जाए तो डैय हयटो, गिक्ट टैक्स, बैल्य टैक्स, इत्यादि के जितने झगड़े हैं वे सब समाप्त हो जायेंगे। उत्पादन कैसे बढ़ेगा, यह देखना इनका काम **है** 1

किन्तु वे कदम कहां से उठायें ? उनकी जिन्दगी, उनका चनाव, उनका सारा दारो-मदार ही रुपये बालों के उपर है। कम्पनी एक्ट जब स्राया था तो उस बक्त इन्होंने उसमें यह रखवाया कि राजनीतिक पार्टियों को कम्पनियां चन्दे दे सकती हैं भ्रौर करोड़ों के चन्दों से चनाव स्राज लड़े जाते हैं। इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज उठाया है। संतानम कमेटी जो बनी थी करण्यन को दूर करने के लिए उसकी रिपोर्ट की भी चर्चा हई है। उसमें यह कहा गया है कि ये चन्दे बन्द होने चाहियें। मैं चाहता हं कि वह दिन आए जब ये बन्द हों। ये यदि बन्द हो गए तो भ्रष्टाचार भो बन्द हो जाएगा भीर जब भ्रथ्टाचार बन्द हो जाएगा तो दूसरी मच्छी मच्छी बातें भी पैदा होंगी। कांग्रेस जन जबानी जमा खर्च करने में ही ये विखास करते हैं। इनका काम है करो कुछ ग्रीर कहो कुछ भीर ही। इसी की वजह से सारे झगड़े देश में मचे हुए हैं। यदि जो कुछ कहा जाता है उसके उपर ईमानदारी से ग्रमल किया जाए तो फिर कोई झगडा ही बाकी नहीं रह जायेगा। उसके करने के लिए सारे जीवन

12974

Constitution

में उमें परिवर्तन लाना होगा । श्राज तो यह लोग बड़े ग्राराम के साथ पैसे के बल पर विरोधी दलों का मकाबला कर लेते हैं लेकिन ितर शायद ऐसा सम्भव न हो । बड़े बड़े शोगों से जब तक चन्दा मिलता रहेगा तब तक ग्राप उन लोगों को सनाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं।

ग्रज्यक्ष महोदय, इनको स्पष्ट ग्रपने दिमाग में यह बात बिठानी है कि उत्पादन बढाने केहेनू कैसे लोगों की जरूरत है। एक तरफ कहा जाता है कि उत्पादन बढाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जरूरत है ग्रीर बहुत बड़े ग्रंशों में जरूरत है ग्रीर इसरी तरफ कहा जाता है कि हमें शहरी लोगों के बारे में सोचना चाहिये। पहला कदम भी इसके बारे में नहीं ग्राज जठाया जाता है। यदि हम चाहते हैं कि शहरों में लोगों को रहने के लिए भक्तान मिले, गरोबों को मकान मिलें तो हमें यह सोचना चाहिये कि किराये की ग्रामदनो पर लोग जिन्दा न रहें। इसको करने के लिये सरकार को निश्चित रूप से यह जो जमोनों को खरोद ग्रीर फरोब्त है इसको अपने हाथ में ले लेना वाहिये। श्रीर व्यक्तियगत रूप में इसको करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लोगों को सरकार की ग्रोर से मकान बनाने के लिए उचित मृत्य पर जमीन दी जानी चाहिये। यदि ऐता किया जाता है तो कम से कम इतनातो निश्चित हो हो जाता है कि एक ब।मारी शहरों से ब्राप मिटाने जा रहे हें। यदि आग किराये की पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो लोगों को श्रानको साफ बनला देना चाहिये कि श्रामदनी करने के लिए वे इस में रुखान लगायें। लेकिन हर वर्ग सरकार की नीति बदलती रहती है स्रोर फिर से वह ग्रपनी पूरानी नीति को लाना चाहती है। वही पूरानी नीति इस में लाना चाहती है। इन संशोधनों में र्दे नहीं समझता की नीतीयों का कोई

सीधा मतलब है। यदि मेरे साथी समझते हैं ग्राँर यदि वे हिम्मत करके सही काम करना चाहते हैं तो इस विल में जो संशोधन मैंने दिये हैं उनकी तत्फ ध्यान दें। वैसे ता इन संशोधनों पर जब समय श्राएगा मैं बोलुंगा। लेकिन उनको इन्हें पढ़ लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने इनको भी पढ़ लिया होगा । मेरे संशोधन बहत साफ हैं। जो भूमि दी जाए वह उन लंगों को दी जानी चाहिए जो लोग उस भूमि पर खेती करें और उन्फो ही उन जमीनों का मालिक बनाया जाना चाहिये। ये शब्द जब तक नहीं होंगे तब तक स्वतंत्र पार्टी का भ्रंदेशा है वह बना रहेगा भ्रौर कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है कि १२४ के १२४ एक्ट इस में शामिल कर लिये जायें। चाहे उनका जमीन के सुधार से कोई सम्बंध हो या नहीं, वह बनी होगी। तब तक यह जो षपला है यह चलता ही उहेगा। बात स्पष्ट होनी चाहिये। हमें क्या करना है यह हमें मालम होना चाहिये। सतरहवें संशोधन का सीघा सादा तात्पर्य यह होना चाहिये कि जिस किसी जमीन को भी एस्टेट की परिभाषा में लेने की बात हो वह उन लोगों को देने के लिए हो जिनके पास जमीन नहीं है और उन लोगों को जमीन का मालिक बना दिया जाए । न इसमें केई कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी का प्रश्न पैदा होता है ग्रीर न ही कोई ग्रीर प्रश्न पैदा होता है । इस प्रकार यदि सरकार नहीं करती है तो शंकाओं का पैदा होना स्वाभाविक हैं। मैंने एक प्रयत्न प्रवर समिति में किया है जिस में मैं नाकामयाव रहा। वह प्रयत्न मैं द्बारा करना चाहता हं। मेरा निवेदन है कि स्राप इस स्रोर ध्यान दें। नौवें शेडयुल में जो भी प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं और सरकार जो कूछ भी यहां रखवा रही है, वह केवल थे। ड़े समय के लिए हो श्रीर इस थोड़े समय में राज्य ग्रपने कानूनों को सही बना लें। मैं नहीं चाहता हुं कि राजनीतिक रूप में इस बिल को कोई देखे। हमें इस विल को इस दुष्टि से देखना चाहिये कि जो जमीन ली जाएगी उसको किस प्रकार से दिया जाएगा और जिन से जमीन जी जाएगी उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो, उनके साथ न्याय हो। प्रगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो उद्देश्य है वह सफल नहीं होगा।

मैं नहीं चाहता हूं कि इस संशोधन को राजनीतिक हथियार बनाया जाए और जो कमी है ईमानदारी से उसको मान करके उसको ठोक कर दिया जाए। इससे देश का हित होगा अन्यया अहित ही होगा।

कांग्रेस दल वालों से मैं कहना चाहता है कि इसमें जो ४४ एक्ट जा रहे हैं उनको वे पढ़ें, समझें ग्रौर देखें कि कहां कहां खराबी है। केवल यह न भान लें कि चंकि प्रवर समिति ने इसके। यहां रख दिया है, चंकि विधि मंत्री इसको यहां रख रहे हैं ग्रीर चंकि सारे के सारे नहीं रखे गये हैं, कुछ निकाल दिये गये हैं इस वास्ते ये सब ठीक हैं। उनको जहां जहां गलतियां मालुम दें, जहां जहां शंकायें मालुम दें, निर्भीक हो कर सदन के सामने रखें ग्रीर जो जो कमियां मालम पडती है, उनके ठीक करवाने की कोशिश करे। ग्रगर मार्किट प्राइस की ही मांग करते हैं तो उनको इसका कतई विरोध करना चाहिये क्योंकि उसकी मांग तो वे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत कर सकते हैं जो मेरी रिष्ट से बाजिब बात होगी। जो भी विचार विमर्श हो इसी ुष्टि से हा, यह मेरा निवेदन है।

Shri Daji (Indore): Mr. Speaker, Sir, we have before us this Bill, to amend the Constitution further. We support the Bill in its entirety. The first thing which I would like to submit before the House is this that in amending the Constitution, as we are doing under this Bill, no new principle is being enunciated. The principles have already been enunciated and accepted by this House and by the State Assemblies and have been embodied in the Constitution. It was

when those principles were being implemented that certain difficulties cropped up. Now, therefore, when we consider this Bill the only question germane to the discussion is whether we would like to correct the Constitution and the lacunae that were left or whether in the garb of correction we are smuggling some new principles. I say categorically that no new principle is being introduced. principle which has been accepted is the principle of land reforms. There has been a controversy raging on that principle. It may be different that works from this may not agree with the philosophy of land reforms. That may be there. But I submit that this particular Bill does not introduce even a new philosophy of land reforms but it only wants to plug loopholes that were discovered as a result of some rulings of the Supreme Court the High Courts. I heard with great attention the eloquent speech of my hon, friend from Chittoor, Despite his eloquence. I am constrained to remark that one cannot either agree with his arguments or with the general tenor of his speech. If I am permitted to say so, I would say that Mr. Ranga was labouring under what is called in logis a fallacy of argumentum ad absurdum. The falacy consists of first reducing the arguments to an absurd limit and then attacking that absurd limit, leaving aside the main argument. Mr. Ranga argued that if a Government came to power which prescribed only 1 acre as the ceiling what will happen? For that matter, he became eloquent and asked 'if only half an acre is fixed as the ceiling, such a legislation would be valid, and then what would happen'? My submission is that we cannot reduce the philosophy of the legislation for land reform to its absurd limit and say What will happen if only half an acre is laid down as the ceiling?' No sane Government and no sane party and no person with a sane philosophy would impose a limit of half an acre as land ceiling. Therefore, my hon. friend was ranting his vehemence that sort of possibility that in course of time in free India the peasant pro[Shri Daji]

12977

prietorship would be abolished altogether. And he pointed out that a free peasant was the pride of the country and he should be defended at all costs. We all agree to that proposition. No one is going to legislate for a ceiling of half an acre. So, my hon. friend Shri Ranga was ranting his anger only on a ghost of his own creation. Such a possibility does not exist. I do not know where from he got this absurd opinion on which he could base his entire opposition to the Constitution Amendment Bill. Even the Communist Party has not got a programme of prescribing half an acre as the ceiling. No sane man would prescribe any such ceiling, because the ceiling is not to be prescribed vindictively.

When we talk of land ceilings, we do not want to punish certain persons. It is only a question of social engineering. You may agree with that or you may not agree with that. But let not the argument be reduced to its absurd limit and let it not be said that a calamity will befall if half an acre is prescribed as the land ceiling, on that basis, and, therefore, this Bill is to be opposed. Such an argument does not hold water.

What then is the main point? The main point is that there is a trend of opinion in this country, unfortunately still strongly entrenched, and more unfortunately even entrenched in the ruling party itself, despite the Avadi resolution, despite the Nagpur resolution and despite their of socialism, that social engineering is bad.

My hon, friend Shri Ranga raised the question of productivity. He said that as a result of this kind of legislation, the productivity in agriculture would suffer. May I remind him that his very good friend, whom he the Members of his party often quote, Mr. Chester Bowles, who has no sympathy for communism and who has no sympathy for socialism, has recently written a book, which has been sent to all the Members of Parliamentit is a good book as far as it goes-in which he says that in Japan while it was under military occupation, it was only when the landed estates broken up and divided and parcelled out to the peasantry, that the Japanese agricultural production could look up? Even a man like Mr. Chester Bowles. who cannot even remotely be considered to be a socialist, advocates that in all backward and under-developcountries where vestiges feudalism still exist and where feudal system of land tenure with landlords in different forms still persists, a bold programme of land reform is the sine qua non for increase in agricultural production. have our differences of opinion regard to the ceiling that he would like, in regard to the methods he might advocate and so on, and we may not like them. But this concept is outmoded and it has been blown up that as a result of land reforms, the productivity of land will fall; that is not so.

In fact, I would submit that we this House are very anxious to give a fair deal to the peasant. We have often spoken from this side as well as from the other side of the House that we want to guarantee prices, we want to guarantee better marketing facilities to the agriculturists and so on. All this could have very little value to a peasant who has no land, to a peasant who tills another's land and who remains unemployed for almost one-third of the year. The biggest problem in agriculture today is the problem of under-employment. About 40 to 50 per cent of the peasantry have no stake in the land which they are made to till. Even according to the philosophy to which Shri Ranga subscribes and by which he stands, I must have some stake in my land in order that I can be made to till my land beter. Does my hon. friend want in the garb of free peasant-holders some big estate-holders, while the rest of the agricultural would work as labourers?

an ideal system of land retenue.
according to my hon. friend.? If
that be so, certainly, this Bill will
not accommodate that thought, and
on that score, of course, he has right
in critcising the Bill.

The Joint Committee has done good work and has given a great volume of evidence to us, which shows badly we have treated our agricultural tenants. For example, Khedut Sangh of Gujarat had given a very painful evidence, in which they had pointed out that even though the Act had been passed in 1950, and we were now in 1964, yet, as many as 24,000 applications of tenant proprietors were still pending in the courts of revenue officials for consideration and disposal. The Act had been passed by the erstwhile Bombay State 1950, and yet, the benefits have not accrued to the tenants even as late as 1964. This is how we have treated our agricultural workers, our peasants! We pass legislation, but we have not benefited them. Again and again, vested interests run to courts, pick up some hole, get a stay order, get the whole Act and then the whole process is set at nought.

Therefore, it is very necessary that we amend the Constitution to see that the land reform programme is impeded or hindered, because I make bold to say that the land reform programme and its speedy implementation is the first condition for the ushering in of a prosperous agricultural India. 80 per cent of our people live in villages. If we cannot give them a decent deal, all talk of introducing socialism in the economic sphere and bringing about a socialist pattern of society is only moonshine. against this background that we have to consider the amendment bofore us as well as the list of Acts which have been sought to be appended to schedule.

My submission is that it is not sufficient that we take over only the old taluqdari and zamindari estates. If under a ryotwari settlement, large tracts of land are owned by a proprietor, it is quite just that we break them up and distribute them to those who have lesser land or no land whatsoever. If the definition of 'estate' as given in the statute hinders this process, as has now been held by Supreme Court-we do not quarrel with it; we respect the judgment -if that is so, we have to amend it that this principle have enshrine in а series of social legislation measures throughout the country is implemented Therefore, I say without hindrance. this Bill does not introduce any new principle. It only wants to plug loophole discovered as a result of some judicial pronouncements.

Now, the main point, as I submitted, is that there is in the country a trend of opinion which is against land reform. They want only to use amendment as a plank to attack the entire programme of land reform, the entire programme of land ceilings. the entire concept of peasant proprietorship. Peasant proprietorship does not consist merely in some big peasants holding large tracts of Peasant proprietorship should this equitable and to the extent amendment helps to have a network of peasant proprietors, raising agricultural labourers to the level of peasant proprietors, it is a step the right direction and brings fruition and guarantees the rights of the farmers. The question is: who is a farmer? Do we consider as farmers only those who own large tracts land already under their proprietorship? Or do we want to raise status of the peasants, persons are working as labourers on land, to that of small peasants owning land on which they labour? If is the principle, then this amendment further protect only rights of the farmers and not away any right whatsoever, cularly with the amendment incorporated by the Joint Committee that upto the ceiling land will not be taken away without paying compensation at market value. If in spite of this any

[Shri Daji]

baseless fear which might have existed, still persists, it is because agricultural reforms are being sought to be negatived.

Constitution

I have no inhibitions about touching the Constitution. I agree Constitution is sacred. But it been given to us by the people οf India with a particular objective and if a particular article thereon requires to be amended for furthering that objective, for furthering the objecamendtive of progress, such an ment should be welcomed and should not make a fetish of constitutional amendments. I make bold to say that if India is to march forward to its goal of socialism, some more amendments may be required so that we may move without hindrance towards the new social engineering that we want to bring into effect in India.

I may point out that when this clause was debated in the Constituent Assembly, all these aspects were presented. It was drafted three times, bу sub-committee, then committee. All the aspects were consdered the opiand it was Shri Munshi even nion of that this particular clause of the constitution was not properly framed. But, may I remind the hon. Member from Chittoor that at that time, Shri Rajagopalachari, his present leader, is on record as having said that even proprietorship protection to should not be given, because with this protection it would be difficult to have any reforms in the country? It is now different. Now, Shri Rajagopalachari has completely changed his philosophy. It may be because of experience and the passing of age, or it may be that age has something to do with bringing conservation thought, but at that time it was very clear to the Constituent Assembly that the draft as approved by them would help the process of reforms and would not hinder it. Let us see if in practice we find that the constitutional provision is interpreted by the courts to mean that it is a hindrance to possible reform. We are not going against the wishes of the Constituent Assembly. By this amendment we are only fulfilling the intention of the framers of the Constitution at that time.

(Seventeenth

Amendment) Bill

One difficulty, however, arises, and that difficulty is this, that howsoever we may agree with the programme of land reform, howsoever we may agree with the concepts of ceiling and land distribution, we cannot forgive nor forget the acts of ommission and commission which the various Congress Governments are committing to shelve the issue of land reform. Merely passing of an Act OF is not sufficient. As I just now pointed out, the Bombay Khedut Sangh says that 24,000 applications are still pending, though the Act was passed in 1950. If one goes and examines the implementation of the land reform programme in various States, the slow, tardy way in which it is implemented, one is forced to doubt the bona fides of the Congress Party in implementing the whole programme of land reforms. It seems either that the party is wedded too much feudal vested interests and is not interested in implementing speedily the land reform programme, or they only giving lip service to the principle with no intention of implementing it. What is the result?this I want to point my hon. friends of the Congress Party and the Treasury Benches. You alienate the interests from whom you declare you are going to take away the land, without winning over the interests to whom you purpose to distribute, because you do not distribute; you create a situation in which you do not even reap the benefit of your land legislation, because the agricultural labour is not won over because it does not receive any concrete benefit, and you alienate the proprietory interests who are going to be deprived of their ageold proprietory rights. The result is that in the present social set-up-and I know something of what I am talking about—the rich peasantry has a social control over the entire community, and it is able to create illusions, wrong notions and make false propaganda and run away with the entire agricultural labour also who are supposed to be benefited by such law, and a sort of movement, agitation, propaganda is built up. All this because you are not speedy enough in implementing your land legislation.

I will not go into the details because I am not well versed in them, but let us take the example of Kerala. The Bill was discussed and passed after one year's consideration, the President gave his consent. was screened by the Planning Commission. All these stages were gone through. As soon as the Congress Government comes to power, all the benefits that accrued to the agricultural labourers and to the very small peasantry from that Bill are scrapped. and a new measure is sought to be introduced and rushed through Assembly, and the President's sanction is obtained, and the applications of thousands of agricultural labourers who had applied for getting peasant proprietorship under the old Act are still pending and washed away. This does not show a burning, genuine desire to implement land reforms. Merely, therefore, talking of land reforms will not help, will not distinguish the Congress Party and its programme from the Swatantra Party and its programme, because you do not implement. People are tired to hearing lip homage paid to socialism and land reforms without implementation

The Joint Committee in its evidence amply proves that the implementation of land reforms has been extremely halting, faltering and blundering. So many loopholes are left, for example, that of transfer. Even the Planning Commission has stated that past transfers should be invalidated. We know actually speaking, that so much is tom-tommed about land reforms, that before the Bill is passed, the interests that be arrange to distribute the land that they own to their brothers, nephews, nieces, to so many persons, and ultimately when it comes

to actually acquiring land, very little land is actually left. That is the experience. That is why even the Planning Commission has pointed out that these are the causes of the failure of land reforms, and has demanded that past transers should be open to re-examination.

Similarly, there are loopholes the exemptions that you allow. It is fantastic. I come from the old State of Madhya Pradesh. So many tions have been allowed that a Congress Member, who ultimately rose to become the Chairman of the Ad hoc committee of the entire province. speaking on the Bill in the Assembly said, that under the Bill even 1,000 acres could be exempted under different heads. If there are such loopholes, what is the use of talking reforms? Loopholes, the about land question of transfer and the question of implementation-unless these three are tackled, merely amending Constitution, showing your earnestness about it, will not solve the basic problem. The basic problem, therefore, is: how are we going to reconstruct our agricultural economy and our agricultural peasant household, so that the question of under-employment of agricultural labour, the question of interest in land is immediately solved. Continuous talk without implementation creates a bad climate which dampens the enthusiasm of the proprietor, without inspiring agricultural labour to work for more production.

Therefore, it is in this context that, while I support this Bill, I request the Government not only to rest on the ores of passing this Bill, but to see that the spirit which has motivated this amendment to go ahead with land reforms, is translated into action by speedy implementation of land reform legislation in all the States, and that the loopholes are plugged

As I submitted, not only this, but even if any further amendment of the Constitution is required for the social progress and economic betterment of the common people, I am sure the people of the country would support any such measures.

Shri Oza (Surendranagar): Since this Bill was introduced in this House, opportunity has been seized by the Swatantra Party to exploit it not only within the four corners of this Chamber, but also outside the House. so many by-elections held since the introduction of the Bill, they have made agitation against this Bill their main plank. I am very happy to note that particularly in my State, the people who, they fear, are vitally affected, have given a very clear verdict, and the candidate whom they sponsored, and who made agitation against this Bill his main plank, lost his deposit. So, I was going to request Shri Ranga and his colleagues not to talk in the name of the peasantry.

We all know that land reforms have been given a special place of significance in all the Plans that we have adopted, the First, Second and the Third Plan. We are wedded to certain policies. The House has adopted from time to time all these Plans, and now it is too late for Members to agitate against certain points which have been already accepted by all the three successive Parliaments.

We know why these land reforms are to be adopted. We want to remove all impediments to agricultural production. That is one objective. second objective is to remove all exploitation so far as land relations are concerned. But, after all these years, when we look back, can we take satisfaction about what has happened? So many Members who have participated in this debate, have taken the opportunity to air their views on land reforms. I found the reasons why land reforms had not been successfully implemented in Being a member of the ruling party, I see around me so many speakers from this side who have attacked the very basis of land reforms. I was not only surprised, but very much pained. It showed lack of earnestness and faith about land reform policies which this House had accepted through so many Plans. Land

reforms disturb the agrarian relations prevailing for centuries in this coun-There was exploitation. certain relations are established between the proprietors and the tenants. When you want to disturb these relations, doing things in a half-hearted and tardy fasion will, I am afraid, do more harm to the community than good that is supposed to accrue to them. We should be very quick in the implementation of these reforms. That is the first condition. Otherwise, we saw that they do much harm than good to the community which was to benefit under the land reforms.

Merely putting land reforms on the statute book is not sufficient. Those who are to profit by these land reforms are illiterate and ignorant persons, spread in interior parts all over our country. So, we must also see that they are made conscious of their rights and that they become courageous enough to enforce the given to them by the legislatures. In many States those who sponsored land reforms rested with the idea of putting the whole thing on the statute book. But I know of a State in which I was staying where we were directly interested in the question of land reforms; we moved from village to village—I mean the political party interested in the land reforms-and explained to the cultivators what were their rights and how they can exercise them and helped them to protect their rights properly. Only if that could be done we could push the whole land reform policy to a success-When Kamal Pasha took ful stage. over the administration of Turkey, he moved with a blackboard and chalk. He went from village to village and explained the reforms that were promulgated and thus created social consciousness. In the same way, if land reforms are to be implemented successfully we have got to see that vast illiterate peasantry spread in interior parts of our country—the political party which sponsors the land reforms has got this responsibility-know their rights and are

encouraged to exercise their rights. This has not been done and we have heard of so many cases of large-scale eviction in many parts of the country. The administrative machinery has also got to be geared up; the records of the ryots are to be properly taken care of. We know in the villages these records are tampered with by small revenue clerks, patwaris and kulkarnis who are put in charge of these land records. There are a lot of genuine complaints in this respect that land records are tampered with. With the result that the land reforms that we propose to carry out successfully could not be done and the poor peasants are deprived of their rights. The administrative machinery has also got to be geared up so that nothing wrong can take place out of the tampering of the records.

When this Bill was introduced so many Acts were included. I am happy to note that many redundant Acts of many States have been taken out and only those which must be included are kept in the Schedule. But there is a somewhat invidious distinction in the proviso that has been adopted by Joint Committee. When abolished zamindary we have acquired land for those who were actually tilling on payment of reasonable compensation. Even when a zamindar's total holding was below the ceiling. we did not give him the market rate. We gave him only reasonable compensation. But when the question comes of acquiring any land from a ryot or from an occupant under the land reform scheme, we give him market value. I think this is not a happy distinction. If the land reforms adopted by the State or by the Governments concerned are found to be necessary for stepping up production, to do away with exploitation, I do not think we should maintain this invidious distinction we have in this proviso. However, I will not have any quarrel with it because all the Members of the Joint Committee except those who come from the Swatantra Party have endorsed it on the whole. With these remarks, I

welcome this Bill and I request the Government to impress upon the State Governments to immediately implement whatever land reforms are yet to be implemented so that their total impact may be realised by the community; production may go up and those who are directly affected may feel a sense of security so that the relations which are till now in a disturbed condition may be stabilished and people may till their lands effectively to the benefit of the community.

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon): Sir, I thank you for giving me time. As a matter of fact I have gone through this Bill as well as the other views recorded. I have very grave doubts if this Bill would solve the difficulties that have arisen because of certain ruling about a certain State in the Supreme Court about the land reforms. In communist countries they say that all land belongs to the State and they can dispose of it in any manner they like; if it is so it is another affair. But in the present context in India, if a land-owner has some property, it is common notion that it is his property and it cannot be taken away from him without compensation, without the requisite conditions being fulfilled, namely, that the land is required for the State for opening an essential and basic industry, etc. mainly for the benefit of agriculturists. I submit that this definition of estate would create more confusion and more difficulties than are expected to be solved. It is provided that all the States may have a ceiling on the basis of some standard acreage on the basis of production. That may solve some difficulty. Now what has been done is, as hon. Members are aware, any surplus land whatever it was called was distributed among the sons and relations and others before any ceiling came into effect and to avoid it. Nothing was done which was meant to benefit the tenants or the landlords in that I would certainly submit manner. that in the State of Punjab to which I belong, we have a very good set of laws, not from today, but since a very

[Shrli Gajraj Singh Rao]

Constitution

long time, from the very start. complaint was just now made that patwaris and other officers make such and such mistakes or something like that. But I may point out that in the Punjab Land Revenue Act there is a presumption under section 44 of that Act, in regard to the correctness of the land records. Ιf anybody is aggrieved, or if anybody feels aggrieved, he can bring a regular suit and can get the record rectified. Then, in section 5 of that Act, there is a provision to the effect that if the tenants are in the possession of the land for 30 years or more, they become occupancy tenants and also under section 8. There is a provision that they become proprietors on paying the nominal compensation. If the other States follow this example, there would not be confusion. Now, the definition of "estate" would be exploited in every State, and different meanings would be given in different ways and it would be interpreted in different ways. It would serve only this purpose: I can say it from my practical experience: it would provide for litigation for the benefit of the lawyers'. It would be a paradise for the lawyers and the litigant public which would be going on for sometime. If any land can be taken without compensation, at any time, as is suggested for co-operative farming, then, clearly they should come out that they want co-operative farming. For that purpose, the peasant proprietor, out of pride and sense of security or something like that, having only two bighas or half an acre of land, can say, "I am a landlord".

13.00 hrs.

Now, the words "landlord" and "zamindari" as existing in the States of Uttar Pradesh, Bihar, Kerala, etc., have absolutely different meanings than what they are meant, in Punjab. In respect of the 90 per cent of peasant proprietors in Punjab, there has been no difficulty. Unless there is a sense of security that this measure is

not going to put up permanent handicaps in respect of land, it would always be in jeopardy; nothing else.

Can it be said, taking into account the whole co-operative movement as such, that the co-operative farming has been successful, if all the cost is taken into consideration? It has been a big loss and failure, and if this is experimented in this manner, as is suggested, it would be a still bigger loss. There would be loss in production. What is aimed at would result in a loss altogether.

I would certainly submit that at least if the Government want this Bill to be considered and passed into an Act, they should clearly say that the peasant proprietors, whatever ceiling is fixed by the States or by the direction of the Centre, would not be touched and that their land would not be taken without compensation or without any reasonable amount by way of compensation.

Take this question of army men. They are serving the nation abroad and they may be absent for five to eight years. It would be interpreted that they are not self-cultivating the land and that their land should therefore be taken away. Is it fair? Take for instance this aspect of the matter. There are five brothers and two or three of them are away. They cannot afford to live on the income of the land of two or three bighas. The authorities would say that the lands are not in self-cultivation and therefore the land can be taken. Would it be fair? So, this definition of "estate" as has been contemplated, would serve neither the purpose of bettering the cultivation or production nor the purpose of having good relations between tenant and landlord nor the purpose of giving away the surplus land, as it is called, to the landless tenant. I would like to point out to the hon. Members the system of Shartwajabulwarz,-the record of village customas it existed in Punjab. It was more than a codified law, and under it, every landless proprietor who helped in cultivation was given a certain share, say, one maund per plough or one maund per bullock for cultivation, and that was a better thing for him, and he got more land produce by helping in the operation. It is a combined operation; it is not a question of ploughing and sowing all alone. Many persons in the village combine together and engage themselves in the agricultural operations at various stages.

So, I would submit that at least Government should give an assurance that this measure would not be exploited in the sense that the peasant proprietors having land below the ceiling would not be affected. The land of the serving men, those who are in the army even for a temporary period or for a certain definite period and the land of those who are in the essential services,-when the men are absent for a temporary periodshould not be affected and compensation paid in this manner. Even today what has happened in Faridabad, 16 thereabouts from Delhi? Hon. Members can go there and find the position is. The people there got land at three annas or four annas per square yard. Now, they are selling the land at Rs. 35 or Rs. 40 They took the per square yard. average of five or ten years and compensation was paid like that. That is so, because the price of land, especially in the factory areas, has risen very high, and the rate was computed on that basis and the land was taken and it is now being exploited like that.

With your permission, I shall make one point. "Land" as defined in any law means land with buildings and structures. That is the definition of the land. Why should it not apply to the lands in Delhi, where lakhs and lakhs of people who have built this big Delhi are lying or living in these sirkis and thatched huts, without adequate shelter? Cannot those lands on which the palatial buildings stand be considered as lands? Should it apply only to the small peasant

proprietors and their lands? Why should the definition not apply to these big people so that those who live in the huts could get some accommodation?

I beg to submit that the basic law should be this. If once it is conceded that he is the owner or the proprietor of the land-I do not mean surplus land and a ceiling may be fixed-then, for land revenue there should be the basis of income-tax which should be A man living in a castle would pay a certain tax on his income, but if a man's income is below a standard, he would not pay any tax to the Government. Similarly, if a peasant proprietor has only half an acre or a quarter of an acre of land, why should he pay? Why should the law be of such a nature that he is asked to pay? Why not income-tax be the basis for assessing the land revenue?

So, with these suggestions, I submit that the Government should assure us that the peasant proprietors would not be exploited. These theories would only create confusion, and favour the communist-minded people who want confusion all over India and in every walk of life and destroy the social and civic life of the country. This should be avoided and the Government should give us this assurance.

श्री बड़े (खारगोन) : १७वा एमेंड-मेंट जो कांस्टीट्यूशन का है, यह किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है । किसानों को राजा-महाराजाओं से पट्टे पर जमीन मिली हुई थी। जब किसान मर जाता है तो उसके लड़के को गह जमीन जाती ह। प्रान्तों में सीजिंग एक्ट लागू कर दिये गये हैं। सीजिंग से ऊपर जो जमीन थी उसको लेने का अगर सवाल पैरा होता था उसके ऊपर लंड अगर एक्वायर की जाती थी तो किसान कोर्ट में जा सकता था और कह सकता था कि उसको पूरा उसका कम्पेसेशन नहीं मिला है, ज्यादा मुआव्या उसको मिलना चाहिये। लेकिन अब जो संशोधन किया जा

12994

रहा है. उसमें उसके इस ग्रधिकार को छीना जा रहा है। उसको ग्रब इस प्रकार का कोई हक नहीं रह जाएगा। इस डेमोक्रेसी में कोर्ट के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बन्द हो जायेंगे। इसी कारण से मेरा इस बिल से मख्यतः विरोध है। स्राप इन एक्ट्स को नौवें शैड्यल में रखें या किसी भी शैड्यल में रखें. लेकिन कम से कम कोर्टका जो दरवाजा है वह तो ग्राप उसके लिए बन्द न करें। कोर्ट का दरवाजा तो सब के लिए खुला रहना चाहिये । उसको ग्रपने राइट्स को कोर्ट में जा कर सुरक्षित करवाने का हक होना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो किसान को कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकती है ग्रीर न है।

Constitution

लैंड रिफार्म्स करने का ग्रापका जो उद्देश्य है, जो भाखिरी उद्देश्य है, वह उद्देश्य ग्राप इस में हस्तगत कर रहे हैं। ऐसी घारणा किसान के मन में निश्चित रूप में समा गई है। हमारे एक गुजरात के मित्र ने ग्रभी कहा कि स्वतंत्र पार्टी हर एक जगह जा कर कहेगी कि देखो तुम्हारी जमीन जाने वाली है। इस में कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। **प्रापका उद्देश्य भ्राखिर में यह है कि यहां** पर कोम्रोप्रेटिव फार्मिंग हो । यह उद्देश्य केवल इस बिल से परा नहीं होता । एक श्रीर भी कारण से पुरा होता है। स्रापने अपना उद्वेश्य थर्ड फाइव यीग्रर प्लान में दिया हुग्रा है । उसमें भ्रापने क्या कहा है, यह मैं भ्रापको बतलाना चाहता हं।

A perusal of Chapter XIV of the third Five Year Plan will show that the ulterior object of these land reforms is to impose co-operative farming: I am quoting from there:

"It was realised that with the existing pattern of distribution of agricultural holdings and the predominance of small farms, redistribution of land in excess of any

given level of ceiling was likely to make available any large results in the shape of surplus land for distribution. It was considered however that such a reduction in disparities was a necessary condition for building up a progressive co-operative rural economy."

इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्राप कोग्रोप्रेटिव फार्मिंग करने जा रहे हैं। यह घारणा किसान के मन में, काश्तकार के मन में घर कर गई है कि उसके पूर्वजों को जो जमीन पट्टे पर मिली थी, जो उस वक्त के राजा महाराजा थे उन्होंने उसके पूर्वजों को जो जमीन दी थी उसको छीन कर श्राप वहां पर कोग्रोप्रेटिव फार्मिंग करवाना चाहते हैं। यह शंका उस ठहराव के कारण उस प्रस्ताव के कारण श्रीर भी पक्की हो जाती है जो प्रस्ताव कांग्रेस ने प्रपने नागपुर के घ्रधिवेशन में पास किया था। उस में यह कहा था कि जो म्रल्टीमेट श्राब्जेक्ट है वह कोश्रोप्रेटिव फार्मिंग करने का है। इस १७वें संशोधन से, नागपुर वाले प्रस्ताव से तथा थर्ड प्लान के उद्देश्य से किसान के मन की धारणा पक्की हो गई है। कोर्ट का दरवाजा जो भ्राप किसान के लिए बन्द कर रहे हैं उससे उसके मन में यह शंका पैदा हो गई है कि भ्राप स्टालिन बनना चाहते हैं, भारतीय रहना नहीं चाहते हैं, श्राप स्टालिन हैं, भारतीय नहीं हैं।

"The opposite method may be termed as Stalinist method. Stalin destroyed 20 million peasants to enforce the co-operative farms in Russia."

स्टालिन ने बीस मिलियन किसानों को **डेस्ट्राय** किया था । यदि श्राप स्टालिन होना चाहते हैं श्रीर कोश्राप्रेटिव फार्मिग करना चाहते हैं तो यहां का जो शासन है. उस में उलटफेर हो जाएगा, इसको लोग बरदाक्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसान से जा कर भ्राप पुछिये, कांग्रेस में ही जो किसान हैं, उन से ब्राप पूछिये कि ब्रगर उनकी खेती को हाथ नगाया जाएगा, ब्रगर कोब्रोप्रेटिव फार्मिंग करने की कोशिश की जाएगी तो क्या किसान उसको वरदाश्त करेगा ? कभी नहीं करेगा ।

ग्रापने यह नारा लगाया था कि लैंड टू दी टिल्लर । बहुत सी जगह पर यह हुग्रा भी है । मध्य प्रदेश में रायतवारी टैनेंसी शुरू से ही चल रही है । वहां पर लैंड रेवेन्यू कोड शुरू से ही चल रही है । वहां पर लैंड रेवेन्यू कोड शुरू से ही लागू रहा है । उस ायतवारी टैनेंसी को वास्तव में इस नौवें शैड्यूल में लाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी । वहां पर रायतवारी पद्धित होते हुए भी इसको इस में डाल दिया है, इससे शंका पैदा होता है कि ग्राप एक शस्त्र ग्रपने हाथ में लेना चाहते हैं, संहारकारी शन्न ग्रपने हाथ में लेना चाहते हैं, लोगों से उनकी जमीनें ले कर कोग्रोफेटिव फार्मिंग करवाना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश का जो लैंड होल्डिंग एक्ट है, रेवेन्यु कोड है, उस में लिखा हुम्रा है कि जो सीलिंग से ऊपर की जमीनें होंगी वे पहले तो जो पोलिटिकल सफरर्ज हैं, उनको मिलेंगी। पोलिटिकल सफरर्ज कौन है, इसकी परिभाषा भी कर दी गई है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में या सत्याग्रह में हिस्सा लिया था. जो जेल गये थे. उनको पोलिटिकल सफरर्ज माना गया है। अब आप देखें कि जल जाने वालों में बड़े बड़े नेता भी हैं, वे लोग भी हैं जो उच्च पदों पर ग्राज लगे हए हैं, कोई खादी श्रीर ग्रामाद्योग बोर्ड का चेयरमैन है ग्रौर कोई दूसरी जो संस्थायें हैं, उनमें पदाधिकारी है या श्रध्यक्ष है। इन लोगों ने काफी पैसा कमा लिया है। वे भी एप्लीकेशन देते हैं कि हम भी पोलिटि-कल सफरर हैं, हमें भी जमीन मिलनी चाहिये। भगर वे एप्लाई करें तो पहला प्रेफेंस उनका हो जाता है। दूसरे नम्बर पर कोस्रोप्रेटिव सोसाइटीज घाती हैं जिनको जमीन दी

जाएगी । तीसरे नम्बर पर म्रादिवासी श्राते हैं और चौथे पर हरिजन स्राते हैं। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का जो रूल १६२ है उसके अनुसार अगर आप पोलि-टिकल सफरर को जमीन देते हैं जिसके पास जमीन नहीं थी, जो किसान नहीं है, उसको जमीन देते हैं तो लैंड ट दी टिल्लर का जो श्रापका नारा है, वह कहां चला जाता है, टिल्लर को ग्राप कहां से जमीन देंगे ? चुंकि एक बार कोई जेल चला गया भीर उसने कुछ तकलीफ सहन की, इस वास्ते उसको पहले जमीन दी जाए और यही उसकी क्वालि-फिकेशन हो गई जमीन पाने की तो यह बात समझ में नहीं म्राती है। यह तो उसी तरह से हो गया जैसे कोई बी० ए० पास करने के बाद एम० ए० पास कर लेता है या भाई० ए० एस० पास कर लेता है भीर यह उसकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। जेल जाना भ्रापने एक क्वालिफिकेशन मान लिया । दूसरे भ्राप कहते हैं कि भ्राप कोभ्रो-प्रेटिव्य को जमीनें देंगे। तो फिर भ्रादिवासियों श्रौर हरिजन लोगों के लिए जमीन श्राप कहां से देंगे । उनके दिमाग में भ्राता है कि उनकी जमीनें भी भ्राप कोम्रोप्रेटिव फार्मिंग में लेना चाहते हैं, इसलिये वे इसके विरुद्ध हैं ।

सिलैंक्ट कमेटी में लैंड की जो डेफीनी हान दी गई है उसको भी धाप देखें। उस में एप्रिकलचरल लैंड भी धाती है और बिडिंग्ज भी आ जाती है। बिल्डिंग की बात धाप क्यों रख रहे हैं? केवल एप्रिकलचरल लैंड धाप रखते तो शायद धाब्जेक्शन न होता। हमारे माननीय सदस्य श्री काशीराम गुप्त जी ने जो एक एमेंडमेंट दी है, मैं उससे सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया जाए।

सीलिंग लैजिस्लेशन में कहा गया है कि जहां फ़ूट गार्डन हैं वहां यह लागू नहीं होगा। हमारे साथ लगता हुआ। महाराष्ट्र का इलाका

[श्री बड़े]

है। वहां पर लोग गन्ना उगाते हैं। गन्ने की बेती फट गार्डन में नहीं आती है। इसलिए उस पर सीलिंग एक्ट लागू होता है। वहां पर जितने भी काश्तकार हैं उन्होंने इस वास्ते दाख की खेती. केले की खेती करना शरू कर दिया है जिस का नतीजा यह निकला है कि गन्ने का उत्पादन कम हो गया है। बम्बई में मैं एक मंत्री महोदय से जो उच्च कांग्रेसी नेता भी है, मिला था और उन को बताया था कि इस से गन्ने का उत्पादन कम हो गया है भीर आगे भी कम होता जा रहा है। चंकि फट गार्डन पर सीलिंग एक्ट लाग नहीं होता है इस वास्ते इम एक्ट से बचने के लिए लोगों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है। इस तरह से भ्राप जो डिफेक्टिव कानन बनाते हैं, उन से कोई लाभ नहीं होता है। दो बातें स्राप को करनी चाहियें। एक तो लैंड टुदि टिल्लर की बात ग्राप करें ग्रीर दूसरे जो मैंकेनाइज्ड फार्म हैं. उनके लिए श्राप कोई प्राविजन रखें। जब तक भ्राप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तब तक जो भ्राप का उद्देश्य है वह पुरा नहीं होगा । इन के बगैर लैंड रिफार्म्स नहीं हो सकती हैं।

हमारे दाजी साहब ने श्रभी कहा कि लैंड रिफार्म्स भ्रौर तेजी से होनी चाहियें। वह तो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का किसी तरह से विघटन हो । जब राजे महाराजे ये तो कहा जाता था कि जमीन स्टेट की है भौर किसानों को पट्टे पर जमीनें मिल गई थीं ग्रीर उन पर किसान बड़े ग्राराम से बेती कर के ग्रपना पेट भर लिया करते थे। मापने कहा है कि कोम्रोप्रेटिव फार्मिंग करेंगे. कलक्टिव फार्मिंग करेंगे, जिससे किसान के मन में शंका पैदा हो गई है। इस तरह की बातों से ही इलैंक्शन में श्राप को हार खानी पड़ी है स्वतंत्र पार्टी के हाथों या दूसरी विरोधी पार्टियों के हाथों । दरश्रमल किसान को इंसेंटिव मिलना चाहिये, उस को मालुम होना बाहिये. उस को बताया जाना चाहिये कि

लैंड रिफार्म्स के नाम पर भाप उस की जमीन लेने वाले नहीं हैं, वह भ्रपनी जमीन का भाप मालिक है। उस को विश्वास होना चाहिये कि ग्रगर वह ग्रपनी जमीन में कूंग्रा खोदता है तो उस कुए का पानी उसके बच्चों को वीने को मिलेगा, श्रगर कोई श्रीर काम करता है तो उसका लाभ उसके बच्चों को मिलेगा । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक खेती में सुधार नहीं हो सकेगा । आप रिफार्मेशन नहीं. डिफामेशन ही करेंगे । रशिया और चाइना में इस प्रकार का कलैक्टिव फार्मिंग हम्रा है। वहां पर वह फोल हो गया है स्रोर उन को ग्रमरीका से व्हीट मंगानी पड रही है। ग्रगर ग्राप इस विधेयक के उद्देश्य की तरफ जायेंगे तो जो ग्राप का⊹संविधान का ९७वां ग्रमेंडमेंट है मैं उस का विरोध करता हं. भ्रौर वह केवल इसलिये कि स्राप को कोर्ट का दरवाजा बन्द नहीं करना चाहिये। इस में कम्पेन्सेशन देने का प्राविजन रक्खा गया है ग्रीर ज्वायेंट कमेटी ने उस में एक सुधार भी कर दिया है कि जब किसी की जमीन माप लेंगे तो उसको मार्केट वैल्य कम्पेन्सेशन के तौर पर देंगे। यह बहत ग्रच्छा संशोधन है स्रौर हम को इस को जरूर मानना चाहिये। लेकिन माकेट वैल्य देने के सम्बन्ध में जो म्राधार होता है उस के बारे में एक जगह पर इस एविडेंस में स्राया है कि :

"In Sherawati, with which I am a bit conversant, Government gave a direction 'you shall not award more than Rs. 6,000'."

यह जाहिर कर दिया कि मार्केट बैल्यू ६,००० रु० से ऊपर नहीं मिलनी जाहिये।

"Accordingly, the Land Acquisition Officer gave Rs. 6,000 as his award. When the matter went to the courts, they gave Rs. 18,000 and the High Court has recently confirmed it."

इस प्रकार से हर एक गवर्नमेंट ने अपना अपना आर्डर निकाला है कि कितना कम्पेन्से- शन प्रति एकड़ मिलना चाहिये । मीलिंग ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि कितना कितना प्रति एकड़ ठहराना चाहिये । जिनके खेत आप लेते हैं उन के लिये आप ने निश्चित कर दिया है कि कम्पेन्सेशन ६,००० रू० होना चाहिये लेकिन हाई कोर्ट में जा कर इस रक्स को तिगुना और चौगुना कर दिया गया । इसलिये मैं समझता हूं कि कोर्ट का दरवाजा आप को बन्द नहीं करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सीलिंग के मामले में बहुत डिस्क्रिशन रक्खा गया है। मध्य प्रदेश में तो एक मिक्स्चर सा है। वहां पर "कहीं का इंट स्रोर कहीं का रोड़ा, भानमती ने कूनबा जोड़ा" वाली बात है। वहां पर महाकौशल हिन्दी स्पीकिंग है. उस में पहले मध्य भारत का हिस्सा था. ग्वालियर स्टेट का हिस्सा था, होलकर स्टेट का हिस्सा था । वहां पर ग्रलग ग्रलग सेटल-मेन्ट हए हैं भ्रौर भ्रलग भ्रलग जमीन के स्टैन्डडर्स ठहराये गये हैं। किसी ने स्राधार इनकम टैक्स को ठहराया है, किसी ने यह सोच कर कि उन के यहां श्रफीम की खेती होती है, और फिर जो काली जमीन होती है वहां स्रफीम ज्यादा होती है, इसलिये जस को ब्राधार मान लिया है, होलकर स्टेट में ज्यादा सीलिंग रक्खी गई है। ग्राप ने ग्रपने ऐक्ट के पूरे प्रिंसिपल को स्टडी किये बगैर सीलिंग लगा दिया है। मैं कहना चाहता हं कि हमारे यहां जो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स है वह स्टडी करते नहीं हैं किस किस जगह पर क्या क्या जिलिपल रक्खेगयेथे ग्रीर उन का ग्रोरिजन क्या था। वे सोचते नहीं हैं कि सीलिंग रखने से क्या दिक्कत पैदा हो जायेगी । नतीजा यह हुम्रा कि एक जगह पर एक मिसिपल रक्खा गया है दसरी जगह पर दूसरा प्रिंसिपल रक्खा गया है। श्राप ने मध्य प्रदेश के सीलिंग ऐक्ट को शामिल किया है। उस को शामिल करने की जरूरत नहीं थी रैयतवाड़ी हमारे यहां थी। लेकिन उस पर बिचार करने के बाद ज्बायेंट

कमेटी ने इन इट्स स्रोन विजडम सात ऐक्ट्स स्रौर जोड़ दिये। यह हाउस में कभी नहीं स्राया। इस के वास्ते डिसेंटिंग नोट भी है कि इन सात ऐक्टस को जोड़ने के वास्ते किसी की तरक से भी बात नहीं उठाई गई थी, किसी का साब्जेंक्शन नहीं स्राया था, किसी का प्रायंना पत्न नहीं स्राया था लेकिन गायद गवनंमेंट ने इन को जोड़ने के लिये कहा होगा। इस तरह एक जगह पर लिखा गया है। मैं समझता हूं कि इन सात एक्ट्स को जोड़ने के सम्बन्ध में इस सदन में कोई बात नहीं स्राई। इसलिये उन को ६वें शेड्यूल में रखना ठीक नहीं है।

मन्त में मेरा यह कहना है कि माप कं। कम से कम यह देखना चाहिये कि सीलिंग के वास्ते दरमस्ल सारे देश में एक स्टैन्डडं ठहराया जाये। म्राप को तय करना चाहिये कि स्टैन्डडं क्या होगा मर्यात् वह इनकम पर होना चाहिये, लेंड रेबेन्यू पर होना चाहिये या जमीन की क्वालिटी पर होना चाहिये । म्राप ने इस विभ्येयक में बहुत सी जगहों को छोड़ दिया है। मारच र्स को छोड़ दिया है। प्लैनिंग किम सन ने साफ कहा है कि किन किन को सीलिंग से म्रलग रखना चाहिये। उस ने कहा:

- "(1) tea, coffee and rubber plantations;
- (2) orchards where they constitute reasonably compact areas;
- (3) specialised farms engaged in cattle breeding, dairying, woolraising, etc.;
 - (4) sugarcane farms operated by sugar factories; and
 - (5) efficiently managed farms which consist of compact blocks on which heavy investment or permanent structural improvements have been made and whose break-up is likely to lead to a fall in production."

[श्री बड़े]

प्लैनिंग कमिशन ने ग्राप को इन्स्टक्शन्स दिये थे कि शगर केन फार्म्स को जिन को फैक्टीज आपरेट करती हैं, छोड़ दिया जाना चाहिये। ग्राप को शगर केन फार्म्स को बढाना होगा क्योंकि इस में जो लिस्ट दी हुई है उस में सीलिंग ऐक्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ज्वायेंट कमेटी की रिपोर्ट में । ज्वायेंट कमेटी यह भी व्यवस्था चाहती है कि प्लैन्टेन ग्रीर शगरकेन फार्म्स या बागीचे जो हैं उन को जोड देना चाहिये। लेकिन उस को सरकार ने जोड़ा नहीं है। इस प्रकार से करने की बात यदि हाउस के सामने श्राये तो मैं माननीय सदस्यों से श्रपील करूंगा कि उन को उसे देखना चाहिये । मैं कहना चाहता हं कि भ्राप चाहे जितनी जमीन दीजिये. लेकिन कोर्ट में जा सकने के लिए उस को खला रिखये। ग्रगर ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के किसानों की स्थिति बदल जायेगी, भारत के किसानों की एकानमी बदल जायेगी। कहावत है कि जब खराब दशा म्राती है तो बृद्धि पहले चली जाती है। "विनाशकाले विपरीत बुद्धि" । विनाग काल में सरकार की बृद्धि खराब हो गई है।

म्राच्यक्ष महोदय : यह तो म्राप के फायदे के लिये है।

श्री बड़े: मेरे फायदे के लिए जरूर है लेकिन साथ साथ श्री होमी दाजी का भी फायदा हो जायेगा । इस को देखना चाहिये ।

म्राच्यक्ष महोदय : ग्राप ग्रपना फायदा छोडने के लिये तैयार हैं।

श्री बड़े: इस प्रकार के ऐक्टस ला कर ग्राप कम्यनिस्टों का फायदा करेंगे। ग्राप कहते हैं कि ग्रागे के लिये बहत ग्रच्छा कर रहे हैं, लेकिन ग्राप ऐसी चीजें लाते हैं जिन से म्राप इस बिल के उद्देश्य की हत्या कर देते हैं। मैं भ्राप से यही कहना चाहता हं कि कोर्ट के दरवाजा इस के ग्रन्दर बन्द करना ठीक नहीं है, उस को खला रखना चाहिये।

(Seventeenth

Amendment) Bill

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, I welcome this Bill and I feel that the Joint Committee has done its job very thoroughly and very circumspectly. It has gone through a large number of memoranda and examined witnesses of varying political complexions. It has cross-examined them and it has tried to arrive at the truth of their assertions. All this process has been undergone, and the Bill as it has emerged from the Joint Committee is before us.

13.27 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

In the first place, I am very happy the definition of the word "estate" has been given in a very expressive way and an attempt has been made to remove as much of vagueness as possible. I do not think in this world we can arrive at an all-inclusive definition of anything. What human beings can do is to make an approximation to truth in these matters. I believe, in this definition of the word "estate" hardly anything has been left out, and if anything has been left out I think it can be covered But my feeling is that the definition has been made as fool-proof as possible.

I also feel that the legal sanction which has been given to this process of land reform is very heartening. Unfortunately, in this country we have vested interests. Of course, they are to be found in every country of the world. These interests are to be found not only in all the institutions which can be called representative in this country but also, all along the line, they can be found in the administrative services of our country. They can be spotted in other services of the country also. But it has been seen that the vested interests have as little a hand in playing with this reform as possible. I feel that this Bill will make it impossible, if not impossible at least very very difficult, for vested interests in the Parliament, in the Assemblies, in the Zilla Parishads, in the administrative services and other places to sacrifice the spirit of this reform. I think, this is a step in the right direction.

I also think that the principle of compensation which has been enunciated in this Bill will meet with the objectives which have been voiced by some of my hon. friends-I do not want to mention the names of their People have been talking parties. about Stalin and they think that it is a Stalinist measure. I would say that a Stalinist measure is a measure which does not think in terms of compensation but which thinks in terms of root and branch expropriation and of liquidation of those who stand in the way of any reform. I think, this is a democratic measure, conceived in the spirit of democracy and to be implemented in the spirit of democracy because the proprietor or the landlord, if I can use that word though that word stinks in my nostrils, is going to have his proper due and that nothing is going to be done by means of which he will be smarting under a sense of grievance that his land has been taken away and his land has been taken away without his having been paid adequately for it. These are the three things in this Bill which, I think, are steps in the right direction.

But I ask myself one question. What is the purpose of this Bill? What is the objective underlying all our land reforms? Why are we tinkering with.....

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): God alone knows.

Shri D. C. Sharma: Why are we tinkering with these land reforms all these days? Why have we been doing so all these days? So far as I know, there are three objectives. In the first place, there is the objective of

agricultural productivity. I want to ask: How far have these land reforms of ours promoted this objective? 17 years have passed and we are still in the land of scarcity and not in the land of plenty or the land of sufficiency; but we are still in the land of scarcity. I think, the Government should ask itself one question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Even the Punjab?

Shri D. C. Sharma. I come from the Punjab, but I have to think of you also. That is my misfortune. My misfortune is that I do not think only about myself but I think about persons like you who are always skeletons.

Shri Hari Vishnu Kamath: Madhya Pradesh is very backward.

Shri D. C. Sharma: Madhya Pradesh is very backward but it is represented by the very forward member. That is the misfortune of Madhya Pradesh.

I was submitting very respectfully that agricultural production is the sine qua non of these reforms, but have we been able to do that? No. We are still floundering in the mire of scarcity and we have to go to this country and that country in order to have enough to feed our citizens. Why is it so?

People talk of co-operative farming. Co-operative farming is very good if we are able to put it into practice rightly. But the difficulty is that these reforms have not given the people that kind of an incentive for production which they should have given. I am not one of those who say that they are destroying the incentive for production and that they have not given that quantum of stimulus for production which they should have given. We want co-operative farming. There is no doubt about it. We want other things also. But we should not think of USSR, Rumania, China and USA when we think of produc-If we want to improve our production, we have to think of countries, like, the UAR or Japan. In

[Shri D. C. Sharma]

Japan the per acre paddy yield is much higher than in my country; in the UAR the yield per acre was much higher than in my country. What is it that makes those peasants produce so much? This is what has not been done. Of course, you will say that this is not within the purview of this Bill, but certainly we have to see to the overall objectives of this Bill.

Again, take development. I think, industrial development is there. There a time when I represented There we built the Hoshiarpur. Bhakra Dam and also the Nangal Fertiliser Factory. We took away the lands of people for those projects. What happened? They were struggling for compensation for a long time. Ultimately, they were given compensation which, I should say, was not very adequate. Take the case of the UAR. They are building the Aswan Dam. What have they done? They have uprooted persons from certain villages, but they have built villages for them which bear their old names; they have given them those very amenities which they used to enjoy in those places where Aswan Dam is now being built. Are we doing that? No. We uproot the people for the sake of industrial development in our country which is very necessary but we do not give them the same kind of compensation and amenities which they were enjoying before.

I have said just now that compensation is a good thing, but I may tell you that land cannot be equated with money. Land cannot be measured in terms of money. There is no compensation which anybody can give for land. Even if you were to give Rs. 1 lakh to a peasant for one acre of land, it may be a monetary transaction but it will not be a psychological transaction; it will not be an emotional transaction. With land are bound up our emotions, our psychology, our heritage, our traditions and so many things. So, industrial development is all right, but we are not to sacrifice the welfare of our people to advance

industrially. I am saying all this because this Bill is going to place power in our hands which cannot be questioned in any court of law. Therefore I am striking a note of warning to my Government in these matters.

(Seventeenth

Amendment) Bill

The fundamental basis of our land reforms was distribution. Where is this distribution? I ask the Chief Ministers of States and the Minister of Agriculture in India to place their hands on their chests and tell me whether there has been any distribution worth the name in this country. I may tell you that a deputation of landless persons-a big deputationwaited on a Chief Minister of a State. I do not want to give the name of the State. They said, "We are ruined: our lands have been taken away. What can we do? We are starving. How shall we educate our children? How shall we be able to perform our social duties"? The Chief Minister knew much more than they thought he knew. He asked them: "Tell me honestly and truthfully whether any one of you has parted even with an inch of your land". Nobody had parted with an inch of his land. He gave away his land to his sons, daughters, brothers and other relations and there was no surplus land to be distributed to the harijans, the landless labourers and the occupancy tenants. All those persons did not get anything.

Only some days back some harijans from my State had a demonstration put up near Rajghat, the place where Mahatma Gandhi's sacred remains are. What did they want? They wanted that the surplus land should be distributed among them. If the surplus land had been distributed among the harijans, they would have had no need for that kind of a demonstration. But the fact of the matter is that the land remains with the persons who possess it and the harijans, the landless labourers and other persons do not get any land. You are taking away from these persons the right to sue somebody in the court. fore, I say, the implementation of this Bill has to be taken in hand very thoroughly and very conscientiously so that those objectives which we have in the matter of land reforms are fulfilled very thoroughly.

The question has been raised about urban and agricultural income. I support my hon, friend Mr. P. R. Patel. I support him in saying that you cannot have two nations in this country, one the nation of industrialists and other, the nation of agriculturists. I believe that there should be only one nation and that should comprise of both industrialists and agriculturists. The rules applied to agriculturists should also apply to industrialists. You are taking away so many things But you from agriculturists having monopoly in newspaper industry, monopoly in industrial development and monopolies all along the You are taking away the land from the land-holder but you are not thinking of those persons who are building up the industrial empires. I think there should be one rule which should apply to all persons.

In the end, I would say that this Bill is good as far as it goes but I do not know what machinery in the Government will evolve to see to it that this Bill fulfils the objectives for which it is going to be enacted.

Shri P. G. Menon (Mukundapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have great supporting this Bill. pleasure in Criticisms against this Bill have been based on many grounds, one of them being that the fundamental rights enshrined in our Constitution being meddled with too often. Sixteen times the Constitution has amended and this is the seventeenth amendment. I agree with those who think that the fundamental rights enshrined in our Constitution constitute a noble and very exalted element in the Constitution of our country. One of those articles in that Chapter, namely, article 19, guarantees to citizens the right to hold property and to acquire property. That is, no doubt, a valuable right and a very important right. These are rights guaranteed to

individual citizens. It is the duty of the courts to see that those rights are not interfered with either by executive action or by legislation. But at the same time, it is necessary to remember that the same document. namely, the Constitution, enacted by the Constituent Assembly, in the next chapter refers to certain other matters. I refer to the Directive Principles. So far as the Government is concerned, so far as this Parliament is concerned, I hold that the Directive Principles are as important as Fundamental Rights themselves. I heard on the floor of this House arguments in support of the necessity for land reforms, the statement that successive Parliaments and the Planning Commission have been advocating. But we need not go into that point because the Directive Principles themselves provide for land reforms. The economic equities and equalities provided for in the Directive Principles require that there should be land reforms in this country so that as regards the tenants who are subject to rackrenting, tenants who have no fixity regarding their tenures, agricultural labourers who although tenants are not given this status of tenants-large and extensive holdings in the possession of individual persons-something has to be done with respect to this matter if we attach any importance, apart from other considerations, to the Directive Principles contained in the Constitution.

May I, with your leave, draw the attention of the House to the article which says:

"... but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

So, so far as the Government is conecrned, so far as we in the Parliament and the members of the Legislatures in the State are concerned, the Directive Principles in the Constitution are very fundamental and a Government and a Parliament which ignores in its trans-

[Shri P. G. Menon]

13009

actions the directions contained in the Directive Principles are ignoring the fundamental directions made by the Constitution. This is the reason why land reforms become necessary and it has been found by experience that unless there are some amendments removing the fetters regarding acquisition contained in article 31, it would be impossible to have land reforms in this country. In that situation. what is the duty of this Parliament? Is it the duty of the Parliament to see that the Constitution is there, the fundamental rights are there-let us not touch them-or is it not our duty to see that these are equally fundamental and the amendment should be there? Look at the fate of the land reforms legislation which was passed in Kerala and which was an immediate occasion for bringing in this amendment. There was the Land Tax Act and there was the Agrarian Relations Act which was passed in 1960 or 1961. These Acts were found to be invalid both by the High Court of Kerala and by the Supreme Court. Therefore. the attempts of the Government and the Legislatures to bring about land reform failed and that occasioned this amendment. I think, therefore, it is the duty of all concerned to give whole-hearted support to this amend-This is not the occasion this is the forum wherefrom to speak about the merits and demerits or the different land reforms Acts of the various States of India. I think I will be going out of my subject if I attempt to do so. But at the same time, it should be remembered that the object of this constitutional amendment is to give constitutional backing to these various land reform legislations. It was stated by one of my friends the other day-Mr. Ranga, I believethat unless we put some fetters future Governments and legislatures from dealing freely with ceilings and other things, there may be ruin in this country. Is it possible to put fetters like that? Can't the Constitution be amended by future Parliaments? Apart from those things, can't extraconstitutional efforts come into play

if social urges are not properly satisfied? Therefore, I do not think that there is much in that argument

I heard from one or two friends some reference to what happened in Kerala with respect to the Land Reforms Act of Kerala. The charge was that the Act which was passed in 1959 by the legislature which was then in existence had been substituted later on by an Act which was passed in 1962 or 1963. A claim was made that the former Act was more liberal and more progressive than the later one. this matter also. I do not want to enter into any controversy. But what happened was this. I do not want to make any reflections on anybody. The communists were in power in 1959. I do not want to make any attack against them. But early in that year there was an agitation in the State to remove them from office, and ultimately, I think in July that year they were removed. When that agitation reached high proportions and intelligently they felt that they would have to quit office, it was their desire to see that before they did so they placed on the statute-book the Kerala Agrarian Relations Act. With that desire, that Act was passed hastily, without bestowing sufficient forethought on the various provisions of the legislation, and in July, 1959, that was passed, and the Communist Ministry there went out of office in July, 1959, a few days after the passage of that Bill, and the legislature was dissolved. am submitting that the Bill was passed hastily. I could understand their anxiety to see that the Act was placed on the statute-book.

The result was that every provision of that Act was found to be defective from a constitutional point of view. The Act was struck down by the High Court and by the Supreme Court. Apart from the unconstitutionality of the provisions, it is my submission that it was very difficult to work out the provisions of the Bill. When the Act was found to be unconstitutional, it was the duty of the legfislature in Kerala to enact a new law, because they were anxious that land reforms should be implemented. In enacting the new law, some of the obvious defects in the previous legislation were sought to be removed. If I had the time and the opportunity, I could, by making an analysis of the provisions of the two Bills, demonstrate that the claim made here that the second Bill was not progressive etc. is a claim made without any basis, and that it is only a political attack.

The only important change effected in the new Act is with respect small holders of property, persons holding one acre or two acres or half an acre of land. If they happen to have leased out their property others, they would come under the definition of a landlord in that Bill; they are landlords, under the definition, because it is a classification of different kinds of persons who have anything to do with property. What engaged the attention of the legislature on the second occasion was to see that these small holders of property or these small landlords were given some better protection than what was given to the bigger ones. The tenants, in some of these cases, may be very rich people holding large extent of property. That is the only change which has been made. So, I think it was absolutely without any grace that such an attack should have been made on the floor of this House on this score. It is the anxiety of the Congress Party, and I believe, of all Congress Governments, to see that the socialist and egalitarian principles enshrined in the Directive Principles in the Constitution, and later on consciously adopted on different occasions by the party, should be implemented. I do agree that there have been some delays here and some delays there, but the complexity of the question has occasioned the delay in some cases, and hasty legislation may lead to difficulties as we have seen.

For instance, look at the long Schedule, and the large number of items mentioned in the Ninth Schedule. It

difficult Take, is a question. example, the case of Kerala itsel!. The Kerala Agrarian Relations Act which was passed in 1959 was found to be valid in some portions of the Kerala State and invalid in other portions of the State; also, certain sections were valid in certain areas, and certain others were invalid in certain other areas. This is an index of the complexity of the matter.

Amendment) Bill

(Seventeenth

One of the reasons why Government decided to bring forward this seventeenth amendment to the Constitution is to see that these anomalies do not happen.

With these words, I support

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को गिराना या कानन न बनने देना मेरी इच्छा नही है श्रीर न ही यह मेरे दल की इच्छा है। लेकिन इस के साथ ही मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हं कि पिछले १७ सालों में कृषि के मामले में ग्रीर किसानों के सम्बन्ध में जो सरकारी नीति रही है, उस को देखते हए यह भी इच्छा नहीं होती है कि हम लोग मत-दान के समय इस विधेयक के समर्थन में मत-दान करें, क्योंकि ग्रगर इस विघेयक की पष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुए इस विघेयक को देखा जाये, तो यह विधेयक देश के किसानों के साथ एक मजाक है।

पिछले १७ सालों की इस की पष्ठभमि क्या है ? भ्राजादी मिलने से पहले देश की जनता के मन में क्रान्ति की ग्राशा थी। क्रान्ति का रूप क्या होगा. उस के सम्बन्ध में सब की घारणा साफ नहीं थी, लेकिन देहाती जनता के मन में, श्रीर खास कर के खेतिहर मजदर श्रीर छोटे किसान के मन में, यह ग्राशा जरूर थी कि श्राजादी के बाद, जमीन में जो बीच वाले होते हैं, वे खुत्म हो जायगे भ्रौर जो सही काश्तकार है, जो श्रपने हाथ से, श्रपने शरीर से, जमीन पर काम करता

[श्री किशन पटनायक]

है, जमीन पर उस का ही स्वामित्व होगा। लेकिन यह जो क्रान्ति की ग्राज्ञा जनता के मन में थी, वह १७ सालों के ग्रन्दर खःम हो गई।

Constitution

ग्राजादी के बाद दस बारह साल तक तो स्वतंत्र दल जैसे दल बनने की कोई सम्भावना भी नहीं थी, इसलिए कि कान्ति की ग्राशा तब भी जनता के मन में थी। लेकिन इन दस बारह सालों के ग्रन्दर जब सरकार की कृषि-नीति भ्रौर किसानों संबंधी नीति से अधि-अर्थ-नीति में भी बबादी आई ग्रीर किसानों के जीवन में भी वर्बादी ग्राई ग्रीर जनता के मन में ऋगित की ग्राणा कमजोर होने लगी तब जा कर इस देण में स्वतंत्र दल जैसे दल बनने की भी संभावना हुई ।

माज जब संविधान के सत्रहवें संशोधन के बारे में चर्चा होती है और स्वतन्त्र दल की तरफ़ से उसका विरोध किया जाता है श्रौर उस विरोध के समर्थन में प्रदर्शन लाए जाते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए भ्राज हिन्द-स्तान के खेतिहर मजदूरों या छोटे किसानों के पास ताकत नहीं रह गई है, या मन नहीं रह गया है। इन १७ सालों में भूमि सुधार करने के लिए, किसान का सुधार करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, इसको श्राप देखें। श्रभी तक तीन प्रकार के किसानों के बारे में कानुन सारे देश में बने हैं। एक कानन के जरिये तो जमींदारों को, जागीर-दारों को खत्म किया गया है, उनको खत्म करने के लिए कानून बनाये गये हैं, दूसरे जो बटाईदार वगैरह हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, बेदखली से रोकने के लिए कुछ कानून बने हैं भ्रधिकतर प्रान्तों में भ्रीर तीसरे हदबन्दी कानून बनने लगा है। इस कानून के फलस्वरूप हिन्दुस्तान की कृषि ग्रर्थ नीति में हर किसान के जीवन में क्या परिवर्तन भाषा ? जब सारी नीतियों को इकटठा करके हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं हमा है। न कृषि मर्थ नीति में कोई तबदीली हुई है जिससे उत्पादन बढ सका हो भीर न ही किसान के जीवन में कोई परिवर्तन हमा है।

14.00 hrs.

जहां तक पहले कानून का सम्बन्ध है जिसके द्वारा जमींदारी और जागीरदारी को खत्म किया गया है, बीच वालों को खत्म किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हं कि एक किस्म के बीच वाले को तो खत्म किया गया है लेकिन एक नई किस्म का बीच वाला ग्रा गया है, एबसेंटी लैंडलाडिज्म तो खत्म कर दिया गया है, दुरवासी जमींदारी तो चला गया है लेकिन काश्तकार की परिभाषा ऐसी कर दी गई कि दूरवासी जमींदार के बदले दूरवासी काश्तकार भ्रागया । भ्रब भ्राप एस्टेट की परिभाषा को साफ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जब तक काश्तकार की परिभाषा को भी ग्राप साफ नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा । वह काश्तकार नहीं हो सकता है और जो जमीन के पास नहीं रहता है भौर जमीन के ऊपर जो भ्रपना शारीरिक श्रम नहीं करता है। परिभाषा में ऐसी कोई चीज होनी चाहिये जिससे श्रंग्रेजी पढे लिखे लोगों को काइतकार न माना जाए।

एक माननीय सदस्य : वह कैसे ?

श्री किशन पटनायक : कृषि के ऊपर लगे लोगों को हिन्द्स्तान में हमको घटाना है, जो भूमि पर भार है, उसको कम करना है। उन लोगों को कृषि क्षेत्र से दूर चले जाना चाहिये जिनके पास साघन हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में प्रतियोगिता कर सकते हैं, जो व्यापार में, नौकरियों में या इसी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में प्रतियोगिता कर सकते हैं। ये प्रंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही हैं। इन लोगों को तो कम से कम कृषि क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिये।

दूसरे ढंग का जो कानून था उसका मकसद यह था कि जो खेतीहर मजदूर है, जो बटाईदार है, उसके ग्रधिकारों का संरक्षण हो। यह जो कानुन था इसका फल क्या हुन्ना इसकी आंच करने के लिए योजना स्रायोग ने एक विशेषज्ञ समिति बिठाई थी ग्रीर उस कमेटी का निष्कर्ष यह था कि बेदखली बन्द करने के लिए, बटाईदारों के ग्रधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जहां जहां कानून बनाये गये वहां वहां लाखों की संख्या में लोगों को बेदखल किया गया, कुछ छिपे ढंग से, कुछ कानून के सहारे श्रीर कुछ खुलेश्राम । उससे बड़ी विषम स्थिति बंगाल और बिहार में पैदा हुई। एक विशेषज्ञ का कहना है कि इन कानुनों ने फलस्वरूप करीब तीन प्रतिशत बटाईदार किसानों को काननी तौर पर बेदखल किया गया, १६ प्रतिशत लोगों को खुले ग्राम बेदखल किया गया कानून का विरोध करते हुए ग्रीर करीब २२ प्रतिज्ञत लोगों को स्वैच्छिक समर्पण ·यानी वालेंटरी सरेंडर के नाम पर डरा धमका कर, हटने के लिए बाध्य किया गया । किसान के जीवन में सुधार लाने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए जितने भी भ्राज तक कानुन मने हैं, उनका यही नतीजा निकला है। हाल में जो कानून बने हैं हदबन्दी के उनका क्या नतीजा हो रहा है ? हदबन्दी सिर्फ नाम ने वास्ते हो रही है। कहीं पर किसी राज्य में भी श्रभी तक पर्याप्त मात्रा में स्रतिरिक्त जमीन नहीं भिली है। तीसरी योजना की मध्यावधि रिपोर्ट में लिखा हम्रा है कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा लम्बा चाँडा प्रान्त है देश में जनसंख्या के लिहाज़ से वहां पर इस कानून के फलस्वरूप सरकार को अभी तक २४ या २५ हजार एकड़ जमीन 472 (Ai) LSD-5.

ऐसी मिली है जिसको सरकार वांट सकी है बेतीहर मजदूरों में या भूमिहीन किसानों में । महाराष्ट्र में नेवल ३० या ४० हजार एकड़ भूमि ही मिली है। इससे कहीं ज्यादा जमीन श्री विनोबा भावे ने मांग मांग कर इकट्ठी की है। २४ या २५ हजार एकड़ जमीन एक एक प्रान्त में ग्रतिरिक्त भूमि के रूप में पाने के लिए गुवर्नमेंट यदि कानन बनाती है, इतने भ्रधिक कानुन बनाती है, इतना मुद्रावजा देती है, इतना लम्बा चौड़ा संविधान का संशोधन करती है तो इसका भतलब क्या होता है, इसको भ्राप देखें । मुग्रावजा देना होता है तो बजट पर बोझा बढ जाता है और कानुन को चलाने के लिए ग्रला से प्रशासनिक व्यवस्था करनी पढती है लेकिन ग्रन्सरी नतीजा कुछ नहीं होता है, वितरण के लिए बिल्कुल जमीन मिलती ही नहीं है । जितना पैसा कानून बनाने के लिए, कानून के प्रशासन को चलाने के लिए या मुम्रावजा देने के लिए खर्च हो जाता है उतना पैसा अगर समुचित ढंग से खर्च किया जाए, उसका सम्चित विनियोग किया आए तो करोड़ों एकड़ जमीन जो अभी बिना कृषि के पड़ी हुई है, उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है, उपजाक बनाया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उन जमीनों को कृषि योग्य बनाना ही पर्याप्त था ग्रीर हदबन्दी की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं इतना भ्रवश्य कहना चाहता हं कि हदबन्दी कानून से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई नतीजा नहीं निकला है ग्रीर मौजदा सरकार की जो नीति है, उससे कोई नतीजा नहीं होने वाला है। ग्रगर सरकार संविधान संशोधन के बारे में सही तौर से सोचती है तो जं। स्रब तक उसकी कृषि नीति रही है किसान वाली नीति रही है, उसमें उसको मौलिक परिवर्तन जल्दी से जल्दी लाना होगा। हदबन्दी कानुन को इस ढंग से बनाया जाना चाहिये जिससे सरकार को वितरण के लिए, भूमिहीन किसानों को देने के लिए जमीन मिल सके । पहले तो इसके लिए यह जरूरी

[श्री किशन पटनायक]

है कि हदबन्दी के लिए कोई अपवाद न हों। चाहे कोई चाय का बागान हो या बड़ा मैंके-नाइज्ड फार्म हो किसी के लिए भी कोई किसी किस्म का अपवाद नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा होगा तब आकर कहीं सरकार को वित-रण के लिए जमीन मिल सकेंगी।

ग्रच्छे कामों के लिए सरकार इस सदन से ताकत तो ले लेती है लेकिन उस ताकत का इस्तैमाल वह बुरे कामों के लिए करती है। मझे डर है कि यह हदबन्दी कानन िस ढंग से बनाया जा रहा है उससे यह भी एक नतीजा निकलेगा कि जहां बाग बगीचों के लिए श्रपवाद है, फार्म्स कें लि*वे* अपदाद हैं वहां पक्षपात भी हो जाएगा। काश्तकार जो कि सरकारी दल के समर्थक हैं उनके लिए ग्रपवाद मान लिये जायेंगे । धगर पहले वह बाग बगीचा नहीं भी था भीर कानन बनने के दो महीने पहले से बन गया है तो उसको सही बाग बगीचा मान लिया जायेगा, लेकिन किसी ऐसे मनुष्य का बाग बगीचा जो सरकार विरोधी हो, कांग्रेस दल का विरोधी हो, चाहे वह कितना ही पराना क्यों न हो, उसे अपवाद नहीं माना जायेगा । तो सरकार एक हाथ से काम करने के लिए ताकत ले लेती है लेकिन उस ताकत को बरे काम के लिए इस्तैमाल करती है। कृषि और किसानों के मामले में गत १७ सालों का इतिहास यही रहा है। इसलिये मैं यह नहीं चाहता हं कि विधेयक गिर जाये, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि इसके पक्ष में मतदान करूं।

श्री सिहासन सिंह (गोरखपुर): उपा-ध्यक्ष महोदय, यह जो संविधान का १७वां संशोधन है, उसके मृलाधार को, जैसा कि वह है, स्वीकार करते हुए मैं गवनंमेंट के रवैये के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

ग्राटिकल ३६ जो है वह एक डाइरेक्टिव ग्राटिकल है । उसमें (वी) के ग्रन्दर प्रावि-- जन है:

"that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common-good;"

(Seventeenth

Amendment) Bill

श्रर्थात् जो रिसोर्सेज मुल्क के श्रन्दर हैं उनका वितरण इस तरह से हो कि उनसे समाज की श्रिधिक से ग्रिधिक सेवा हो सके। श्रव ग्राटि-कल ३१ जो है वह यह प्रोवाइड करता है: कि:

"No person shall be deprived of his property save by authority of law."

श्रपनी जगह वह बिल्कुल दुरुस्त है। इसके सब क्लाज (२) में कम्पेन्सेशन की बात कही गई है। मुझे दुःख यह हैकि ग्रपने देश में ग्राटिकल ३६ ग्रौर ३१ का जो मूलभूत श्राधार है उसका पालन सही रूप से नहीं हो रहा है। जहां तक प्रापर्टी का सवाल है, है, हमने ३१(ए) का एक नया ग्रार्टिकल जोड कर लैंडेड प्रापर्टी को ग्रलग करके उसके साथ दूसरा व्यवहार किया है।३१(ए)में स्टेट ऐक्विज्ञिन का प्राविजन किया और यह लिख दिया कि म्रार्टिकल १३ की कोई रुकावट उसपर लागु नहीं होगी, लेकिन केवल स्टेट पर । यानी हमारे देश में माइन्स भी हैं, वह भी किसी स्टेट के ग्रन्दर हैं, ग्रौर भी चीजें हैं लेकिन उनके लिये यह लालागुनहीं होगा। उनको हम लेने लगते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने लगते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरा होता है ग्रीर जमीन के बारे में हमारा व्यवहार भिन्न होता है। ग्रव भिम के सम्बन्ध में हम ने जो रि**फा**र्न किये हैं उनके सम्बन्ध में यह जो अमेंडमेंट है उसमें प्रथम बार यह व्यवस्था की जा रही है कि सीलिंग के ग्रन्दर किसी के पास जो जमीन होगी अगर उसको सरकार किसी

कान्न से प्राप्त करना चाहेगी तो उसका बाजार भाव देगी । श्रव "सीलिंग के अन्दर" जो शब्द हैं उनमें लिखा है कि "उस समय पर" यानी जो समय ग्राज नियत किया गया है, जिसका व्यौरा शडयल्ड ६ में हमने दिया है--उसमें सब राज्यों का व्यौरा दिया है, उत्तर प्रदेश का भी है-- उसमें दिया हुग्रा है कि जो सीलिंग का कानुन पास हम्रा है, वही रहेगा पर. लेकिन उसके सब जगह की जो जमीन ली जायेगी उसके लिये बाजार भाव से मल्य मिलेगा। फिर ग्रागे चल कर भ्रगर सीलिंग ला परिवर्तित हो जाये. भ्रयीत ग्राज जहां ४० एकड़ का ग्रौसत माना गया है जमीन का तो कल वह ३५ हो सकता है, ३० हो सकता है, १५ हो सकता है, तो भी यह "फार दिटाइम बींग" के वर्ड लिख कर दिखाने को तो जमीन के मालिकों की जमीन को घटाते हुए भी धीरे धीरे कहा जा रहा है कि हां, तुम्हारी जमीन की कीमत तो हम बाजार भाव पर देंगे, लेकिन यह माफ नहीं है कि वह जमीन क्या होगी। इस लिये मैं विधि मंबी से कहना चाहंगा कि वे बतनायें कि "फार दि टाइम वींग" के क्या ग्रर्थ होंगे। जिस वक्त जमीन लेने का कानून बनेगा वह वक्त लागृहोगा याजो स्राजबन रहा है वह लागु होगा। किसी बात की निश्चितता तो होनी चाहिये। हम ने संशोधन किया संविधान का उस में लिखा गया है कि जो सीलिंग ऐक्ट लागृहै उस के ग्रन्दर जिस की जमीन बची है वह उसकी मानी जायेगी, लेकिन भ्रगर कभी सरकार उस को लेने का दावा करेगी तो उस की कीमत बाजार भाव से दी जायेगी। लेकिन साथ साथ यह भी परि-स्थिति आज है जो कि देहात के रहने वाले हैं, जो भूमि के स्वामी हैं, उस को जोतने वाल हैं वे चाहते हैं कि उन की रक्षा हो उस में रक्षा की बात नहीं स्राती।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, इस संविधान मैं भी त्राज दो तरह का व्यवहार हो रहा है।

यह व्यवहार किस न्यायिक दुष्टि से भ्रपने लिये अच्छा है। अभी बड़े बड़े पूजी पति हमारे देश में हैं, शहर में रहते हैं। तो शहर र्योर देहात के क्षेत्रों का संतलन नहीं है। ग्राज जमीदारी गांवों में तोडी गई, उत्तर प्रदेश में भी तोडी गईं. लेकिन ग्राप को जान कर हैं रत होगी कि सिर्फ देहात की जर्नादारी तोड़ी गई, शहर की जमीदारी आज भी बनी हुई है : हालांकि जमीदारी तोडने का कानन पास हो चका है और बहत देर हई जब पास हम्राया, लेकिन उसे शहरों पर लाग, नहीं किया गरा। अभी लखनऊ शहर की जमी-दारी ज्यों की त्यों बनी है, ग्रागरे की जमी-दारी ज्यों की त्यों बनी है, कानपूर इलहाबाद बनारस की जमीदारी ज्यों की त्यों बनी हुई है, गोरखपूर शहर की जमीदारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। केवल उन में जो नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया की जमीदारिया हैं वे शहरी जमीदारियों में नहीं स्राती हैं। हम ने कानन बनाया भिम सुधार करने के लिये लेकिन ग्राज शहर वालों के साथ पक्षपात हो रहा है। शहर के रहने वालों की तरफ और ध्यान है सरकार का ग्रीर देहात के रहने वालों की तरफ स्रौर ध्यान है। देहात की जनता मुक है, वह बर्दाश्त करती है, लेकिन समय ग्रा सकता है कि वह को देखकर उठ पड़े भ्रौर जमीदारी तोड़ी तो फिर शहर ग्रीर देहात की जमीदारियों के ग्रन्दर भेदभाव क्यों हम्रा। वास्तव में सम्पत्ति सब एक है। उदाहरण के लिये भाप देखिये कि मैंने १० हजार रु० का शेग्रर कैपिटल ले लिया किसी बैंक का, ग्रगर उस बैंक का राष्ट्रयकरण हो गया, जैसे कि बीमा कम्पनियों का राष्टीय-करण हो गया, हवाई जहाजों का राष्ट्रीय-हम्रा, इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय-करण हुम्रा, भ्रौर उस के शेम्रर वैल्यु की जो माकट प्राइस उस वक्त थी उस की पांचगनी

[श्री सिंहासन सिंह]

छ गनी अधिक कीमत दी गई. तो उन १०,००० ६० की तात्कालिक शेग्रर वैल्य ग्रगर २०,००० र • हुई तो मेरे जेसे शेग्ररहोल्डर को १ लाख के करीब दिया गया। लेकिन ग्रगर किसी की १०,००० रु० की जमीन ले ली. दस बीघे जमीन लेली तो उस का बाजार भाव नहीं दिया जाता। उस की २ ६० मालगजारी फी बीघे के हिसाब से चालिसगुना तीसगुना, बीसागुना, कुछ दे दिया जाता है। जो १० हजार का कैपिटल लगाया वह भी स्वाह हुन्ना, वह भी उसे नहीं मिलता। इस को क्यों नहीं द बाजार भाव से होना चाहिये। सम्पत्ति एक है, चाहे वह शहर में हो, चाहे फैक्टरी में हो, चाहे जमीन में हो, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति हो, उस सम्पत्ति को लेने में सरकार की नीति एक सी होनी चाहिये। लेकिन आज दो नीतियां हैं। इस संविधान संशोधन में मेरा विरोध केवल इस से हैं।

इसी तरह से ग्राप देश के हित में ग्रार्टिकल ३ ६ के उद्देश्य की पति करने के लिये और समाज के धन को ठीक से वितरित करने के लिये जो कदम उठाये उन में सब ग्राप के साथ हैं. लेकिन कदम उठाने में दो तरह का व्यवहार हो यह ठीक नहीं है। जिन का धन कम्पनियों में लगा हमा है, जो म्रधिक से म्रधिक कमाने वाले व्यवसायी लोग हैं वे सरकार के रुपयों से लाभ उठाते हैं और कम्पनियों के मालिक बने हैं, उस में सरकार कुब रुपया नहीं लेगी। वेलोगक रुपयालगाकर सरकार से ही रुपया लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे विधि मंत्री क्लकत्ते से ग्राते हैं। ग्रगर वे पता लगायें तो जितने भी इंडस्टिलिस्टद्वस हैं उन के ऊपर सरकार का करोंडों रुपया बाकी है। लेकिन जब उन के व्यवसाय के राष्ट्रीय-करण की बात आयेगी तो आप उन को दाम देंगे उन के शेग्ररों की वैल्य के हिसाब से ग्रीर वाजार के भाव से । ग्राटिकल ३१ जो उस में कहा गया हैं कि सबकी प्रापर्टी

लेने में कानून के द्वारा जो मुझावजा प्रति एकड़ नियत किया जायेगा वह लागू होगा। म्रार्टिकल ३१ में स्टेट को ग्रलग कर दिया ग्रोर प्रापर्टी को ग्रलग कर दिया। ग्रब श्राप देखिये कि यह ३१ (ए) क्या है। ग्रगर खाली आर्टिकल ३१ होता तो वह सब भिम पर लाग होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। श्राखिर यह कब तक चलेगा। मैं जानना चाहता हं कि म्रार्टिकल ३६ का जो उद्देश्य है उस की पूरा करने केलिये गवर्नमेंट कब कदम उठायेगी। मैं चाहुंगा कि जब मंत्री महोदय जवाब दें तो बतलायें कि क्या कभी यह ग्राशा हो सकती है ।

(Seventeenth

Amendment) Bill

श्रभी यह हम्रा कि कंसेटेशन श्राफ वैल्य के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई। महालोनोविस कमेटी बनी बडे शोर गल से यह जानने के लिये कि देश में जो धन पैदा हम्रा वह किघर गया। उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिली या नहीं मैं नहीं जानता। प्रखबारों में तो यह निकला कि ग्रा गई लेकिन मभी कमेटी की रिपोर्ट सदन में नहीं आई। न मझे पता है और न आप को पता है कि वह ग्ररबों रुपया जो खर्च किया गया वह कहां गया। यह कमेटी तो यहीं रही, पर ग्रब एक दूसरीकमेटी का निर्माण होने जा रहा है यह देखन के लिए कि छोटे ग्रौर बडे में ग्रन्तर क्या है। अगर कमेटियों के निर्माण से ही संतोष करना है तो कर लें। कमेटी की रिपोर्ट माने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस प्रकार कमेटियां बनाते चले जाने से काम चलने वाला नहीं है और पंजी कुछ जगहों पर इकटठी होती चली जायेगी।

सदन में ग्रागे भी चर्चा हई थी ग्रीर श्रभी भी कहा गया कि इंडस्टीज के लिए लाइसेंस कुछ व्यक्तियों ने ही ले लिये। वे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ग्रधिकांश लाइसेंस ले लिये ? श्रापने कम्पनी कानुन में संशोधन किया कि किसी के पास दस से ज्यादा मैनेजिंग एजेंसियां नहीं रहेंगी। इसका नतीजा यह हुन्ना कि घर भर में सब के नाम दस दस मैनेजिंग एजेंसियां हो गयीं, लेकिन किसान का पांच ग्रादमियों का परिवार चालीस एकड़ से ग्रधिक जमीन नहीं रख सकता। कम्पनी कानून के अनुसार बाप दस मैंनेजिंग एजेंसियां ग्रलग रख सकता है, पत्नी दस ग्रलग रख सकती है, लड़का स्रौर लड़की दस दस मैनेजिंग एजेंसियां ग्रलग ग्रलग रख सकते हैं, लेकिन जहां भूमि का सवाल है, स्त्री, पुरुष भौर उनके बच्चे सब मिला कर चात्रीस एकड से ग्रधिक भूमि नहीं रख सकता ग्रापने ऐसी व्यवस्था की है कि सब के साथ समान ब्यवहार नहीं हो रहा है। विरोधी दल वे लोग इसका विशेष कारण बताते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं देखता हं कि हम पर पूंजीपतियों का काफी प्रभाव है। वह प्रभाव चुनाव के रूप में हो या किसी ग्रौर रूप में हो, लेकिन प्रभाव है। वे लोग शहरों में बड़े लोगों को दावतें देते हैं पर किसानों के पास ऐसे साधन नहीं हैं। हमारे डा० देशमख साहब ने काश्तकारों का एक फोरम बनाया था किसानों के हित की चर्चा करने के लिए। जब तक वह मंत्री रहे वह फोरम चला, लेकिन अब उस कोरम की भ्रवस्था क्या है ? कारण यह है कि काश्तका**रों** के पास पंजीपतियों की तरह लोगों को चैम्स-फोर्ड क्लब में दावत देने के साधन नहीं हैं जहां वे सिचवों को बुलाकर उन से परामशं कर लेते हैं। यह चीज ब्राज है। इस ब्रोर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हं कि संविधान की घारा ३६ पर ग्रमल कब तक होगा, कब तक धन का संग्रह कुछ व्यक्तियों के पास होता जायेगा ? ग्रगर ग्राप किसानों के लिए यह करते हैं कि एक परिवार चालीस एकड़ से ग्रधिक जमीन नहीं रख सकेगा, तो सेठों के लिए भी कर दीजिये कि एक परिवार चालीस लाख से ज्यादा रुपया नहीं रख सकेगा या चालीस लाख से अधिक की जायदाद नहीं रख सकेगा लेकिन उनके लिए कोई रोक नहीं है। वे

करोड़ों अरबों की जायदाद रख सकते हैं। इसे रोकना पड़ेगा। अगर आपको आर्टिकल ३६ का पालन करना है तो ईमानदारी से कहिये कि सब की सम्पत्ति एक समान है, सब प्रकार की सम्पत्ति के लिए एक तुला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रकार की सम्पत्ति के लिए तूर प्रकार की सम्पत्ति के लिए दूसरी पुला रहे और दूसरी प्रकार की सम्पत्ति के लिए दूसरी तुला रहे।

कहा जाता है कि जमीन के बारे में खास नीति इसलिए अपनायी जा रही है कि खेती की उन्नति हो। इसके लिए जापान का उदाहरण दिया जाता है कि जापान में जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद खेती में बहुत उन्नति हुई। यह ठीक है। मैंने जापान में देखा है कि जयीदारी प्रथा की समाप्ति के बाद खेती में काफी उन्नति हुई है। हमारे यहां भी जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जब किसान जमीन का मालिक बन कर खेती करने लगा तो खेती में उन्नति हुई । लेकिन मैं गवर्नमैंट का ध्यान कुछ बातों की म्रोर दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे कम्युनिटी डेवेलपमेंट के मंत्री इस समय सदन में नहीं हैं।

यहां कोग्रापरेटिव खेती का नारा लगाया गया भ्रोर कहा गया कि भ्रगर कोग्रापरेटिब खेती हो तो देश की बहुत तरक्की होगी। इसके स्रांकडेभी कागजों में दिये गये। लेकिन इस का परिणाम यह हुम्रा कि कोग्राप-रेटिव खेती के सवाल को लेकर स्वतंत्र पार्टी चुनाव में सफल हुई। उन्होंने काश्तकारों को यह कह कर बहकाया कि इस कोग्रापरेटिव खेती की बात कर के सरकार उन से उनकी जमीन छीन लेना चाहती है। इधर सरकारी ग्रधिकारी, जो कोग्रापरेटिव खेती के लिए जिम्मेवार हैं, वे श्रपने महलों से, श्रपने श्राफिसों से, बाहर नहीं निकलते। मैं स्राप से गोरखपूर की बात कहता हं: मैंने ग्रपने यहां के कोग्राप-रेटिव ग्रधिकारियों से कहा कि तुम काम नहीं करते इसलिए हमारी भाज क्षति हो रही

[श्री सिंहासन सिंह]

है। तम्हारे काम न करने के कारण बहत से लोग चनाव में ग्रा गये वोटरों के: यह कह कर कि को ग्रापरेटिव के नाम पर सरकार किसानों की जमीन लेना चाहती है। ब्राज तुम कु अ कर के दिखायो। लेकिन वह कुछ करते नहीं हैं। भ्रौर न इधर से कोई प्रोत्साहन मिलता है। कोग्रापरेटिव का वही सन १६१२ का पुराना कानून चालू है जिसमें ग्रधिकारियों को बहत पावर मिली हुई है। भाज ग्रवस्था यह है कि ग्रगर दो चार ग्रादमी मिल कर खेती करना चाहें तो उनको कोई सुविधा नहीं है। दस ग्रादिमयों से मिलना कठिन है खीर मिल भी जायें तो फिर हम को रजिस्टी करानी होगी, और उसके लिये दो महीने तक दौडना पडेगा । उसके बाद सरकारी सहायता मिलेगी । ऐसा कानन क्यों नहीं बना दिया जाता कि जो दो चार पांच दस ग्रादमी मिल कर खेती करना चाहें उनको सरकार सहायता दे। लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं होता। ग्रगर इस वारे में सवाल किया जाये तो डे साहब खडे हो कर कह देंगे कि दस लाख को आपरेटिव बन गयी हैं। लेकिन कहां बब गयी हैं। वे केवल कागजों में हैं। हम तो देहात में रहने वाले हैं, हम देखते हैं कि वे कहीं नहीं हैं।

एक बार एक हल्ला हुग्रा कि एक मजदूरों की सेना बनायी जायगी, एक लेंबर का बेंक बनाया जायेगा जिससे खेती की तरक्की होगी। यह काम भी कागज पर बहुत हो गया लेकिन देहात में यह सेना कहीं दिखाई नहीं देती। इस तरह की कागजी कार्रवाई कब तक चलेगी?

मैं सेन साहब से अनुरोध करूंगा कि वह संविधान की धारा ३६ पर ध्यान दें और अगर जरूरत हो तो ऐसा संशोधन लावें कि सारी जायदाद, चाहे वह जमीन में निहित हो या रुपये में निहित हो या मकानों में निहित हो, समान समझी जाये धौर सब के साय समान व्यवहार हो। तभी हम देश में वैलफेयर स्टेट की ग्रवस्था ला सकेंगे। तभी हर ग्रादमी समझेगा कि हमारे सब के समान हित हैं।

इन अब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्रापने किसानों को उनकी जमीन की मारकेट वैल्यू देने की ब्यवस्था की है और एक बार तो उनको यह कहने का मौका रिलेगा कि हमारी जमीन का भी बाजार भाव होने जा रहा है।

Shri P. N. Kayal (Joynagar): Sir, our Law Minister Mr. Sen was drawing Rs. 30,000 in his profession. He has sacrificed all that for this country and we are very happy that today he is here. But I do not know whether this Bill has come from his mind or from somebody else. I have also heard Mr. Menon who happens to be the ex-Chief Minister of Travancore State. What does he mean by the phrase 'land reform'? Do you want to get more production? If so, what are you going to do? To give the lands to the tillers-that means to make the tillers owners or to give the land to the cooperatives or to give it to the landlords or to give it to the ryots? You must tell me. Is it merely for the sake of land reform? We are anxious to get more production. come from an agricultural family and from a village too. From my childhood I lived with those poor people of those hamlets in those broken villages of India. I do not know what is the intention of this Bill. It depends upon the intention actually; it is those intentions on which I propose to support the Bill. Otherwise from the core of my heart I oppose this Bill, if the intention is otherwise . . . (Interruptions.) Let me analyse it. Government comes forward with the Bill to give power to the State Governments to acquire any land that falls even within the ceiling level for any purpose. It will not be for public purpose. They say, "in pursuance of the land reforms policy of the Government that has already been endorsed by this Parliament, we are going to introduce this measure". Now, this Parliament may very well ask the Government, so far from what reforms have already been brought in, what have the Government done for its implementation and also for growing more food from all that. This House has every right to demand a reasonable explanation from the Government for its performance on that count.

Let us make a survey. The estates of intermediaries were acquired. How have those lands been settled What have those land the tillers? reforms officers done with those lands? Have those lands really been settled with the actual tillers of the soil or your officers have taken bribes and settled those lands in the hands of (An Hon. Member: wrong people? For themselves). And after doing ali that, what production have you got out of it? The new tenant-owners were given most uneconomic holdings. After the abolition of the zamindar: system the tillers of the land were given uneconomic heldings. Government gave them seeds, manures, cattle purchase loans etc. The amount that has been given to the tillers cannot even buy a tail of a cow. Are the planners making a farce of it? I do not know what is in the minds of the planners. Have they any connection with land? हिन्दी में इसको यों कहा जा सकत। है। "जिसके हाथ में हल होगा जमीन उसकी होगी तो उस तरह से पालकी जिसके हाथ में होगी, बहु उसी की होगी।

Is it democracy, is that logic? (An Hon. Member: Please translate it). It means this. If you make the tiller the owner of the land then could the man who carries the bride in a palanquin be the owner of the bride?

The case of supplying seeds and manure also has met with the same fate.

Then the Government improverished the big landholders by putting up a ceiling. Actually these holders were playing the role of bankers in the villages. As a result of the ceilling improsed on their holdings they refused or were incapacitated to help the tillers in the matter of investment for cultivation. And that was true not only for investment in cultivation but also for the purpose of sradhs, marriages and other ceremonies. Thus the villagers at last lost their bankers, but the Government failed to give any proper substitute for that. The result is disastrous. The backbone of the village community was broken, and today the relation between the landholders and the rest of the agricultural community has been embittered badly. As a result, village squabbles and litigation have increased, and fire has been set on the peaceful homes of the innocent village community.

The intermediaries, that means the zamindars. having ben pushed out, a direct relationship between the Government and the tiller has been established. No doubt that is good. But unfortunately there is none to look after these poor tillers in time need, and the land reform officers and tehsildars have turned out to be more dreadful and oppressive than those zamindars. These officers and officials go to collect the rent, well-armed with all the Government weapons, in villages, irrespective of any failure of crop in any particular season. Everybody's business is nobody's business. Who cares whether there is any crop failure or not? The tiller must have to pay the rent at the cost of his cattle, household articles or utensils, or by all possible means.

But this was not so during the time of the intermediaries. They used to help their tenants in every possible way, and in case of crop failure the rents were invariably being remitted. Therefore today they are often heard to say that the zamindari system was far better than the oppressive Government officers and officials. So gra-

[Shri P. N. Kayal]

dually the tillers are getting themselves indebted more and more, and production is coming down and down, and the life of every villager has become miserable and most miserable indeed. Such is the picture of rural India today. Things have reached the bursting point.

Here I must say a few words about these intermediaries. When this system was abolished the zamindars were only too glad to hand over their estates in lieu of a compensation. Because, after independence the rent-payers were developing resistance in paying their rents. The zamindars also were all along making an unearned income. So it was found by them as gainful to give up their estates in lieu of compensation. So they gave their consent to the zamindari abolition.

But that is not the case with the landholders today. They rvotwari are not making any unearned income. They had to supervise their land by themselves. They had to handle their labourers and had to keep their eyes on their work in rain and knee-deep They were very sympathetic mud. towards the villagers and with the rest of the village society in their joy and sorrow from day to day. They built tanks of drinking water in the villages, schools and hospitals for the benefit of the village community. They also played invariably the role of bankers, and in times of need they would come forward to spread out their helping hands to the village community. They produced good children in the villages who brought light in darkness, who fought for every cause of the village.

So the holdings of such people cannot be called estates, as they never behaved like estate-owners or zamindars making an unearned income.

Today we must admit that the villages are very fast losing life and it is going to be a desert.

It seems by this Bill the Government are misled, if it is one to bring down ceiling, to take away from the landholders whatever little comfort still remains for the village community

(Seventeenth

Amendment) Bill

It is not only that. It seems today the town has waged a war against the village to destroy it. You put up a ceiling and now again you propose to bring down that ceiling if I am correct, for no valid or sound reason, and without caring for what happens to them and their children after they are pushed out from their land. At the same time, you are not in anyway curbing the incomes of those city people who own the tea and coffee gardens, fisheries, etc., and who own several palatias buildings in the cities. You are going to commit a terrible social injustice. You are discriminating against the village. That is why I say the town perhaps has waged a war against the villages. It is simply unfortunate.

May I ask, who lives in a lower standard of life, who does the dirty work, who produces food for nation, who are deprived of the amenities of city life? It is the villagers. These landholders put physical labour on their land as much as the labourers themselves and they wait on their labours in rain knee-deep mud as a friend of ourers and live a humble standard of life. They work more but get less; whereas the people in the town doclean work on tables and chairs from 10 to 5, and riding in buses and trams. with all the facilities of electricity and water supply walking on metalled roads and producing nothing. They work less, but get more. Who deserves more incentives, more remuneration, may I ask? Who gets more the man who does the dirty work or the man who does clean work?

Today, wherever you go in the villages, you will find the enlightened section of the village community are: tention.

gradually deserting the villages, leaving behind a helpless, forlorn and unkind hamlet in the villages. The number of crimes has increased and poverty and misery have aggravated. You will find the tattered clothed mother in a fallen hut crying in vain with a baby in her arms also crying, finding no milk in the dried-up breast of the starving mother. You will also find the father moving about with empty beggar's bowl from morning till night, from door to door. So, today is the day we will have to steer our wheels on agricultural reform in a reversed gear. Only when the House is satisfied that a satisfactory result has been already achieved out of all the land reforms that have already been gone through then only this House should agree to bring down the ceiling of the ryots land-holdings. That is my humble con-

Sir, this measure may make communists of this country dancing. As we know, their goal today is only to bring in discontent and a feeling of frustration within the country. Their idea is: एली मेली कोरे दे मा, लटे फटे खाये । That is to say, the more you create disorder, the more you ¿ain. उल्टा-सीधा कर दो, बस नफ़ा हो जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : खुव भालो

Shri P. N. Kayal: Sir, are we here today to welcome that? Shall we have to live in a situation where human value is trampled with foot? We want to breathe a free and fresh air. Let not the ryot's ceiling be touched just now. Give proper price for their produce, balancing it with the price of other consumer goods.

Mr. Deputy Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri P. N. Kayal: I shall end in a minute, Sir. You will get more production then. In the name of reforms, do not deform the land. Allow the villagers to live in peace and to work with more energy and with a sense of security. They will do the job for the nation. Bring back the old good relationship in the village community. Sense of security is the question today.

Amendment) Bill

Now, I want to finish with one last word of importance. If the purpose of the Bill is to acquire the uneconomic holdings, say, one acre or half an acre of land, with the idea bringing homogeneity and not to bring down the ceiling, then and then only I fully agree with this Bill.

Dr. L. M. Singhvi: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I often wondered what persuaded the hon. Member who spoke before me to make an eloquent speech and then to water it down by agreeing with the Bill which he opposed all through his speech. The hon. Member who preceded me delivered a powerful speech, making a plea against the very principle of the Bill which is before the House, and yet he felt persuaded to finish his speech by saying that he supports the Bill because of its underlying intentions. Must I remind him of what has been said very often in this House that the way to hell is paved with good intentions.

Hitopadesha gives us the history of a prince and a bear, who was his friend. While the bear was guading the prince in sleep, he found an offending fly. What he did was to take a sword in hand and strike the prince himself in order to put an end to the offending fly. It appears that the good intentions, of which the hon. Member who spoke before me under which he took a refuse in supporting the Bill, are the good intentions of the bear, the friend of the prince, who in order to put an end to the offending fly, took the sword in hand to kill the prince.

Sir, I cannot but express my great disappointment that this Bill was brought forth in this House in a very casual, cavalier manner. I sympathise [Dr. L. M. Singhvi]

with the lot of the hon. Minister of Law who happens to be an eminent lawyer and who, often in season and out of season has to support Bills of all kinds, good, bad and indifferent. I suppose that is one of the occupational hazards of being a Minister. I feel all the more sorry for him because during his tenure of office, he has had to bring forth Bills of a highly questionable character. He had to father legislation which could not give him the happiness and the pride of a progenitor. I am sorry to say that this Bill which was introduced before this House discloses a completely insensitive casualness of approach to legislation. When the Law Minister introduced the Bill, at the time of making a reference to the Joint Committee, he sought to append as many as 124 enactments in Ninth Schedule, and in a few months the Law Minister was in a position to come before the Joint Committee and-and this I think was an act of open mindedness though a belated act of open-mindedness-ask that 8 out of the 124 enactments may be Certainly the Law Minister omitted. owes an explanation to this House as to how it transpired that as many as 124 enactments were first sought to be appended to the Ninth Schedule and later on it was realised by the Government and the Planning Commission that 88 out of the 124 enactments were unnecessary. Is this the way this House should be treated? As a matter of fact, this is tantamount to being indifferent to the House and showing disrespect to the House. which I hope the Law Minister and the Government would not countenance in future.

I would also like to give expression to the sense of dismay which every scholar who wishes to analyse this Bill has to encounter. There is no reliable economic data on which this is based. There is no sustained analysis of economic data in relation to our land problems from which this Bill originates. There is not even a pro-

per legislative analysis of the various enactments which are sought to be protected now. Indeed, there is not even a satisfactory answer to the queries in respect of the various legislative enactments which had struck down by courts of law in this country and which are now sought to be revived through this Constitutional amendment. I think the lack of data is so pervasive that it would behave the Government much better to wait for sometime more to make a deep study of the problems and then to bring forth a comprehensive legislation based on some economic data. I am not sure that the Law Minister would be able to tell this House as to what is the economic rationale of this Bill, beyond making a platitudinous generalisation that it has been necessitated because some problems had not been anticipated and because we wish to ensure security of tenure and undertake a programme of land re-distribution. These are cliches. We must know what the programme of the Government is in a precise way. We must know how far Government has already made use of the existing legislation.

I should like in this connection to refer to three reports briefly, which are available to us on some of these problems of land reform. The report is Consolidation of Holdings -Methods and Problems which was published by the Planning Commission in 1957. Another report is that of the committee of the Panel on Land Reforms which was published in 1959 and the third is the Progress of Land Reform published in 1963 by the Planning Commission. I should like, in this connection, to draw the attention of the House to what the report on Progress of Land Reform has to say in para 54:

"It is difficult to make an estimate of the extent of culturable waste lands that may be available for distribution. The total geographical area of India is about 811 million acres. Land-use statistics are available for about 721 million acres (1956-57) which are classified as follows:

	Million	acres
Forest		126
Not available for		
cultivation		116
Other uncultivated		
lands excluding		
fallow lands		98
Fallow lands		59
Net area shown		322
Tot	al	721

I would like to know whether the Government can go no further except stating what is the total area of the country or what land use statistics were available in 1956-57, according to which 721 million acres in all have been accounted for. Even in that accounting, you will find that there are categories which are overlapping. There is the category of land which is not available for cultivation; there is the category "other uncultivated lands excluding fallow lands" and there is the category of fallow lands. These three categories, as a matter of fact, make up the total of land which is available today for cultivation. Nothing of any worthy dimension has been done so far by the Government to these culturable wastelands in this country. This is a record of which no Government can be proud and for which any self-respecting administration should be sorry In view of such a record, is it necessary really, is it really plausible that the Government wants to undertake this constitutional amendment merely to redistribute the land or to bring lands under cultivation by the common tiller? These, I think, are misleading assurances to the House. These are cliches and platitudes by which the House cannot be convinced.

I would like to draw the attention of the House to the fact that the Law

Minister has time and again tried to assure the House that what this constitutional amendment seeks to do is not to incorporate in the Constitution a new principle. All that he is prepared to admit is that this is merely a readjustment of certain things, but the constitutional principle had already been accepted. I challenge this statement, with great respect to the Law Minister. I would submit that this is not based on a proper appreciation of our Constitution or how it came to be made. I should like, in this connection, to refer to the fact that the controversy relating to what eventually came to be article 31 was so intense that it was recalled at a later stage in the Constituent Assembly that the differences could even break up the whole Constitution and cause our ship to founder on the rocks.

At the stage of Constitution-making, it was clearly put before the Constituent Assembly that there were two alternatives: the alternative of not allowing any resort to courts of law, of leaving all this matter to ordinary legislation and the alternative of constitutional protection to the rights of property. The Sub-Committee, after extensive consideration of this problem on this matter, formulated a proposal which appeared as clause 27 in its first report. It was as follows:

"No property, movable or immovable, of any person or corporation, including any interest in any commercial or industrial undertaking, shall be taken or acquired for public use unless the law provides for the payment of just compensation for the property taken or acquired and specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined."

When this clause came up for discussion, it was pointed out that like the Fifth Amendment of the U.S. Constitution, this would bring into existence a spate of litigation and may stand in the way of beneficent land

[Dr. L. M. Singhvi]

legislation. In particular. Pandit G. B. Pant expressed the apprehension that the U.P., Zamindari Abolition Act may be actually defeated as a result of such a clause being adopted in the Constitution. At that time, Sardar Vallabhai Patel observed in the Constituent Assembly that it was wrong to assume that the object of the clause was to provide for the acquisition of zamindaris, because he thought that by the time the clause became law, almost all the zamindaris would have been liquidated. Of course, such a sanguine hope was to be belied because land reforms in this country could not be expeditiously implemented.

The clause was further revised and what was eventually accepted was a compromise. This compromise was based on the acceptance of the assumption that courts of law would be available to aggrieved persons and on the assumption that compensation would be paid. Therefore, it is wrong and entirely misleading to say that this constitutional amendment does not seek to bring about any new legal principle in the Constitution of our country. I do not have the time at my disposal, but the Constituent Assembly debates and the reports of various committees are replete with material which would prove that the position taken by the Law Minister is not correct.

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra): Is he referring to the history of article 31A or 31B?

Dr. L. M. Singhvi: That is a well-known fact. I am not speaking of the amendments. I am speaking of the original provision in the Constitution which was originally brought into existence. I am not speaking of the various amendments which have watered down the principle which was initially accepted by the Constitution. The claim that the Law Minister has made is that this is in consonance with the Constitution as it was origi-

nally framed and that this constitutional amendment is only a readjustment and not a departure from any of the principles adopted in the Constitution. That is why I was impelled to bring these materials before the House.

Be that as it may, I would like to refer in the first instance to the legal principle involved in this case. The principle is that it is wrong, it is an anathema to all legal conception to retrospectively validate a legisaltion which has either been struck down or which has been in operation for some time. Retrospectivity is repugnant to the norms of jurisprudence. It is true that this House has in its wisdom in the past enacted certain legislative enactments with retrospective effect. But I think taht if this habit became chronic and is repeated too frequently because the Government happens to have a large majority, it would be setting up wrong conventions. I would like to show what the result of such retrospective operation of the constitutional amendment would According to the report of the Joint Committee, this Bill now seeks to append 44 legislative enactment to the Ninth Schedule.

Now, Sir, it appears to me that even these enactments which are now sought to be included in the Constitution have not been properly considered, the necessity has not been properly shown not even to this House. do not know whether the Minister proposes to go into each legislation and show to the House as to why such an extraordinary step has been necessitated. But I am sure that he has neither the time nor the inclination nor perhaps the necessary supporting material to substantiate any such claim regarding these 44 enactments which are sought to be protected by the Constitutional amendment.

15.00 hrs.

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): Sir we circulated the reasons

to every member of the Joint Committee. I took the personal troublenot trouble, but discharged a pleasant duty-of explaining the reasons to all members of the Joint Committee. You were presiding over it, Sir, and you know it.

Dr. L. M. Singhvi: I am glad that the Law Minister has referred to this matter. I am also thankful to him for accepting many of our suggestions in a spirit of open-mindedness in the Joint Committee. I am grateful to him that he did not tenaciously cling to any proposition, except this that the Joint Committee itself, as I have pointed out in my minute of dissent, was greatly restricted because of lack of time. There was pressure of time and it was not possible to consider this whole group of legislation, hundreds of legislative enactments, in great detail and to scrutinise the rationale of each and every legislative enactment.

I would, for example, like to inform the House that the court handed down a judgment in Writ Petition 1 of 1963 in the Madras This is a Land Reforms Act case. case of Naidu versus the State of Madras along with various other connected cases. This legislative enactment was struck down by the Supreme Court because of the definition of "family" adopted in this enactment. I would like the Law Minister to tell us why it is necessary to insist on the definition of "family" which the Supreme ourt has in its wisdom rightly pointed out has nothing to do with the fulfilment of the objects which are in view and which pursue or promote the discrimination which is not the objective of the Constitution. We are doing something which is repugnant to the Constitution, which is contrary to the spirit of the Constitution and, if I may be permitted to say so, it is a fraud on the Constitution. Are not rights against discrimination as valuable as the various socio-economic objects which are sought to be achieved by this legislation? Are we to say that the rights of the Constitution

have always to remain subservient to certain changing and shifting economic policies of the Government? I will point out to you only a portion of this judgment wherein the Supreme Court says:

"The provision of s. 5(1) results in discrimination between persons equally circumstanced and is this thus violative of Art. 14 of Constitution. This will be clear from a simple example of an undivided Hindu family which we may give. Take the case of Joint Hindu family consisting of a father, two major sons and two minor sons, and assume that the mother is dead. Assume further that this natural family has 300 standard acres of land. Clearly according to the personal law, if there is a division in the family, the father and each of the four sons will get 60 standard acres per Now apply s. 5(1) to this head. family. The two major sons being not members of the family because of the artificial definition given to "family" in s.3(14) of the Act will be entitled to 30 standard acres each as individuals and the rest of their holdings i.e. 30 standard acres in the case of each will be surplus land. But the father and the two minor sons being an artificial family as defined in s. 3(14) will be entitled to 30 standard acres between them and will thus lose 150 standard acres, which will become surplus land. This shows clearly how this double standard in the matter of ceiling read with the artificial definition of "family" will result in complete discrimination between these five members of a natural family. Under the Hindu law each member would be entitled to one-fifth share in the 300 standard acres belonging to the family. Under the Act however the two major sons will keep 30 standard acres each while the father and the two minor sons together will keep 30 standard acres which work out to 10 stan[Dr. L. M. Singhvi]

dard acres each. The two major sons will thus lose 30 standard acres each while the father and the two minor sons will lose fifty standard acres each."

Then it goes on further to how this discrimination will work. But it is clear that there can be no legitimate objective of land reform which would be fulfilled by discriminating between two major sons, who will get 30 acres each in the given illustration, and between the father and his two minor sons, who all told will get only 30 standard acres for the three of them. What kind of objective are we seeking to fulfil through legislative enactments such as these. If I had the time. Sir. I would have shown to the House that, by and large, the whole approach of including enactments as a whole, enamasse approach which is based on circuiting, of taking the path of least resistance and assuming the widest amplitude of powers which the executive has no right, in a limited constitutional government, to do.

Before I conclude, Sir, I have a point to make which I think is very important. Clause 2 of this Bill uses a legal euphemism which, I think, is also misleading and which may actually operate as a fraud on the Constitution. Clause 2 says:

"Provided further that any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto...."

Now, Sir, what is the meaning of this expression "for the time being in force." What it means really is that

the Constitution is being thrown to the winds. What it really means is this that every State legislature will be able to enact amendments to ceiling legislation which is presently in force and even those amendments will not be subject to this Constitutional amendment. This is a travesty of the constitutional process. It is a travesty of justice and fairplay. am sure the Law Minister, who is an eminent jurist himself, will at least consider this, and even if such a constitutional amendment has enacted by this Parliament, even the Planning Commission considers it absolutely essential that such я blanket constitutional amendment. such an ill-conceived measure, has to be passed by the Parliament at the behest of the Planning Commission because they say that economic progress otherwise is not possible, this House would not be stalked into this erring piece of legislation which protects ceiling legislation in force today but exempts ceiling legislation as may be enacted from time to time in manner in which the State legislatures may choose from the operation clause 2 of the Amendment. This is a blanket delegation of power and it is in derogation of the Constitution.

Sir, I rise to oppose this Bill which is before us, on account of this ground and many other grounds which I have had occasion to state in my minute of dissent. I hope the hon. Minister will show at least a measure of open-mindedness on this matter and rise above partisan considerations in accepting at least an amendment for not exempting future ceiling legislations from the provisions of the Constitution.

श्री दें जि पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के १७वें वर्ष में संविधान में १७वां संशोधन प्रस्तुत है। संयुक्त प्रवर समिति ने इसके बारे में कुछ, सुझाव दिये हैं। इस भू-मुधार विधेयक को लाने का उद्देश्य देहात की गरीबी को दूर

करना है। प्रवर समिति ने जो सुझाव दिये हैं उन पर मैं अपने विचार ग्रापके साम रखना चाहता हुं।

प्रवर समिति का एक सुझाव यह है कि यदि निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर किसी व्यक्ति की ऐसी भिम, जिस पर कि वह खद काश्त करता हो, सरकार भ्रपने ग्रिधिकार में ले ले तो उसे बाजार दर पर उस जमीन का मन्नावजा देना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया इस भ-सूघार विधेयक को लाने का उद्देश्य देहात के लोगों की गरीबी को दूर करना है। काश्तकार के पास जो जमीन होती है उसी पर उस से खाने पीने श्रादि की व्यवस्था निर्भर है। इसलिए पैसा देने का जो सवाल है ग्रीर बाजार दर का जो सवाल है उस में बहुत कठिनाई ग्राती है। कोर्ट में जब सवाल जाता है तब हर एक काश्त-कार वहां जो बिकी होती है जमीन की, उस तमाम रकम को पूल करके जब दर मुकर्रर करता है तो उससे काश्तकार को काफ़ी नुकसान होता है। मेरा सुझाव यह है कि जो उपज का साधन है, ५ एकड, १० एकड काश्तकार के पास जुमीन है, उस पर वह खद काश्त करता है और उसके भौरत, बच्चे यह सब उस पर काम करते हैं और वही उनकी श्राजीविका का साधन है तो बजाय पैसा देने मे उनको जमीन देनी चाहिए।

बहुत से प्रोजैक्ट्स हमारे देश में बने हैं, इलेक्ट्रिसटी वहां पैदा हुई है लेकिन वह प्रोजेट्स इस प्रकार बने हैं कि हजारों ग्रौर लाखों किसान जो कि वहां रहते हैं उनकी अमीनें प्रोजेक्ट्स के बनने में ग्रा जाती हैं। मेरा कहना यह है कि उनकी जमीन जो एक्वायर कर ली जाती है उसके बदले में उन्हें जमीन ही दी जानी चाहिए, पैसा देने से काम नहीं होगा। इसलिए यहां बाजार दर से जो पैसा देने का मुझाव है उस के बजाय जमीन देने का मुझाव है उस के बजाय जमीन देने का मुझाव ही किसान ग्रपनी

भ्रार्थिक स्थिति को सुधार नहीं सकता है।

एक दूसरा कारण यह भी है कि उच्चतम सीमा जिसको कि सीलिंग कहते हैं वह हमने निर्धारित की है। ज्यादा से ज्यादा इनकम एक किसान कितनी कर सकता है उसकी भी एक सीमा ग्रापने निर्वारित की है। इसलिये जब उनसे वह जमीन लेने का सवाल आता है तो बदले में उतनी जमीन उनको भिलनी चाहिए। दूसरा सुझाव इसमें यह दिया है कि खद काश्त ग्रगर है तो उसको पैसा दिया जायमा और बाजार की दर से दिया आयगा लेकिन जो लोग खद काश्त नहीं करते हैं उनको उस दर से नहीं दिया जायगा । इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि मालिक खद काश्त नहीं भी करता है लेकिन भ्रगर वहां टेनेंट है तो उसको पैसा देना चाहिये। जैसा मैंने पहले सझाव दिया उस की जमीन ग्रगर ली जाय तो बदले में उसे जमीन ही देनी चाहिए। यह जुमीन कैसे दी जायगी? सीलिंग लगाने के बाद जो सरप्लस जमीन मिलेगी उसमें उसका पहला ग्रधिकार होना चाहिए। वह जमीन टेनेंट्स को देनी चाहिए।

जैसाकि कई वक्ताग्रों ने बतलाया एक दूसरा प्रपोजल यहां पर कोग्रापरेटिव फार्रामग के बारे में है। कोग्रापरेटिव फार्मिग के बारे में प्लानिंग कमिशन ने यहां पर भी कई सुझाव रखे हैं। मेरा कहना यह है कि . ४-१० साल के भ्रनुभव को ध्यान में रखते कोग्रापरेटिव फार्रामंग को हमें एक पयार्थवादी ग्रीर व्यावहारिक दिष्टिकोण से देखना चाहिये । यह ठीक है कि जापान में यह किया गया है कि एकोनामिक होल्डिंग्स जो हैं, थोड़े थोड़े जमीन के जो ट्कड़े हैं, उनकी कोम्रापरेटिव फार्मिग उन्होंने वहां पर की लेकिन हिन्दुस्तान की परिस्थिति वैसी नहीं है। श्रन एकोन।मिक होल्डिंग वह भी एक एकड़, दो एकड़, ४ एकड़ और ४ एकड की वह भ्रलग भ्रलग रहती हैं। एक, एक ग्रौर दो, दो फर्लांग का अन्तर उनमें रहता है इसलिए छोटी जमीनों को भी कोग्रापरेटिव फार्मिग

I 3C45

नहीं हो सकती है। लैंडलैस लेबरर्स को जो जमीनें दी गई हैं उन में भी कोग्रापरेटिव फार्मिंग की गई है लेकिन उनमें भी जिसे कामयाबी कहते हैं, वह कामयाबी नहीं हुई है। इस का एक कारण यह है कि वह जमीन एकत्र नहीं है, ग्रलग ग्रलग टुकड़े पड़े रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि उसकी जो सहलियत और मदद मिलनी चाहिये वह भदद और सहलियत वक्त पर नहीं मिलती है। सही बात यह है कि ग्रगर छोटे छोटे काश्तकार एकत्र हो जायें श्रीर मिल कर कोग्रापरेटिव फार्मिंग करें तो उनको सूभीता हो जाएगा लेकिन जब तक एक जगह ग्रानहीं सकते तब तक उनको पैसा नहीं मिल सकता और जब तक वह मिल कर काम नहीं करते तब तक वह स्विधायें उनको नहीं मिलती हैं। इस बारे में मेरा अनुभव यह है कि कोन्रापरेटिक फार्मिंग प्रैक्टिकल विका में बहुत कम है, बहुत करके कागजों पर ही सीमित है, वह प्रैक्टिकल विकेश में मौजूद नहीं है

दूसरी एक शिकायत इसमें की गई थी। महाराष्ट्र का जो सीलिंग का कानून है, उसमें प्लानिंग कमिशन ने अधिकतम सीमा से छट देने का जो सुझाव रखा था इसमें यह कहा गया था कि ईख के फार्म, जो कि चीनी कारखानों द्वारा चलाये जा रहे हैं, उनको इस ग्रधिकतम सीमा की व्यवस्था से छट दी जानी चाहिए । प्लानिंग कमिशन ने जो यह सिफ़ारिश की थी वह तीन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर की थी। प्रथम तो यह कि धाग जो हैं उन पर यह सीलिंग न लगाई जाय । दूसरी बात यह है कि ऐसे फार्म्स जिन पर दोर्घकालीन आधार पर पंजी लगाई जाती रही हैं उन पर सीलिंग न लगानी चाहिए । तीसरी ब त यह है कि जो उत्पादन घटने की जोखिम लेते हैं जैसे चीनी कारखानों के लिये चलाये जा रहे फार्म्स पर भी यह सीलिंग का कानुन ग्रमल में न लाया जाय · क्योंकि इस तरह से उत्पादन घटने की जोखि**म**

से बचा जा सकेगा। एक बात तो इसमें यह है कि फार्मों की अखंडता बनी है और फार्म की कार्यकशलता का स्तर गिरने न पाए। उसी भांति चीनी कारखानों के फार्मों का जहां तक सम्बन्ध है यह पक्का भरोसा हो जाना कि सम्बन्धित कारखानों स्तर ग्रच्छा रहे. वहां का संतोषजनक रहे ग्रीर कच्चा माल उनको मिले । महाराष्ट्र में जो कानून बनाया है उसमें चीनी कारखानों से जो फाम्सं चलते हैं उन पर सीलिंग का कानन लगाया है। उन को ग्रधिकतम सीमा की शर्तसे छट नहीं मिली एक सिद्धान्त महाराष्ट्र कानून में यह है कि जो भी काश्तकार है, चाहे वह बडा काश्तकार हो या छोटा काश्तकार हो, या कोई चीनी कारखाना चलाने वाला हो, सब के लिए एक कानून होना चाहिए ग्रीर इसी दृष्टि से वहां पर यह सीलिंग लगाई गई है। उस में एक बात निश्चित की गई है कि उन को गन्ना बराबर मिलता रहे। जो टेनेंट्स हैं उन टेनेंट्स को कारखानेदार बरावर गन्ना देते रहते हैं। उस पर यह बंधन रखा गया है कि वह चाहे जमीन के छोटे छोटे ट्कड़े हों जिनमें कि गन्ना बोया जाता है, वह तमाम गन्ना उन फैक्टरीज को दिया जाता है। इस तरह से उनको यह भरोसा दिलाया गया है कि उनको गन्ना बराबर मिलता रहेगा। यह तो ठीक है कि महाराष्ट्र में चीनी कारखातों के ईख फार्मी को ग्रधिकतम सीमा की शर्त से छट नहीं मिली है। एक या दो सटे हुए फार्मों के रूप में फार्मों की अखंडता बनाये रखने की व्यवस्था की गई है ताकि चीनी कारखानों को मुनासिब दाम पर कच्चा माल पुरी माज्ञा में बरावर मिलता रहे । उस में संयुक्त कृषि समितियों का प्राविजन किया है। इसके प्रलावा जो छोटे छोटे काश्तकार हैं वह ग्रलग फार्मिंग सोसाइटी स्थापित करना चाहें तो वह भी वहां सयुक्त कृषि सिन्धि की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसी िक्षा नहीं है। ६० हजार

(Seventeenth

Amendment) Bill

एकड जमीन सीलिंग में ग्राई है लेकिन उसमें से ४० हजार एकड़ जमीन उन्होंने दे दी है। एक दो कारखाने ऐसे है जिन्होंने कि यह आपत्ति उठाई है । इस्लिए मेरा यह सुझाव है कि सीलिंग कानून चीनी कारखानों के फाम्स में लगागा जाय और ऐसा करने में कोई दिक्कत है या ग्रडचन है ऐसा मैं नहीं समझता

उपाध्याम महोदय, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बातों पर ब्राता हूं। बात यह है कि यह जी ममि सुधार का कान्न है उसमें पहले तो कुछ वक्ताओं ने बतलाया कि टेनेंट का जो मामला या वह टेनेंसी एक्ट करके उसे दुरुस्त करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया लेकिन ग्राघ टेनेंट्स का जहां तक सवाल है उनके लिये माज तक कोई ऐसा अच्छा तरीका नहीं हमा। प्रोटैक्शन जिसे कहते हैं वह टेनेंट्स को नहीं मिला। जब कान्त बनाया गया था तो उसमें देख लिया जाता कि इतने टेंनेंट्स हो जायेंगे लेकिन बाद में देखा गया तो बहत से टेनेंटस या उसके ऊपर जो बालते हैं वे इविक्ट हो गये। उसका कारण यह है कि उसमें सरंडर का प्राविजन था। सरंडर जो दिया है बह भानना चाहिए। ग्रब मैं नहीं समझता कि वह काश्तकार जोकि किसी जमीन पर कई साल से भ्रपनी कांग्त करता है, उस जमीन पर ही वह निर्भर है वह खुद कैसे ग्रपनी जमीन को सरंडर कर सकता है ? वह कभी वालिए-टैरेली सरंडर नहीं हो सकती है। लेकिन कानुन में यह ग्रड्चन रहेगी जिसके कि ग्रन्दर काश्तकारों को टेनेंट्स को इविक्ट कर दिया है। टेनेंट्स को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। १० एकड़ से कम वाले जो लोग हैं उन टेनेंट्स के पास ग्राधी से लेकर तीन चौथाई फार्म्स उनके पास है, श्राधी से ज्यादा जमीन पर वे काश्त करते हैं लेकिन. उन की तरक प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट ने कभी देखा नहीं है। जहां तक केडिट का प्रश्न है, उन की कोई केडिटवर्दीनैस नहीं है। उन के पास ग्रपनी खुद की जमीन न होने से 472 (Ai) LSD-6.

उन को कोई भी सह़लियत नहीं मिलती है श्रयीत् न उनको कर्ज मिलता है श्रीर न सुधरे हुए बीज ग्रादि मिलते हैं। इस कारण काश्तकार, टिनाट, बहुत परेशान और तंग हो जाते हैं और ग्रपनी जमीन सरेंडर कर देते हैं।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि छोटे फार्मर्ज से लैंड न लिया जाये।

म्राख्रिर में मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हं कि गुकटमेवाजी को जल्दी से जल्दी बन्द करना थाहिए, क्योंकि कोई टिनांट हाई कोर्ट या सप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है। यह सब बड़े लोगों की वात है।

श्राज श्रावश्यकता इस बात की है कि सरकार को भूमि के बारे में एक सुनिश्चित नीति निर्धारित कर के उस पर ग्रमल करे। ग्राज काश्तकारों के दिलों में एक सन्देह पैदा हो गया है कि जो जमीन कानून से हम को मिली है, जो कि सीलिंग के ग्रन्दर है, वह हमारे पास रहती है या नहीं। विनोबा जी कहते हैं कि सभी भूमि गोपाल की। सरकार ग्रौर प्लानिंग कमीशन कहते हैं कि को-ग्रा**प-**रेटिव फ़ार्मिंग किया जायेगा । ग्रमी एक कानुन ग्राया है, जिस के ग्रनुसार जो जमीन हमारे पास है, ग्रगर कोई कारखाना, सिनेमा या थियेटर बनाना चाहता है, या बंगला बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी उस जमीन का एक्वीजीशन हो सकेगा । इन बातों से काश्तकारों के दिलों में सन्देह ग्रौर मंका पैदा होती है।

सरकार को एक सुनिश्चित निर्धारित करनी चाहिए कि म्राज काश्तकार के पास जो जमीन है, ग्रगर वह उस पर खुद काइत करता है, तो वह जमीन उस के पास रहेगी भौर वह नहीं ली जायेगी।

Shri Bakar Ali Mirza (Warrangal) Mr. Deputy-Speaker, Sir, frequent amendment of the Constitution is not surely desirable. But occasions arise when it becomes absolutely necessary and it is only in the earlier period, after the Constitution was framedespecially the written Constitutionthat the need arises for changes. was the case in the United States also. It is only a new shoe that pinches and you know where it pinches and if you do not make any alterations, then, I think, it will not be a correct thing to do. In particular amendment, the Law Minister has included, as Dr. Singhvi just now said, 126 Acts in the Ninth Schedule and that has been reduced to 44 Acts. It would not have required any great legal ingenuity on the part of the Law Minister to frame a clause which would cover all these without making this cumbersome arrangement. Sir, recently, we find that the Law Minister had to withdraw the Advocates Bill and some of the legislations that we passed have been contested and their validity has been successfully contested in courts. Why is all this? Is it because the eminent lawyers and draftsmen get so much outside that they do not find it tempting and worthwhile to enter the Law Ministers? Ministry excepting as That is perhaps the reason and in a big country like ours, legislation of this standard. I think is something to be deplored. I suggest perhaps it may be useful if he associate a few retired Supreme Court Judges as advisers to our Law Ministry. That might perhaps help in getting over this difficulty.

Shri A. K. Sen: One of the first things done by Mr. Justice Bhagwati, as Vice-Chancellor, has been declared invalid by the Supreme Court.

15.26 hrs.

[SHRI SONAVANE in the Chair]

Shri Bakar Ali Mirza: Maybe. But they are not so many and it is not so often.

Sir, the need for this amendment, as has been stated by previous speakers, is the need for land reforms. The land reforms is not just an idea or a fancy of one political party or the other. It is a well-known economic fact that no country which has got an agricultural base can really be a firstclass power if its agriculture is not modernised to the highest extent. If you see the mediterranean belt, you will find they are last on the scale: then, France and Germany are higher up and England and Scandinavia are still higher up. If the agricultural base is weak, the country is weak. We have seen that the existing agricultural patterns in the country have not helped us. After 17 years, we are no better. We have abolished zamindari system and all that. But we are no better. So, the change is required and the land reforms are essential for the country's progress. You argue that probably the other method of Prof. Ranga of having free enterprise is perhaps the better way. You can argue like that. But supposing if some people who form the Government feel that this is the only way, there should not be any hindrance constitutionally for seeing that is done. Therefore, this amendment is absolutely essential.

Mr. Chairman: The hon. Member should conclude now.

Shri Bakar Ali Mirza: I have just started. I just started when you took the Chair.

The land reforms is not just cutting off the tall poppies and distributing the land amongst the landless people. You have also to raise the low level of holdings. That is also the function of the land reforms. If 50 or 60 per cent of our cultivators have half an acre or one acre of land, no amount of fertiliser, no amount of better seeds, an amount of irrigation, can really make that an economic unit. Unless these peasants have an economic holding, they cannot contribute materially to the progress of the country. So, it is not only to reduce the upper limit

13051

but at the same time to add to these very small holdings so that these become economic holdings. It will be a fundamental mistake if all this land. whatever is available, is distributed amongst the landless labour as just a sort of charity. That will not be the economic way of doing it. Mr. Ranga pleaded for the sacredness of property, that a man has got some property and he must be compensated exactly at the market price. people say, "What about the urban people? You are only dealing with the agricultural holdings and leaving the urban people alone and that you are biased." The property is now no longer sacred in the twentieth century. When you make a lakh of rupees, the Finance Minister comes and says, "you shell out Rs. 75,000 and you pay it. In the reign of Elizabeth it would have been called a banditary, in the reign of Elizabeth II it ts moral and a justifiable act. Take the case of Bank of England. The Bank of England issued notes promising to pay in gold to whoever presents that document to the Bank of England. Then, one fine morning, they announced that they will not be paid in gold. And what was the reason? The reason was because the country had gone off the gold standard. If an individual had done it, it would have been considered as a fraud but on the national scale it is considered to be quite proper. Larceny on a petty scale and by an individual, is considered as a theft, but if it is done on a national scale, it is considered as economics. So, that property is sacred is an outmoded idea. For a social good, for a social objective, it is justified to take property not paying exactly at the market price but less than the market price if you want the country to develop.

As regards ceilings, my hon. friend Dr. L. M. Singhvi has said that the ceiling even for the future is protected. This very amendment seeking to give protection to the small holders is itself a concession. I do not see why it should be there. I feel that it will be quite proper if we remove it

Why should this discrialtogether. mination be there? In the case of a person who is holding land below the ceiling, protection is given, but a person holding land above the ceiling has to get rid of his land without getting proper compensation. I am against this addition that has been made, and I think that that will also answer my hon, friend Dr. L. M. Singhvi's argument.

I am glad that the Hyderabad Tenancy Act etc. has been included in the Schedule. The States have been trying very hard to have land reforms for the last fifteen years, but unfortunately, there is a lot of vested interest in land in our legislatures. and there is a block and there is resistance for all kinds of land reforms. At least one resistance namely constitutional resistance is now being removed, and I welcome that.

Mr. Chairman: Now, Shri Vasudevan Nair.

Shri Sheo Narain (Bansi): Is there a list before you? In the morning. the Hon. Speaker had said that there was no list, and, therefore, we have been sitting in the House from morning till now, waiting to be called. But we are not being called. Instead, only other Members are being called.

Mr. Chairman: Order. order. have called Shri Vasudevan Nair now.

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): It has already been made clear that in principle we are supporting this Bill. Perhaps our only complaint may be that Government were too late in coming forward with such a legislation. But the difficulty is that as in all other things, on this question also, we see the apparent contradictions between the words and deeds of this Government. I should not, therefore, be surprised if Government say one thing but do quite another thing, for after all, Government are influenced by friends like the one that spoke just a little earlier.

[Shri Vasudevan Nair]

I was really shocked and surprised to hear a speech like that from any Member of this Parliament, leaving alone a Member belonging to the Congress Party. I was surprised that in 1964 there were Members of Parhament who were courageous and bold enough to come out and defend the intermediaries, and speak about the good old days when the tenants and cultivators were under the protection of the intermediaries and zamindars. It was shocking or rather I should say that it was really painful to see that there were representatives of people who wanted to go back to the previous centuries. But I should like to tell such friends that they are trying to swim across the current, and they are not going to succeed.

It is not as if some party in this country or some sections of people in this country want to bestow some benefits on peasants and cultivators. The basic question is this. If at all this country wants to move forward step in step with the other contries of the world then we shall have to implement radical land reforms. There is no escape from it.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Which are those other countries?

Shri Vasudevan Nair: Every country has had to pass through this phase. I would like to tell my hon. friend that even in the classically capitalist countries, they had to pass through this particular phase of implementing radical land reforms. There is no escape from it, and there is no getting away from it.

Really, the problem is that we have hesitated, and we have said something but we have acted in quite a different manner. Let us take this particular legislation itself. You may remember that this was introduced in this House over a year ago. It was mentioned in the Statement of Objects and Reasons that this Bill was recessitated by the judgment of Supreme Court against certain provisions of the Kerala Agrarian Relations Act. That was the immediate provocation for Government to come forward with such a Bill. Then tthey thought it wise to make it as comprehensive as possible and to include as many land reform Acts as possible in the Ninth Schedule so that they were not encroached upon or challenged leaving the peasants in lurch.

When we speak of litigation in the courts etc., let us not forget that the poor cultivator in the dark corners of this vast country is not on a par with the zamindars, landlords and others who are materially placed in a much more favourable position to go to court and to spend money over litigation, and to engage advocates to to do whatever is possible. So, it is the bounden duty of this Government and this Parliament to come to the help of such helpless millions of people in this country.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): After the imposition of the ceiling, where are the landlords now?

Shri Vasudevan Nair: I am sorry that my hon, friend is concerned only with ceiling. We are dealing with comprehensive land reform legislation, concerning not only ceiling but also fixation of fair rent, giving right to cultivators to purchase the land and have ownership right, protecting the people who are without homes and who are occupying home-steads and so on which are contained in these various Acts. So, such constitutional amendments are welcome and are necessary, and they have to be stoutly defended by this Parliament. I should say that we are here to defend such legislation, and we want Government to stand firm on such questions and not vacillate and run away from reality.

As I said earlier, even this Bill was introduced a year ago. As I said earlier, the immediate provocation was the Supreme Court judgment against certain provisions of the Kerala Agrarian Relations Act. That Act had to be defended and protected. But then what did this Government do? Of course, they may say that they were not the party and they were not directly concerned. But we know that this Government was approached by the Kerala State Government to proceed with another Bill. My hon. friend Shri P. G. Menon had stated a little while ago that in 1959, the communist Ministry wanted somehow or other, before it went out of office, to pass the Kerala Agrarian Relations Bill and place it on the statute-book. It is true that what Government was very earnest in bringing forward a Bill like that and in getting it passed, because right from 1947 uptil 1959, during the twelve years of popular government afttr freedom, twelve long years, the ruling party, that is the Congress, would not bring forth such a legislation-in spite of their resolutions, declarations and so-called talk of socialism and what not twelve long years it went by default.

Our Government was wedded to it. They had made a promise to the electorate. This was one of the main items in the election manifesto of the party running that Government. We are not used to professing one thing and practising another thing. (Interruption). Yes, we are not used to that. We may be doing some wrong things. That is a different matter. But when once we put our faith in radical revolutionary land reforms, we stand by them and we proceed in that direction.

I should like to remind my hon. friend, Shri Govinda Menon that the so-called liberation struggle was started against that Government among other things with the intention of throwing it out before the Kerala Agrarian Relations bill was passed. It was declared by the leaders of the liberation movement. We want

to throw this Government out before this Bill is passed. We do not want this Bill is passed'. We do not want this Bill'. It was declared by them. In spite of that, the Bill was passed. But now my hon, friend was saying that they passed it in haste, in a hurry and because of that haste and hurry, it could not stand the judicial scrutiny. But I should like to correct his memory a little to tell him that it was his party's government that really gave the final seal to that Bill, because even after the Kerala Legislative Assembly had passed the Bill in 1959, for full one year the President of India sat upon it,-his Secretariat sat upon it. They refused to give assent to it and the Bill was returned for amendments-after year. At that time, the Government was not the communist Government: it was run by the Congress and the PSP a coalition government. I should like to ask Shri Menon whether they also acted in a hurry, whether they did not have legal advice in the matter. Why was it that even after amending the Bill by that Government, it was tested in the courts and the courts came down upon it? So there is no use finding fault with the particular party or government that it acted in haste. It acted in earnestness, it acted in good faith. The bona fides of that Government cannot be questioned.

My hon, friend again said that the new Kerala Agrarian Land Reform Act passed very recently is a very good piece of legislation, that there is practically no difference between the old Act and the new Act. Then why did they go in for the new Actthere is no basic difference between the two? The two Acts are quite different. Actually, in the new Act, every privilege that was conferred upon the tenant cultivator and the kudikidappukars has been betraved. taken away-on the question of fair rent, on the question of ceiling, on the question of giving security to the kudikidappukars, on the question conferring right of ownership, of title on

[Shri Vasudevan Nair]

13057

the tenant cultivator. On all basic and major questions, the new Act has nothing in common with the old one. Under the new Act, large concessions are given to the land-owning classes. Today it looks very strange that the tenant cultivator is given the right in principle and on paper to purchase ownership. But then who is to decide that? It is a very strange piece of legislation. The landlord, if he wills, if he wishes if he agrees- if the landlord agrees then the tenant cultivator can purchase ownership! In the previous Act, if the tenant cultivator thinks that he is in a position to purchase the owenrship right by paying the necessary compensation, he can purchase it. He was the person decide. But now that right is given to the landlord. How strange this Act is? Then a clause is inserted in the Act and under cover of that exemptions from ceilings are there. I tell you practically no land will be left. I read in the papers two years ago that in Maharashtra, the Minister for Revenue and Agriculture stated that by making use of the loopholes in the Maharashtra Act, so people had really escaped and a few million acres of land were really transferred, partitioned, and given over. All these methods were adopted. Here in under the exemptions clause, pepper, arecanut cashew and all sorts of cultivated land are included. It was not in the original Act. What will be left in the new Act?

In the previous Act, the kudikidap-pukars, persons without homesteads—there are millions of them in my state—if they were to be removed from a place, evicted from a place, they were bound to get 10 cents of land. In the new Act, which my hon, friend characterises as the same as the old one, the 10 cents is reduced to 3. I do not have time to go into details; it is not also very relevant in this discussion. But, want to make it very clear that the Central Government, even though it they wanted to protect the Kerala Agrarian Rela-

tions Act when they introduced this Bill, really allowed sabotage of the same by permitting the Kerala Government to go ahead with an entirely different Bill. So even though in principle, we welcome this Bill, at least on behalf of the lakhs of people from my State, I should say that they are thoroughly disappointed by the way this Bill was piloted in this House.

Sarojini Mahishi (Dharwar North): The Constitution (17th amendment) Bill is before the House. I listened to many of the hon. Members who have ventilated their grievances the lack of encouragement available to agriculture. I do appreciate that as trustees of the people's confidence, they have got every right to ventilate grievances of the people. But here we are dealing with amendment of the Constitution. The Law Minister has brought before the House the 17th amendment. Whether the Constitution can be amended so many times. whether it is desirable amend it so frequently—that is a different thing. But as far as the Law Minister is concerned, I hope he won't give this answer that he is not concerned only with the law and not with the other things, that the Food and Agriculture Ministry is concerned with questions, that the Irrigation and Power Ministry is concerned with providing better irrigation facilities in the country etc. It should be an inand consolidated policy of tegrated land reforms. All these land reforms legislation passed in different States should go to give better facilities to agriculturists for producing more food in the country. But, with the help of this particular policy, we are leading towards a particular target. That we have completely forgotten, many of the land reform legislations passed in different States are not being implemented.

Now, we have again come with another amendment, namely the Seventeenth Amendment, before the House. Herein, the particular lacuna that was there in article 31A, as a

result of which property could not be acquired under the definition of "estate" which was available in arti-cle 31A, is being corrected, so to say. If any High Court or the Supreme Court challenges or declares a particular law as void then naturally, the legislature tries to amend the Constitution and make a rovision for the law which was considered and declared as invalid and void by the Supreme Court. Is it a running race between the sovereignty of Parliament and the independence of the idiciary that the moment the judiciary declares any particular thing as void or invalid or ultra vires, the legislature runs to amend the Constitution and correct those things which are considered incorrect? I do not know how long this race can continue and wnether it would be desirable in the interests of pursuing land reforms policy itself in the country, in the interests of giving better service to agriculturists and also in the interests of promoting the cause for which the Government stands.

Article 13 of the Constitution says that any law in force prior to the commencement of the Constitution which was inconsistent with any of the provisions of the Constitution, could be void to the extent of such inconsistency. The second clause of the same article says that the State shall not pass any law as would take away or abridge the rights given by the Constitution, and if such legislation is inconsistent with or contrary to any of the provisions of the Constitution, it would be void to the extent of such inconsistency.

Article 31A was introduced into the Constitution in order to counteract article 13, and article 31 states that irrespective of what is mentioned in article 13, any property can be acquired if it is for a public purpose, but that no person shall be deprived of his property save by authority of law. So many things followed. A person can be deprived of his property provided certain conditions are fulfilled and if it is for a public purpose.

Article 31A(2)(a) is amended here in order to make the definition of "estate" wider, and the Law Minister has given the reasons. But I was rather surprised to find the reason that because eight enactments were declared void and 14 others were challenged in the Supreme Court and the High Courts, this amendment of the Constitution has been necessitated. That is not a good defence at all, not a good ground at all.

By the present amendment, the definition of "estate" is enlarged to include the following also:

- "(ii) any land held under ryotwari settlement;
- (iii) any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans;"

The whole country was agitated because even holders of very small properties, agriculturists and even any other persons having some proprietary rights were afraid that their property might come under this definition of "estate", and they might be deprived of it, without having recourse to any constitutional remedy, also, that irrespective of the fundamental rights mentioned in articles 14, 19 and 31 of the Constitution, they might be deprived of their property.

Under your chairmanship, the Joint Committee has made certain amendments to this clause and this definition. A little amendment is being introduced in clause 1. It reads as follows:

(i) in clause (1) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where any law makes any provision for [Shri Sarojini Mahishi]

the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.":

There are three main things: if the land is within the ceiling limit; if the land is under the personal cultivation of the person-these are two things; adequate compensation, market price should be given to the person in case that is acquired for some public purpose.

There are different processes by which land automatically goes to the tenant in certain cases. According to the Bombay tenancy law, if on 1st April 1957, a tenant is holding a particular land as a tenant and if he is a protected tenant, holding that property as a tenant since prior to 1948, automatically he becomes the owner, so to say, of the property. Automatic lapse is there; that cannot be called acquisition also; that may not be brought under the purview of this particular clause. Here the owner of the property may be deprived of his land if he has got surplus land. But supposing there is a person who has got some land within the ceiling and whose property is being acquired for certain purposes: he should be given proper compensation, that is, market price. There are certain cases also brought out by some friends in the Opposition and in the Congress Benches also. Supposing there are disabled people who are not able to personally cultivate themselves, what about those people? Is any given to those people? According to the Hindu Code, daughters are also getting property . . . (Interruptions.)

Shri Ranga: There are old people. What happens to them?

Dr. Sarojini Mahishi: The tion of personal cultivation? must be widened. What is meant personal cultivation? Should it only mean manual labour by the person in whose name the land stands? If it is the case it is very difficult to have the lands under one's own personal cultivation. India is a country and 80 per cent. of our people live on agriculture. According to 1961 census, the people who own land in the country are very few. There are people who cultivate their own lands, who cultivate the land of others, who have small holdings and cultivate the land of others in addition to their land, who work in the field of others, and there are again landless labourers and other lobourers who do not even get labour in the land. All categories of people are in the country. We should take into consideration all these people. I am not interested in defending the cause of particular person who holds surplus land or who once upon a time was an absentee landlord. All the jagirdars and zamindars have been abolished and that question is there no more. I am not very much dealing with those people who are not willing to work and who live upon others. Anyway there are people who actually want to till their land but for whom it may not be possible to do the work or work for themselves. This particular definition of personal cultivation should be widened . . . (An Hon. Member: Minors and widows are there). That is why I have said that many of my hon, friends from the Opposition and many hon. firends from the Congress have advocated this.

Shri Ranga: It is nobody's monopoly except the Communists'.

Dr. Sarojini Mahishi: When there is restriction upon agricultural holdings and the income of that property and that property can be acquired at any time, what about the other types of property? Does article 31A provide for the other types of property also, say, for instance, industry, etc.?

There should be some restriction put upon that partcular property also so that the distinction between urban property and rural property, between industrial estate and agricultural property, should be reduced to a very low percentage. Unless this is done, you cannot guarantee the socialist pattern of society. After the Bhubaneswar session of the Congress, wherein the Congress advocated this socialism many of the friends in the Opposition intended to join the Congress party saying that there is not much difference between their own policy and the policy of the Congress. Now, I am afraid that another group also may join the Congress saying that there is much difference between the policy advocated by the Congress party and their party (Interruption). I know and that is why I make that remark. There is always an unfortunate coincidence-whether it is the acceptance of the Colombo proposals or it is the acceptance of the Seventeenth amendment to the Constitution-that there is a concurrence of opinion between the Congress and the communists; it has agitated many people in the country also as to what mainly is the essential outlook towards land reform, or the proper implementation of the land reform enactment that should be passed in the country. No doubt, the Law Minister was actuated to bring this particular Bill before the House on account of the fact that after reorganisation, many parts which had got land reform legislation went into another State and the other State properties could not bring certain under this definition of the word "estate" coming within the purview of article 31A

16.60 hrs

Therefore, the necessity arose for bringing in this Bill. But in implementing this legislation, as far as possible, there should be uniform legislation and implementation. There can be a little difference, taking into consideration the irrigation facilities or otherwise available in the country. But there should be an integrated policy on land reforms that has to be followed in the country. This want of co-ordination on the part of the different Ministries is no answer for saying that agricultural production has not been adequate in the country.

Shri M. L. Jadhav (Melegaon): Mr. Chairman, Sir, I support the measure that is before this House. I know that thousands of representations have been made and received on the measure that is now under consideration. I also know that a number of vested interests and people who are landowners have opposed this measures. But it is going to affect only five to 10 per cent of the landholders and not more. I know that the majority of the landholders are small in number and the tiller of the soil is not going to be affected by the measure which is before the House. I know that country does not believe in community farms nor does it believe in zamindari. It believes in the socialistic pattern of society, and this measure is an effort towards socialism. It is for Parliament to enact legislation which may achieve this goal. Courts are there to interpret the law, but it is for the legislature to enact and make changes in the law which may suit the needs of the present-day society.

I know that the tiller of the soil, unless and until he is made the owner, cannot be expected to produce more. Only when he feels that he can derive the maximum possible benefit from his own labour, he may be attempting to produce more. Therefore, there is a need of such a type of legislation that is before the House.

Then, it may be that an individual may suffer in his own interests, but if the individual interest is going to

[Shri M. L. Jadhav]

suffer in the interests of the community, and if fair and equitable compensation is being given to him, then, in that case, the question is whether individual interests should over-ride the community interests or the community interests should over-ride the individual interests. In that case, I feel that a measure like this which is of a socialistic nature is all the more necessary, because individual interest is subject to regulations and claims of the community interest. So, I feel that private property should not be allowed to stay to the detriment of the community interest. In that respect this measure is a progress in that direction.

It is not possible in all cases to pay compensation at market value. Partial compensation is a via media. It is not the policy of this State to acquire property without paying any compensation, as has been done in some other countries. It is our policy to pay compensation. But when we have to effect social changes and to meet the prevailing conditions, it is not possible to pay full compensation. Under these circumstances, I feel that this partial compensation, which may satisfy the big landholders is enough to meet the needs of the present day conditions.

Let me turn my attention to the legislation that we have with regard to the land problems. In my State of Maharashtra, the old Bombay Tenancy Act was there and a number of changes were made therein. Still I find that the number of persons benefited by the Bombay or Maharashtra Tenancy Act is very small. I know that a lot of litigation was there and this litigation together with the inefficient administration of the Bombay or Maharashtra Tenancy Act resulted in only 1 per cent of the cultivators or tenants getting the benefits that could be derived from that Act. When the Act itself is clumsy and it has got many sections which are capable of different interpretations, it is very

difficult for the ordinary and poor tenants to make out a case and preserve the land that he is actually cultivating, the administration of legislations of this type which are social ones is left to the mamlatdars and karkuns or even to the patwaris. The administration of such legislation should be clean and capable of giving fair justice to the tiller of the soil. It should be free from corruption. So, I appeal that whatever social legislation that we are going to have should be put in the hands of clean administration, so that the actual tiller of the soil for whom it is meant may get the actual benefit from the measure. The measure should be a simple one, so that the villager may understand the same and utilise it for his own benefit. I know cases where even the village patwaris and karkuns played mischief and valuable rights and interests in the property have been either newly created in favour of wrong persons or those rights have been tried to be taken away by wrong entries. Such type of things are not going to help the nation. So, I feel that legislation of this type should be simple and effective check should be there to stop the mischief.

If you want to have more production, it is very necessary that the cultivators are given certain incentives. I know that the State produces the major fertilisers in its own factories. But what do you find? Fertilisers are being sold to the cultivators at double the price. The profit that the State makes is nearly two hundred times the cost of production. When we import large quantities of foodgrains worth crores of rupees, from the United States of America and other countries, the cultivator who produces for us should be given fertilisers at the proper rate. He should be supplied good seed at the proper rate. More energy should be devoted towards the production of tractors. If he is given fertilisers, seeds and implements at proper rates, and if along with this

he is also given proper credit at the proper juncture, I am sure we can hope to have more production by enacting a law like the one that is before the House. Simply by enacting a law we cannot have more production. We cannot have socialism unless and until we give the cultivators, the tillers of the soil, more incentives to have more production, and then alone we can succeed in achieving our object.

With these words Sir, I support the measure that is before the House.

भी जिब नारायण : सभापति महोदय. स कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम सोशलिस्ट स्टैट बनायें , सोशसिलज्म की पालिसी इस गवर्नमेंट की है। हम नै कई स्टेटस में लैंड रिफाम कानन बनाये श्रीर उन पर श्राब्जेक्शन भी हए हाई कोर्टों में ग्रौर मुप्रीम कोर्ट में । इसी लिये गवनेंमेट ने यह ग्रमें डमेंट ला कर कोशिश की है कि हम एक सही कानन दें भ्रौर पब्लिक को प्रोटेवशन दें। कम्पेन्सेशन की जो बात सरकार ने कही है वह ठीक है। लेकिन ठीक समय से कम्पेन्से-शन मिलना चाहिये श्रीर किस जमीन को लेना चाहिये, यह भी सोचना चाहिये, यह द्याज गांवों में बड़ी ग्रम्बिलिंग हैं। मैं गांवों से लौट कर ग्राया हूं ग्रौर जानता हूं कि शहरों भीर गांवों में क्या डिफरेंस हैं। प्राज गांव का श्रादमी समझता है कि सारा इन्तजाम, सारी व्यवस्था शहर वालों के लिये है, सारी भासाइश उन के लिये है। उन की फैक्ट्रीज बन रही हैं, मिल मालिकों की संख्या बढ रही है भौर गरीब किसान पिसा जा रहा है जिस के ऊपर सब कुछ निभर करता है। मैं गवर्न-मेंट से पूछना चाहताहं कि पांच एकड़ से ऊपर जितनी जमीन लोगों के पास है उस से कितना लगान सरकार को मिल रहा है। कैपिटलिस्तों को करोड़ों रुतये दिये गये हैं। करीब २०० करोड़ रुपये उन लोगों के ऊपर बचता है जिस का टैक्स बाकी है। उसे सर-कार वसूल नहीं करती है। यह सरकार किस की है। किसानों की, गरीबों की, किसानों ने सरकार को बोट दिया था जिस से प्राप

ने बहत से बादे किये थे। लेकिन "कहता बहुता मिला, गहता मिला न कोय"। भ्रगर माप ने प्रपनी बातों पर ग्रमल नहीं किया तो मैं साफ बतलाता हं, क्यों कि मैं गांवों से लौट रहा हं, कि इस समय का समाज ग्रौर देश का वायमंडल बहती बिगडा हम्रा है. वह टेढ़ी चाल जा रहा है। ग्राज देश की परि-स्थिति बहुत गभीर है। कम से है कम ८० प्रतिशत लोग, जो गावों में रहते हैं, किसान वे ग्राज नंगे हैं, भुखे हैं। ग्राज बाजार भर में फ़ोंच रेवोल्युशन की सी स्थिति नजर ग्रा रही है। धाज १२ छटाक की भ्ररहर की दाल नहीं मिल रही है, किसानों, के यहां लोग भखों मर रहे हैं। ग्राज ग्राप मछली, गोश्त ग्रंडा दूध की बात छोड दीजिये. साधारण दाल उन लोगों को नहीं मिल रही है, बाजार में ग्राज किसानों की हालत यह है। मैं ग्रपने गांव की एग्जाम्पल ग्राप को बनलाता हं। वहां एक लेंड लार्ड हैं जिस के पास डेट सौ बीघे की जीदारी है, लेकिन दो वक्त खाने को नहीं मलता । दो वक्त खाना नहीं बनता, दो वक्त सब्जी नहीं बनती । यह है भल्क की तरककी ग्रीर मुल्क की उन्नति ।

हा**ं मा**ं भी भणे : कौन सा गांव है।

भी शिव नारायण : है एक गांव हमारे यहां। यह नक्शा है। भ्राज गांव के किसान का बेटा यनिवर्सिटी नहीं जा सकता। मेरा बेटा युनिवर्सिटी नहीं जा सकता। कारण यह है कि मैं किसान हुं। खेती में इतनी पैदावार नहीं होती है कि हम खा लें ग्रीर पैसा बचा कर बच्चे को हास्पिटल भेजें या स्कल भेजें ग्रीर ग्रन्छी ट्रेनिंग दें, ग्रन्छी शिक्षा दें। मेरा बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता जिस के यहां २५ बीघे की खेती है। श्राज क्लास वार चल रही है इस मल्क में। मैं पालियामेंट में ग्रोपनली कहना चाहता है कि ग्रगर इस पालियामेंट ने मुल्क को ठीक नहीं किया तो भ्राप स्ट्रीट में ठीक हो जायेंगे। बड़ी भयंकर स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है। बाज गरीबी का हाहाकार मचा हमा

[श्री शिव नारायण]

13069

है। आज ो क्लास लड़ रहे हैं। ग्राज लड़ाई बाहम्ण और चमार की नहीं है। श्राज लडाई किस की है। जिन के घरों में पैसा है, जो कैंपिटलिस्टों भ्रौर श्राफिशिल क्लास के लोग हैं जिन पर सरकारी बजट का दो तिहाई पैसा खर्च होता है, जिन के बच्चे इंगलिश स्कूलों में जाते हैं, उन की और हमारी लड़ाई है जिन के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं स्रोर जिन के लिये कोई ठिकाना नहीं है। मैं पूछना चाहता हं कि ग्राखिर यह सरकार क्या कर रही है। बड़े खतरे की घंटी आप के सामने **ह** 1

मैं श्राप से बड़ा विनम्म निवेदन करना चाहता हं कि जो कांस्टिट्युशन श्राप ला दें, जो ला ग्राप बनायें, उस को ग्राप पर्फेक्ट बनायें। भ्राप कंस्टिक्टिव ला बना दें स्रौर मल्क भर में उस को एक साथ लागु करें। यह नहीं होना चाहिये कि केरल में कुछ हो। बंगाल में कुछ हो, उत्तर प्रदेश में कुछ हो श्रीर दूसरी जगह कुछ हो। श्राप डिटरमिनेशन से ला बना दें कि पांच एकड़ से नीचे वालों की जमीतों को ग्राप टच नहीं करेंगे। ग्राप ने चालिस वर्ष का ऐश्योरेंस दिया है। उत्तर प्रदेश असेम्बली ने लैंड रिफार्म कानन बनाया है। मैं उस समय श्रसेम्बली का मेम्बर ।। बहां पर सन् १६५२ में गवर्नमेंट ने जमी-दारी ऐबाशिलन किया ग्रीर चालिस वर्ष का रेश्योरेन्स दिया, लेकिन श्राप को फिरबदल दिया। श्राखिर श्रापकोंई पक्की स्कीम भी देंगे जनता को या देश को जिस से कि देश के ग्रन्दर ग्राप के ऊपर हो,। जिस दिन जनता का विश्वास भ्राप से के ऊपर से हट जायेगा श्राप का कल्याण नहीं है। मैं **फ्रैं**∓ली बतलाना चाहता हं कि झांसी की रानी कहती थी कि जनता जागृत रहती है । जनता कभी मरती नहीं है। यह जरकार, यह मिनिस्टर बड़ें बड़े किंग फेल हो सकते हैं, लेकिन जनता नाग्रत रहती है, वह फोल नहीं हो सकती।

वह ऐट ऐ नी मुवमेंट खत्म कर सकती है भाप को यह भाप के लिये भ्रल्टिमेटम है। इस लिये प्राप को बहुत फर्म हो कर इस चीज को बनाना चाहिये । यहां पर न किसी कम्यनिस्ट की बात है न जन संघ की बात है अगर कोई भी हुकूमत भ्रच्छी है तो उस के भ्रन्दर न्याय, सत्य ग्रीर त्याग चाहिये। तब राज्य चलेगा। जनता जनार्दन ही देश की मालिक है. उस की विल का पालन श्राप नहीं करेंगे तो सरकार का कल्याण नहीं हो सकता।

(Seventeenth

Amendment) Bill

मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो भ्रमेंडमेंट भ्राप लाये हैं उस से भ्राप को किसानों को प्रोटैक्शन देना चाहिये । श्राज गांवों के भ्रन्दर यह फीलिंग है कि जो कुछ हो रहा है वह शहर के लोगों के लिये हो रहा है। मैं ने घुम कर देखा है। मैं कांग्रेस सेशन में गया था। वहां पर मैं ने उड़ीसा श्रौर बिहार का जो चित्र देखा उस से मेरी ग्रांखों में ग्रांसू भर आये । आज पूर्वी हिन्दुस्तान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी क्यों है। वहां पर बड़े बड़े लैंड लाइंसे हैं । जिन्हों ने ग्रपनी बड़ी बड़ी जमीनों को भाई, भतीजों, भांजों में बांट दिया है। वह जमीन गरीब किसान को नहीं मिली है। विनोबा भावें को भी जो जमीन मिली है, ला मिनिस्टर साहब कान खोल कर सुन लें, वह भी अच्छी जमीन नहीं मिली है. बैजर खौर रही जमीन मिली है। और वह भी हरिजनों को नहीं मिली। वह उन्हीं जमीदारों के भाइयों भौर भतीओं को मिली। गांव के सभापति जिसको चाहें उसे दे दें । यह नक्शा

मैं भ्राप से कहना चाहता हूं कि भ्राप की जो सरकारी मशीनरी है वह बिल्कूल राटेन है। उस को चेन्ज करना ग्रावण्यक है। जैसे श्रम-रीका में होता है कि जो गवर्नमेंट ब्राती है उस के आफिशियल भी आते हैं। अगर आप वैता नहीं करेंगे तो श्राप खतरे से खाली नहीं हैं। मैं देन की परिस्थिति देख कर श्राया हुं। बड़ी गमनीर परिस्विति है। श्राप एक

डंडे से सब को हांकिये. सब के लिये एक बिल रिखये । जो इंडा गरीब पर पड़े वह भ्रमीर पर पडे। भ्रगर भ्राप एक स्टैन्डड कानन बनायेंगे तो पब्लिक ग्राप के साथ बोग्रापरेट करेगी।

"सुखे दु:खे समवेता"

यह सिद्धान्त है। भ्रगर श्राप चाहते हैं कि ग्राप मिल जल कर इस देश को पनपार्ये, अगर आप चाहते हैं कि डिमा के सी को पनपायें तो ब्राप को इन्साफ की तराज को बहत ऊंचा रखना होगा। किसी ने कहा है:

"खब इंसाफ है तेरे ध्रनज्यमने नाज में, शीशा सकता है मंह चमने को पैमाने का।"

इन्साफ की तराजु बड़ी कठिन चीज है। बडे बडे बादशाहों भीर राजाओं के नाम इतिहास में मौजूद हैं। इस गवर्नमेंट को उन पन्नों को उलट कर देखना चाहिये। बो पी के पलट कर देखता है वह कभी फेल नहीं होता । बड़े बड़े ऐडिमिनिस्टेटर इस मल्क में रहे हैं। लैंड रिफाम के सिलसिले में टोडरमल का हिसाब हमारे सामने है. ग्रकबर ने जो इन्तजाम किया उस को ग्राप देखें. जो जहांगीर ने किया, जो शाहजहां के जमाने में हुन्ना उस को म्राप देखें, जो हिन्दू राज में हुन्ना, शिवाजी के राज में हुन्ना, उस को न्नाप देखें। उस नक्शे पर ग्रमल करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिये। ग्रगर जनता जनार्दन नाराज हो गई तो हमारा और श्राप का कल्याण होने वाला नहीं है। ध्राज देश के भन्दर परिस्थिति टेड़ी है। गरीबी का हाहाकार मचा हुआ है। स्नाज देश में फ्रेंच रिवोल्यशन का नक्या बनता जा रहा है। ग्राप खतरे से खाली नहीं हैं। हम खाली नहीं हैं। मभी ग्राप बचे हुए हैं। मैं भोपेनली कहना चाहता हूं कि श्राप को सही इंग से काम करना चाहिये ताकि जनता ग्राप के साथ रहे। कांग्रेस से काम किया है इस देश के मन्दर यह छिपी बांत नहीं है।

श्राज भी जनता कहती है कि हम करें तो क्या करें। जो ग्रपोजीशन वाले **बैठे** हैं वे भी कमजोर हैं, े भी केवल गाल वजाते हैं. खाली हम को गालियां देते हैं। पवलिक क्या कहती है, ब्राप सून लें। पवलिक कहती हैं कि कांग्रेस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन श्रीरों से बहुत अच्छे हैं। मैं इतना ही कह कर छोड़ता हं भीर श्रागे चलता हं।

मैं इस संशोधन का समर्थन करता है। लेकिन सरकार से ग्रदव के साथ कहना चाहता हं कि ग्राप जो भी कानन बनाएं उस पर ग्राप श्रीर श्राप के श्रफसरीन सही सही तरीके है भ्रमल करें। ताकि किसान को लाभ पहुंचे। श्राप गरीबों का प्रोटैक्शन करेंगे तो गरीब ग्राप का प्रोटैक्शन करेंगे । इन चन्द शब्दों के सा**ध** मैं इस का समर्थन करता हूं।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Land reforms demand reorientation and re-thinking. I would start my remarks with the statement made by Shri Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly, while moving for the consideration of the finally amended draft, Shri Jawaharlal Nehru felt that it would balance seemingly conflicting considerations of individual's right to property and the community's terest in the property. He made three broad, salient propositions which were implied in the article, namely (i) that there would be no expropriation without compensation, and (ii) that a distinction had to be made between petty acquisitions and large schemes of social reform and social engineering, and (iii) that the balancing authority ultimately could only be the legislature which had to keep before it all the relevant factors.

When the hon. Law Minister comes forward with a definite which has been considered Joint Committee under your manship, Sir, it poses before the country very important questions affecting the ent.ire social economic fabric. What does the picture portray when

13073

view the panorama of the development of India, a country with a population of 450 millions and with heavy pressure on land to the extent of 72 per cent of people living on agriculture? In this revolutionary process, the factors which come to the have to be analysed, and we have to find out a positive programme of action that can get all the forces into workable state and thereby the integrated process of development can place.

Undoubtedly, the question of pressure on the land comes to the fore. We recall that the Planning Commission in their earlier report had given an indication that there would be a stage when, after a particular period of development in the country, pressure on the land would be because of the employment opportunities which would be forthcoming as a result of industrial development. But what does the picture portray before If this growing population the equally intense pressure on the land go on, there is no chance whatsoever of shifting even a sizable percentage of the population to sectors outside agriculture. Naturally, agriculture becomes the shock-absorber. and it becomes the sheet-anchor, and the main pressure has to be borne by it at any time of development of the country. Questions relating to rural sector have been posed by some Members on this side and on the other side of the House, because we find ourselves in a difficult situation, confronted with those practical problems which are the concomitant results and necessary accompaniments of changes occuring in a country in the process of development.

So in the developing economy which is based absolutely on agriculture-cum industry, the main question that comes before a man in his everyday life is the question of his earnings, of his income, of the yield of the land which will give him a chance of educating his children, of finding certain sources of employment, gainful employment,

whether as a self-employed person or in industrial development or in some occupation. When the comparative factors are placed before us, it is indeed a sad picture of deprivation, of destitution. We find that the income level of the majority is abnormally low. The landless labour, the weaker section of the community, in distress throw the figures before and tell us: 'Here we stand bearing all the pressure. Where do These destitute millions of our country and the backward or weaker section, the scheduled castes, scheduled tribes and other equally economically undeveloped people, come forth with this vital question. Are we tackling this bigger question when we bring in such amendment to the Constitution?

(Seventeenth

Amendment) Bill

So today if the Law Minister brought forward this amendment. which has been so much carefully gone through and examined by many Members under your chairmanship, we must realise first of all how we are going to solve the bigger question, the question of giving the entire community a sense of participation in the development process, where everyone can say, 'Yes, here do I stand and I am in a position to say that nobody can deprive me of my legitimate rights and the fruits of my labour'. agriculturist finds himself handicapped to this extent that all the pressure is now sought to be placed on Naturally, the question urban vs. rural also comes to the front. Some Members very carefully cogently also put forth the argument, why this ceiling is being imposed only on the agricultural sector, leaving the urban sector untouched.

In 1956, I had the chance to go to a great country, China, which has the largest population in the world and is trying to grapple with its problems inits own way. I asked this very question of the professors of economics there, Have you ever thought of this problem-the heavy pressure on your land which is very scanty'?

land reforms had started before went there. They had divided the land was given 3 mous per capitasix mous make an acre. That means, each person had been given roughly half an acre of land. Of course, the question of compensation does come in China. But how far those small plots of land could help them to achieve a self-supporting economy and at the same time leave scope for development? That was the question I put to them. They said We are now grappling with the question by introco-operatives'. ducing agricultural They have got different names for that. These were called primary cooperatives. Later on they went in for communes where all the lands are collected together and people have their joint cultivation and sharing of yields. They call it by different names as it is called kolkhoz in Russia.

The difficulty cropped up in India in connection with co-operative farming, specially when the Congress accepted in Nagpur a resolution in 1959 in that regard. We definitely posed this question before the country: here are the practical difficulties in carrying the country forward to a higher level of living. The agricultural sector cannot be left to its own fate. There is the question of distribution of land. Within the determined ceilings, when the family divides, the children come forward as shares. They are all cosharers; as a result, the question of uneconomic holdings disturbs OHE minds. So, let us think of any other system wherein you retain your ownership, nobody disturbs it, but you better collect yourselves together. This is the positive concept of joint farming, which never allows anybody to expropriated. We were assured that the landless man also would have a place here. If all the lands are joined together, the people skilled and unskilled will have their physical and intellectual labour, their implements and assets added together, so that it would bring forward added agricultural yield, and in that process the country will achieve progress. Agri-

culture would be wedded to industry, the small scale and medium industry also. This was an attempt to present a picture of a society where everybody has a role to play, whether he is landless or landed.

Naturally, this question was a fundamental, basic question, that could convert this economy into a better form of economy provided the people were acquainted with the problems as well as their solutions.

Unfortunately, Prof. Ranga, happened to be the Secretary of the Congress Party, came forward immediately with the complaint, "here is an attempt to introduce the communes as in China or Russia", and naturally the farmers-they are of different types and different grades-were excited to the extent of refusing to have thing to do with joint co-operative It was declared by farming. Prime Minister and other leaders that there was no idea of compelling people to come together against their will. If they came in, they had every right also to withdraw whenever they wanted, provided they fulfilled certain conditions. If they joined, it would increase the yield, production, and thereby the country's income would be increased, and they would be also participants in the proceeds of the income.

That was the definite idea. So, if joint co-operative farming has not been successful, or we could not carry the people with us, it is up to us again to think whether we can allow the present economy to bear this burden. Whatever ceiling we impose does not bring about a solution. It is only an attempt by the Law Minister to bypass those intricacies of the law which have been made manifest because of the proceedings in the law courts. These proceedings went on for years and years together, and the purpose of land reforms was reduced to nullity.

So, today if we analyse these factors and go deep down into the social [Shri P. R. Chakraverti]

13077

and economic problems, we can find a solution. The Joint Committee. under your chairmanship, went into the Acts mentioned in the Schedule, and decided that some of them could be left out because sufficient sense of security had been generated that some of them had not been challenged in the courts, nor were they likely to be challenged. But one does not know. Again, some intelligent or lawyer might advise them, and they might go to the court. It creates complications. To find a way out of this complicated process, this constitutional amendment is an urgent necessity, an inescapable must. We cannot be carried away by the slogan that it is a transgression of the fundamental rights. You have to adjust yourself to the changes, the forces growing apace, and in that process, the Law Minister had to bring this amendment. The amendment is only one factor that can deal with the fundamental issues before the country, and we have to consider them. In that context shall be able to understand the full significance of this amendment and so I endorse the amendment which has been now placed before the House.

Shri Basappa (Tiptur): On the problem of land reforms, the main question that has been asked is whether the objects with which these reforms were brought in this country been fulfilled. The object of land reforms was to bring about more production, and also to bring about social justice and economic stability. Judged by these standards, I must say that land reforms have contributed very little in this respect. land reforms performed in a piecemeal way with very ineffective implementation, instead of proving benefincial have harmed the country. What were the difficulties in the way of implementing these land reforms? What exactly should be these reforms will have to be gone into in a thorough manner.

We are talking of social justice. What kind of social justice we have in this country now? There student. He is a peon's son; he gets 62 per cent marks but he does not get a scholarship whereas another boy, a superintendent's son getting a salary, gets 64 per cent and gets a scholarship. Is this socialism? Socialism for whom? The Government of India send circulars to the State Governments that family pension should be given to big officers' family. What about the peon's family? No such family pensions are given to them. We do not want this kind of socialism. Socialism must see that the strata of society is uplifted. It is very difficult to bring social reforms into There are administrative and effect. legal difficulties. The Supreme Court strikes down these laws and therefore this Bill has been brought in. are administrative difficulties also Land records are not brought uptodate and so it is very difficult to implement these land reforms. Urgent steps will have to be taken.

While examining the mid-term appraisal the Chief Ministers various States and the NDC came to the conclusion that land legislation had not been implemented fully and unless they were speedily implemented the vital objectives of more production and economic stability could not be brought about. They are now setting up committees after committees with the Home Minister and the Chief Ministers as Members. The Pianning Commission is setting up another committee of its own with probably Jayaprakash Narain others. We set up committees rather than implement them. They have not realised the full implications of these land reforms; the attitude of the State Government or the Planning Commission or the Central Ministers should change; they must resist all pulls which are against bringing of these reforms into effect.

Besides land reforms, there 270 other big problems connected land. To what extent have we achieved results in the consolidation

holdings? Small petty acreage is not proving beneficial. The number landless class is very big. It has not are still been tackled at all. We grouping in the dark whether social interest should prevail or individual interest should prevail. A final solution must be evolved and given effect Whether the land belongs to the zamaindari. whenever rvotwari or there is surplus land, it has to be seized. It has to be distributed in a proper way. To that extent I agree with the Bill and I give my support to it. So far as the market value to be given for the personally-cultivated land is concerned, it is quite all right. But in regard to lands which are within the ceiling limit, greater care shou'd be taken to see that those peop e are not dispossessed because you will be upsetting the whole system here, since, in every town and every village, there are people whose economic background will be upset if this is given effect to. So, greater care should be taken to see that those who are dispossessed of their land get certain compensation which will be a very reasonable one.

This is particularly true when we think of all that has been stated just now on the floor of the House about urban income: why should a who has the agricultural income as the only source of income suffer so much when the man in the area with urban income can go on accumulating his wealth to any extent? This is one thing which is rending, and I think people in this country will not tolerate or put up with this kind of thing which is discriminatory. If we are bent upon having a sort of democratic socialism, let it be a proper one which is applicable to all the people.

So far as the exemptions to land ceilings are concerned, They are a necessary evil. The big tea plantations or coffee plantations have to be exempted in the name of greater production. But if this thing goes on for a long time, I think we will not

be able to establish any socialism in this country at all. So, it can be tolerated only for some time to come. Shri Ranga may not agree with me here, but he seems to entertain unnecessary fears on so many matters, not one or two, but many. Let him not entertain so much fear about absentee landlordism. I do not know why he is so much afraid about this big absentee landlordism.

Shri Ranga (Chittoor): Who said so?

Shri Basappa: At least I understood him like that. After all, there are people who have got plenty of land: thousands of acres of land, and they live in cities like Bombay etc. (Interruption). That is what I understand. I do not know. Now, I understand him correctly. He is not for absentee landlordism

Shri Ranga: That is exactly the point.

Shri Basappa: It is quite correct. But anyhow, we should not attribute any motive to anybody. After all, the main idea of land reform is to have agrarian reform brought about in this country so that the well-being of the peasant for which Shri Ranga is fighting so hard is realised. With these few words, I wish that the Bill should go through, and that greater land reforms are brought up, not in a piecemeal way but in an effective, comprehensive manner and that they should be implemented to the greater benefit of the country as a whole.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you heartily for giving me this opportunity to speak on this Bill. Since the time at my disposal is very short, I shall only touch upon two or three points and finish my speech.

I appreciate the circumstances that led to the introduction of this Constitution (Seventeenth Amendment) Bill. The Supreme Court, as we

[Shri Muthiah]

know, struck down the Kerala Agrarian Relations Act in its application to the ryotwari lands. It struck down the Act on many valid grounds such as arbitrariness and discrimination in regard to many of the provisions in the Kerala Act and these discriminatory and arbitrary provisions are also found in several other Acts passed by the various State Governments. Naturally, the Government feared that the other land reform measures passd by the other State Governments also might be struck down by the Supreme Court and they wanted to give protection to the various State land reform Acts passed by the various State Governments. Hence arose the necessity for introducing this Bill.

I want to say a few words about the Madras ceiling Act. I want to say that there is some sort of misconception about ryotwari land-owners. The ryotwari land-owners stand on a different footing from zamindars or jagirdars or inamdars. They are not rent-collectors or intermediaries like the zamindars. They have full proprietary right over their lands. They have every right to acquire or to sell and this is proved by the patta that is granted by Government to every individual land-owner. Patta means Government accepting full ownership and occupation of the land concerned by the individual. So, ryotwari landowners stand on a different footing from zamindars and their case should be viewed in a different manner.

Ceilings have been imposed on agricultural holdings and various ceiling Acts have been passed by the various State Governments. Ceiling on land is in keeping with the policy of our Government and of the Congress Party. We all know that the Congress Party is wedded to democratic socialism. Only recently in January 1964 at Bhuvaneshwar the Congress Party passed unanimously a resolution on democratic socialism.

Ceiling on landed property is in keeping with the spirit of that resolution. But ceiling on agricultural property alone is not quite fair inasmuch as ceiling on non-agricultural property is not introduced. In that case the Government cannot claim that they are ushering in a really democratic socialist society. So, inasmuch as ceiling is imposed on agricultural property, similar ceiling should necessarily be imposed on all kinds of nonagricultural property, particularly the huge house properties in urban areas, the huge industrial or commercial properties in the possession enjoyment of big industrialists and big businessmen and big planta-That owners. would absolutely fair. If we are to be fair to the agriculturists, we must introduce ceitings on urban incomes also, as we have done in the case of agricultural income.

I find that whereas ceiling on foodcrop lands has been introduced various categories of agricultural land like tea, rubber and coffee plantations and huge gradens and huge sugarcane farms are exempted. Ceiling is imposed only on agricultural land that produces foodgrains which are more and more necessary for our growing population. This looks discriminatory.

Inasmuch as various State Governments have passed ceiling Acts and inasmuch as the Central Government is bringing this amendment in order to give protection to the various ceiling Acts, I do plead that full and adequate compensation should be paid for the lands that are being acquired by Government. If full compensation is not possible, then the compensation should be as near as possible to the market value. I plead that at least 80 per cent of the market value should be paid as compensation for the surplus lands that are being acquired by the Government under the ceiling Acts. Even under the Kerala Agrarian Relations Act passed by the communist government in Kerala, the

compensation laid down was 60 per cent, of the actual value to surplus bands up to an annual income of ks. 15.000 Therefore, our Congress Government should see that fair, full and adequate compensation is paid for surplus lands up to an annual income of Rs. 15,000 as was stipulated in the original Kerala Agrarian Relations Act. The Land Acquisition Act passed by the Central Government gives full compensation plus 15 per cent solatium for lands acquired by the Government. But these benefits are denied to the ryotwari land owners under the various ceiling Acts. This should looked into. Even though this amending Bill is going to be passed the Government should sympathetically view the cases of affected ryotwari and owners.

In this connection, I want to say that Dr. Munshi and Alladi Krishnaswami Iyer pleaded most strongly in the Constituent Assembly for giving full compensation for any land to be taken over by the Government. Dr. Ambedkar, when he moved the first amendment in 1951 with regard to zamindari estates gave an assurance to the House that in future all lands other than zamindari estates would be taken over after payment of full and adequate compensation. This should be borne in mind by the Government while giving compensation for surplus lands when they are taken over.

Coming to the Madras Ceiling Act, I fiind that the compensation given under the Act is 9 to 12 times the net annual income minus land revenue. This comes to less than 50 per cent of the market value. I plead once again to you. Sir, and through you to the House, that at least 80 per cent of the market value should be given in fairness to the ryotwari land owners who have full rights over their properties.

Another thing that I find is, there is no uniformity in the various Ceiling Acts passed by different State Governments. The ceiling limits and the provisions of compensation vary

from State to State. Orissa and Madhya Pradesh Ceiling Acts allow the land owners to sell all the surplus lands within a specified time to specihed categories of persons. It these two Acis, the Orissa Ceiling Act and the Madhya Pradesh Ceiling allow the land owners to sell the land to certain people within a certain time, I feet that the Madras Government should also allow the land owners, the pattadars, to sell surplus lands within one year and if they tail to do it, the Government is at liperty take over the surplus lands and give compensation.

Coming to stridhan lands, under the Madras Ceiling Act a married woman is allowed only 10 standard acres out of her stridhan property however much it may be, while an unmarried male adult is allowed 30 standard acres. This is clearly a discrimination against women on the ground of sex. It is clearly a violation of Article 14. A married woman should have stridhan land up to 30 acres which is allowed to an unmarried male adult.

Now, I would just point out a few arbitrary and discriminatory features in the Madras Ceiling Act which were pointed out by the Supreme Court in their judgment as recently as March, 1964. The first one they have pointed out is the adoption of the concept of 'ramily' for purpose of ceiling not the individual. The family should not be taken as the unit for purposes of ceiling. The individual should be taken as the unit. In democracy, it is the individual that should be taken as the basis for fixation of ceiling and not the family. Therefore, this arbitrary and discriminatory. The second one they have pointed out is the definition of the word "family" as consisting of a husband, his wife and three minor children. This also is clearly arbitrary and discriminatory. Thirdly, there is the exemption given to huge plantations getting lakhs of rupees as income. There are plantations of rubber. tea, coffee etc., and huge gardens earning lakhs of rupees. They have [Shri Muthiah]

exempted. Huge sugarcane farms have also been exempted. All these exemptions allow the owners of these properties to earn lakhs of rupees, whereas the middle-income ryotwari pattadars are not exempted. Of course, in the name of social reform, in the name of democratic socialism, in the name of reduction of concentration of wealth, ceiling has to be imposed. But when these exemptions are made, my plea is that at least adequate compensation should be paid in all fairness and justice to all ryotwari patadars who are affected by the ceiling Acts.

Lastly, I appreciate the new amendment that has been adopted by the Joint Committee, namely, the amendment which allows full compensation for lands within the ceiling limit and which are under personal cultivation.

Shri A. K. Sen: Mr. Deputy-Speaker, Sir, as I expected, the Bill naturally evinced considerable interest both in the House and outside, would have been surprised if it had'nt because it concerns vital problems on which our entire agricultural economy depends and on which the welfare of our agricultural population to a very large extent depends, Prof. Ranga has done us a service in reminding us that long before we had started thinking in terms of land reforms, he had been moving in the same direction and that his grievance possibly is that others had not moved as much he did in those days and others are showing greater enthusiasm only now. Well, instead of trying to find out who was more energetic than others in the matter of land reforms, I think, it would be better, if I may say so with respect to Prof. Ranga, if he could now concentrate on the essentials and find out what possibly would be to the best interests of each State because conditions differ from State to State and, therefore naturally ceilings will have to be different from State to State having regard to the population of each State, the amount of land available and various other factors and also having regard to particular types of tenures which may be existing in respective States.

(Seventeenth

Amendment) Bill

Sir, what we are trying to do here is not to discharge the functions the State Lgislatures. In fact, most State Legislatures have passed land reform laws and, if I may say so, with almost unanimous consent. The purpose for which the present Bill has been introduced is quite different and, if I may say so with respect to many hon. Members who have tried to underline deficiencies in the matter of land reform, vices which have appeared in the course of working out different schemes of land reforms, deficiencies in laws. deficiencies workings 5ng ous other matters, these are completely outside the scope of this Bill. They are matters which have to be considered in the State Legislatures, Parliament is not concerned with legislation on land which is exclusively a State subject. All that we are concerned limitations here is to remove those from which, as a result of some recent decisions of the Supreme Court, our State laws appear to be suffering. Our State Legislatures appear to be suffering from certain incompetencies in the matter of legislation on land reforms, particularly touching on certain tenures and also in imposing ceilings in the States as a result of certain decisions which have been recently passed in the Supreme Court and also in several other High Courts. What the shape of laws would be

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

17.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday April 28, 1964/Vaisakha 8, 1886 (Saka).